



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2628]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941

No. 2628]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2887(अ).—जबकि भारत द्वारा आधार संकुचन और लाभ अंतरण को रोकने के लिए कर संधि संबंधी उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय अभिसमय (इसके बाद इसे "उक्त अभिसमय" कहा गया है) पर 07 जून, 2017 को पेरिस, फ्रांस में हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त अभिसमय 01 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 34 के पैराग्राफ 1 के अनुसार, संपुष्टि के पांचवें लिखत के जमा करने की तिथि को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेंडर माह की समाप्ति के बाद वाले महीने का पहला दिन है;

और जबकि, भारत ने 25 जुलाई, 2019 को उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 139 में दिए अनुसार उक्त अभिसमय की पुष्टि की थी तथा समाहित कर समझौतों, आरक्षणों एवं अधिसूचनाओं की सूची के साथ संपुष्टि के लिखत (इसके बाद इसे "उक्त अभिसमय के अंतर्गत भारत की स्थिति" कहा गया है) को न्यासी के पास जमा किया था;

और जबकि, भारत में उक्त अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख 01 अक्तूबर 2019 है, जो कि 25 जून, 2019, उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 34 के पैरा 2 के अनुसार भारत द्वारा संपुष्टि लिखत के जमा करने की तिथि है, को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेंडर माह की अवधि की समाप्ति के बाद के महीने का पहला दिन है;

और जबकि, उक्त अभिसमय के प्रावधान उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अनुसार समाहित कर समझौते के सम्बंध में भारत में प्रभावी होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अभिसमय के उपबंध भारत संघ में इसके साथ संलग्न अनुबंध के अनुसार उक्त अभिसमय के अंतर्गत भारत की स्थिति के अनुसार प्रभावी होंगे।

अनुबंध

आधार संकुचन और लाभ अंतरण को रोकने के लिए कर संधि संबंधी उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय अभिसमय

इस अभिसमय के पक्षकार,

इस बात को मानते हुए कि सरकारें काफी हद तक उन आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय कर नियोजन के कारण निगम कर राजस्व खो देती हैं जिससे उन स्थानों पर कृत्रिम रूप से लाभ स्थानांतरित होते हैं जहां वे गैर-कराधान या कम कराधान के अधीन हैं;

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आधार संकुचन और लाभ अंतरण (इसके बाद इसे "बीईपीएस" कहा गया है) न केवल औद्योगिक देशों के लिए बल्कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है;

यह सुनिश्चित करने की महत्ता को मानते हुए कि लाभों पर वहां कर लगाया जाता है जहां लाभ सृजित करने वाले पर्याप्त आर्थिक कार्यकलाप निष्पादित किए जाते हैं और जहां मूल्य सृजित किया जाता है;

ओईसीडी/जी 20 बीईपीएस परियोजना के तहत विकसित उपायों के पैकेज का स्वागत करते हुए (इसके बाद इसे "ओईसीडी/जी 20 बीईपीएस पैकेज" कहा गया है);

इस बात पर ध्यान देते हुए कि ओईसीडी/जी 20 बीईपीएस पैकेज में कुछ संकरित बेमेल व्यवस्थाओं को ठीक करने, संधि के दुरुपयोग को रोकने, स्थायी संस्थापनों की स्थिति के कृत्रिम परिहार को दूर करने, और विवाद के समाधान में सुधार के लिए कर संधि-संबंधित उपाय शामिल हैं;

बहुपक्षीय संदर्भ में संधि से संबंधित बीईपीएस उपायों का तेजी से, समन्वयित और सुसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक होते हुए;

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को नोट करते हुए कि आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए मौजूदा करार इन करारों में शामिल करों के सम्बंध में दोहरे कराधान, कर अपवंचन अथवा परिहार के द्वारा गैर-कराधान अथवा कम कराधान हेतु अवसर उत्पन्न किए बिना (तीसरे क्षेत्राधिकारों के निवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ हेतु उन करारों में प्रदत्त छूटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी की व्यवस्था के माध्यम सहित), को समाप्त करने की व्याख्या करते हैं।

प्रत्येक समझौते पर द्विपक्षीय पुनर्विचार की आवश्यकता के बिना आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए मौजूदा करारों के नेटवर्क में समकालिक और कुशल तरीके से सहमत परिवर्तनों को लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए;

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

भाग-I

पदों का कार्यक्षेत्र एवं व्याख्या

अनुच्छेद 1 - अभिसमय का कार्यक्षेत्र

यह अभिसमय अनुच्छेद 2 (पदों की व्याख्या) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ क) में वर्णित सभी समाहित कर समझौतों को संशोधित करता है।

अनुच्छेद 2 - पदों की व्याख्या

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

क) "समाहित कर समझौता" पद का अर्थ आय पर करों के सम्बंध में (अन्य कर शामिल हों अथवा नहीं) दोहरे कराधान के परिहार के लिए उस करार से है:

i) जो दो अथवा दो से अधिक:

क) पक्षकारों के बीच लागू है; और/अथवा

- ख) क्षेत्राधिकार अथवा राज्य-क्षेत्र जो ऊपर वर्णित किसी करार के पक्षकार हैं तथा जिनके अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों के लिए कोई पक्षकार जिम्मेदार है; तथा
- ii) जिनके संबंध में प्रत्येक ऐसे पक्षकार ने करार को सूचीबद्ध करने वाले जमाकर्ता को अधिसूचित किया है तथा कोई संशोधनकारी या उसके साथ एक करार के रूप में दिए गए कोई लिखत (शीर्षक, पक्षकारों के नाम, हस्ताक्षर की तारीख, और यदि अधिसूचना के समय लागू हो, लागू होने की तिथि से पहचाना गया) जो यह इस अभिसमय में शामिल करना चाहता है।
- ख) “पक्षकार” शब्द से अभिप्रेत है:
- i) एक राज्य जिसके लिए यह अभिसमय अनुच्छेद 34 (प्रवृत्ति) के अनुसार लागू है; या
- ii) कोई क्षेत्राधिकार जिसने अनुच्छेद 27 (हस्ताक्षर और सम्पुष्टि, स्वीकृति या अनुमोदन) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ख) अथवा ग) के अनुसार इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं और जिसके लिए यह अभिसमय अनुच्छेद 34 (प्रवृत्ति) के अनुसार लागू है।
- ग) “संविदाकारी क्षेत्राधिकार” पद का तात्पर्य समाहित कर समझौते के पक्षकार से है।
- घ) “हस्ताक्षरकर्ता” पद का तात्पर्य किसी राज्य अथवा क्षेत्राधिकार से है जिसने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं परंतु जहां यह अभिसमय अभी लागू नहीं हुआ है।
2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस अभिसमय को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस समय संगत समाहित कर समझौते के तहत था।

भाग II

संकर बेमेल

अनुच्छेद 3 - पारदर्शी संस्थाएं

- सम्मिलित कर सम्बंधी करार के प्रयोजनों के लिए, किसी संस्था या व्यवस्था जिसे किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के कर कानूनों के तहत पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय रूप से पारदर्शी माना जाता है, द्वारा या उसके माध्यम से प्राप्त आय संविदाकारी क्षेत्राधिकार के किसी निवासी की आय समझी जाएगी, उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के द्वारा कराधान के प्रयोजनार्थ, केवल उस सीमा तक आय समझी जाएगी जितनी उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी की आय।
 - समाहित कर समझौते के प्रावधानों द्वारा एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार से उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के किसी निवासी द्वारा प्राप्त आय के सम्बंध में जिस पर समाहित कर समझौते के प्रावधानों के अनुसार आयकर से छूट अथवा कटौती देने अथवा अदा किए गए आयकर के बराबर क्रेडिट अपेक्षित है, वो प्रावधान उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक ऐसे प्रावधान उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार को कराधान की अनुमति केवल इसलिए देते हैं कि वह आय उस अन्य संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा प्राप्त आय भी है।
 - समाहित कर समझौतों के सम्बंध में, जिसके लिए एक या एक से अधिक दलों ने अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण कर दिया है (किसी पक्षकार द्वारा अपने स्वयं के निवासियों पर कर लगाने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए कर समझौतों की प्रयोज्यता), निम्नलिखित वाक्य पैराग्राफ 1 के अंत में शामिल किया जाएगा : “किसी भी स्थिति में इस पैराग्राफ के प्रावधान किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासियों पर कर लगाने के अधिकार को प्रभावित करते हुए नहीं माने जाएंगे।”
 - पैराग्राफ 1 (जैसा कि पैराग्राफ 3 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है) उस सीमा तक समाहित कर समझौते के प्रावधानों की अनुपस्थिति में या उनके स्थान पर लागू होगा कि वे इस बात का समाधान दें कि क्या किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के कर कानून के तहत वित्तीय रूप से पारदर्शी मानी जा रही उन संस्थाओं या व्यवस्थाओं के माध्यम से या उनके द्वारा प्राप्त आय (चाहे एक सामान्य नियम के माध्यम से या विशिष्ट तथ्यों के पैटर्न और संस्थाओं या व्यवस्थाओं के प्रकारों के साथ व्यवहार के बारे में विस्तार से पहचानकर) किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी की आय के रूप में मानी जाएगी।
 - कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:
- क) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए;

- ख) उसके समाहित कर समझौतों पर जिनमें पैराग्राफ 4 में निर्धारित प्रावधान पहले से ही समाहित हो तो वहां पैराग्राफ 1 लागू न हो;
- ग) उसके समाहित कर समझौतों पर जिनमें पैराग्राफ 4 में निर्धारित प्रावधान, जो किसी तीसरे क्षेत्रधिकार में स्थापित किसी संस्था या व्यवस्था के माध्यम से अथवा उनके द्वारा प्राप्त आय के मामले में संधि लाभों से मना करते हैं, पहले से ही समाहित हो तो वहां पैराग्राफ 1 लागू न हो;
- घ) उसके समाहित कर समझौतों पर जिनमें पैराग्राफ 4 में निर्धारित प्रावधान, जो संस्थाओं अथवा व्यवस्थाओं के विशिष्ट तथ्य पैटर्नों के साथ व्यवहार को विस्तार से पहचानते हैं, पहले से ही समाहित हो तो वहां पैराग्राफ 1 लागू न हो;
- ङ.) उसके समाहित कर समझौतों पर जिनमें पैराग्राफ 4 में निर्धारित प्रावधान, जो किसी तीसरे क्षेत्रधिकार में स्थापित किसी संस्था या व्यवस्था के माध्यम से अथवा उनके द्वारा प्राप्त आय के मामले में संधि लाभों से मना करते हैं तथा जो संस्थाओं अथवा व्यवस्थाओं के विशिष्ट तथ्य पैटर्नों के साथ व्यवहार को विस्तार से पहचानते हैं, पहले से ही समाहित हो तो वहां पैराग्राफ 1 लागू न हो;
- च) उसके समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 2 लागू न हो;
- छ) उसके समाहित कर समझौतों पर जिनमें पैराग्राफ 4 में निर्धारित प्रावधान, जो संस्थाओं अथवा व्यवस्थाओं के विशिष्ट तथ्य पैटर्नों के साथ व्यवहार को विस्तार से पहचानते हैं, पहले से ही समाहित हो तो केवल वहां पैराग्राफ 1 लागू हो;

6. प्रत्येक पक्षकार जिसने पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ क) अथवा ख) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है वह निक्षेपागार को यह अधिसूचित करेगा कि क्या उसके प्रत्येक समाहित कर समझौते में पैराग्राफ 4 में वर्णित प्रावधान शामिल है जो पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ ग) से ङ) के तहत आरक्षण के अधीन नहीं है, और यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक प्रावधान का अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या। प्रत्येक उस पैराग्राफ के मामले में जिसने पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ छ) में वर्णित आरक्षण किया है, पूर्व वाक्य के अनुसरण में अधिसूचना उन समाहित कर समझौतों तक सीमित होगी जो उस आरक्षण के अधीन हैं। जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने समाहित कर समझौते के प्रावधान के संबंध में ऐसी एक अधिसूचना की है, वह प्रावधान पैराग्राफ 4 में प्रदान की गई सीमा तक पैराग्राफ 1 (जैसा कि अनुच्छेद 3 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है) के प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। अन्य मामलों में, पैराग्राफ 1 (जैसा कि अनुच्छेद 3 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है) समाहित कर समझौते के प्रावधानों को केवल उस सीमा तक हटा देगा जहां तक वे प्रावधान पैराग्राफ 1 (जैसा कि अनुच्छेद 3 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है) के साथ विसंगत हों।

अनुच्छेद 4 - दोहरी निवास संस्थाएं

1. एक समाहित कर समझौते के प्रावधानों के कारण जहां एक व्यष्टि के अलावा अन्य व्यक्ति एक से अधिक संविदाकारी क्षेत्राधिकार का निवासी है, संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम अधिकारी पारस्परिक समझौते द्वारा यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि सम्मिलित कर सम्बंधी करार के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति को किस संविदाकारी क्षेत्राधिकार का निवासी माना जाएगा, उसके प्रभावी प्रबंधन के स्थान, जिस स्थान पर वह निगमित या अन्यथा गठित है और किन्हीं अन्य प्रासंगिक कारकों का आदर करते हुए। ऐसी सहमति की अनुपस्थिति में, वह व्यक्ति समाहित कर समझौते द्वारा कर से प्रदत्त किसी छूट अथवा रियायत का पात्र नहीं होगा सिवाए उस सीमा तक और ऐसी पद्धति में जिस पर संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमति बनती है।

2. पैराग्राफ 1 समाहित कर समझौते के उन प्रावधानों की अनुपस्थिति में अथवा उनके स्थान पर लागू होगा जिनमें यह निर्धारित करने के नियम दिए गए हैं कि क्या किसी व्यष्टि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उन मामलों में जिनमें वह व्यक्ति अन्यथा किसी एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार से अधिक संविदाकारी क्षेत्राधिकारों का निवासी माना जाता, संविदाकारी क्षेत्राधिकारों में से किसी एक का निवासी माना जाएगा। हालांकि, एक समाहित कर समझौते के विशेष रूप से दोहरे-सूचीबद्ध कंपनियों की व्यवस्था में भाग लेने वाली कंपनियों के निवास का समाधान करने वाले प्रावधानों पर पैराग्राफ 1 लागू नहीं होगा।

3. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:

- क) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए;
- ख) सम्पूर्ण रूप से यह अनुच्छेद उसके उन समाहित कर समझौतों पर लागू न हो जो पहले से ही उन मामलों का

समाधान करते हैं जहां एक व्यक्ति के अलावा कोई व्यक्ति संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निवास के एकल संविदाकारी क्षेत्राधिकार पर पारस्परिक सहमति से पहुंचने के प्रयास की अपेक्षा के द्वारा एक से अधिक संविदाकारी क्षेत्राधिकारों का निवासी है;

- ग) सम्पूर्ण रूप से यह अनुच्छेद उसके उन समाहित कर समझौतों पर लागू न हो जो पहले से ही उन मामलों का समाधान करते हैं जहां एक व्यक्ति के अलावा कोई व्यक्ति संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निवास के एकल संविदाकारी क्षेत्राधिकार पर पारस्परिक सहमति से पहुंचने के प्रयास की अपेक्षा के बिना संधि लाभों को मना करते हुए, एक से अधिक संविदाकारी क्षेत्राधिकारों का निवासी है;
- घ) सम्पूर्ण रूप से यह अनुच्छेद उसके उन समाहित कर समझौतों पर लागू न हो जो पहले से ही उन मामलों का समाधान करते हैं जहां एक व्यक्ति के अलावा कोई व्यक्ति संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निवास के एकल संविदाकारी क्षेत्राधिकार पर पारस्परिक सहमति से पहुंचने के प्रयास की अपेक्षा के द्वारा एक से अधिक संविदाकारी क्षेत्राधिकारों का निवासी है, तथा यह भी कि समाहित कर समझौते के तहत उस व्यक्ति के समाधान की व्यवस्था हो जहां ऐसी सहमति पर नहीं पहुंचा जा सकता;
- ङ.) उसके समाहित कर समझौतों के प्रयोजनार्थ पैराग्राफ 1 के अंतिम वाक्य को निम्नलिखित विषय सामग्री से प्रतिस्थापित करना: "ऐसी सहमति की अनुपस्थिति में, वह व्यक्ति सम्मिलित कर सम्बंधी करार द्वारा कर से प्रदत्त किसी छूट अथवा रियायत का पात्र नहीं होगा";
- च) सम्पूर्ण रूप से यह अनुच्छेद उन पक्षकारों के साथ उसके समाहित कर समझौतों पर लागू न हो जिन्होंने उप-पैराग्राफ ३ में निर्धारित आरक्षण किया है।

4. प्रत्येक पार्टी, जिसने पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यास को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके सम्मिलित कर करार के प्रत्येक में इस पैराग्राफ 2 में वर्णित उपबंध निहित है जो पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ ख) से घ) के तहत आरक्षण के अधीन नहीं है, और यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक प्रावधान का अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या। जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने सम्मिलित कर सम्बंधी करार के प्रावधान के संबंध में ऐसी एक अधिसूचना की है, वह प्रावधान पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित जाएगा। अन्य मामलों में, पैराग्राफ 1 शामिल कर समझौते के प्रावधानों को केवल उस सीमा तक अधिक्रमित करेगा, कि वो प्रावधान पैराग्राफ 1 से असंगत हैं।

अनुच्छेद 5 - दोहरे कराधान के निरसन की विधि की प्रयोज्यता

1. कोई भी पक्षकार या तो पैराग्राफ 2 एवं 3 (विकल्प क), पैराग्राफ 4 एवं 5 (विकल्प ख), अथवा पैराग्राफ 6 एवं 7 (विकल्प ग) को लागू करना चुन सकता है अथवा इन विकल्पों में से किसी को भी लागू न करना चुन सकता है। जहाँ समाहित कर समझौते का प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार भिन्न विकल्प चुनता है (अथवा जहाँ एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार एक विकल्प लागू करना चुनता है तथा दूसरा किसी भी विकल्प को लागू करना चुनता है) तो प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा चुना गया विकल्प उसके अपने निवासियों के सम्बंध में लागू होगा।

विकल्प क

2. किसी समाहित कर समझौते के प्रावधान जो अन्यथा दोहरे कराधान को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार में उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी की स्वामित्व वाली पूंजी अथवा व्युत्पन्न आय को कर से छूट प्रदान करेंगे, वहाँ लागू नहीं होंगे जहां अन्य संविदाकारी क्षेत्राधिकार इस तरह की आय या पूंजी को कर से छूट देने के लिए अथवा उस दर को सीमित करने के लिए जिस पर ऐसी आय या पूंजी पर कर लगाया जा सकता है, समाहित कर समझौते के प्रावधानों को लागू करता है। उत्तरार्द्ध मामले में, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार उस निवासी की आय या पूंजी पर कर से कटौती के रूप में अनुमति देगा, जो कि अन्य संविदाकारी क्षेत्राधिकार में दिए गए कर के बराबर होगी। तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित, आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय ऐसी आय अथवा पूंजी को हो, जिस पर उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर लगाया जा सकता है।

3. पैराग्राफ 2 उस समाहित कर समझौते पर लागू होगा जो अन्यथा संविदाकारी क्षेत्राधिकार से उस पैराग्राफ में वर्णित आय अथवा पूंजी को छूट देने की अपेक्षा करेगा।

विकल्प ख

4. किसी समाहित कर समझौते के प्रावधान जो अन्यथा दोहरे कराधान को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ एक संविदाकारी

क्षेत्राधिकार में उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी की व्युत्पन्न आय को कर से छूट प्रदान करेंगे क्योंकि ऐसी आय उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा अंशलाभ के रूप में मानी जाती है, वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ ऐसी आय दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के कानूनों के तहत उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी के कराधेय लाभों के निधरिण के प्रयोजनार्थ कटौती को बढ़ावा देगी। ऐसे मामले में, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार उस निवासी की आय पर कर से कटौती के रूप में अनुमति देगा, जो कि दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में दिए गए कर के बराबर होगी। तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित, आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय ऐसी आय को हो, जिस पर उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर लगाया जा सकता है।

5. पैराग्राफ 4 उस समाहित कर समझौते पर लागू होगा जो अन्यथा संविदाकारी क्षेत्राधिकार से उस पैराग्राफ में वर्णित आय को छूट देने की अपेक्षा करेगा।

विकल्प ग

6. क) जहाँ एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार का कोई निवासी आय प्राप्त करता है या उस पूंजी का मालिक है, जिस पर दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में समाहित कर समझौते के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया जा सकता है (इस सीमा तक को छोड़कर कि ये प्रावधान केवल उस अन्य संविदाकारी क्षेत्राधिकार को कराधान की अनुमति मात्र इसलिए देते हैं क्योंकि यह आय उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भी है), तो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार निम्नलिखित की अनुमति देगा:

- i) उस निवासी की आय पर कर से कटौती के रूप में, जो कि उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में दिए गए कर के बराबर होगी;
- ii) उस निवासी की पूंजी पर कर से कटौती के रूप में, जो कि उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में अदा किए गए पूंजीकर के बराबर होगी।

तथापि, ऐसी कटौती, कटौती दिए जाने से पहले यथा-संगणित, आयकर अथवा पूंजीकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय ऐसी आय अथवा पूंजी को हो, जिस पर उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर लगाया जा सकता है।

ख) जहाँ समाहित कर समझौते के किसी प्रावधान के अनुसार किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी के स्वामित्व वाली पूंजी अथवा उस द्वारा प्राप्त आय उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर से छूट प्राप्त है, ऐसा संविदाकारी क्षेत्राधिकार फिर भी, ऐसे निवासी की शेष आय अथवा पूंजी पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय अथवा पूंजी को खाते में ले सकता है।

7. पैराग्राफ 6 उस समाहित कर समझौते के प्रावधानों के स्थान पर लागू होगा जो दोहरे कराधान को समाप्त करने के उद्देश्य से, एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी के स्वामित्व वाली पूंजी अथवा उस द्वारा अर्जित आय पर उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार में उसी क्षेत्राधिकार द्वारा कर से छूट देने की अपेक्षा करता हो, जिस पर समाहित कर समझौते के प्रावधानों के अनुसार दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर लगाया जा सकता है।

8. कोई भी पक्षकार जो पैराग्राफ 1 के तहत विकल्प लागू करने का चुनाव नहीं करता वह एक या एक से अधिक इंगित समाहित कर समझौतों (अथवा उसके सभी समाहित कर समझौतों के सम्बंध में) के सम्बंध में इस सम्पूर्ण अनुच्छेद को लागू न करने का अधिकार अपने पास रख सकता है।

9. कोई भी पक्षकार जो विकल्प ग लागू करने का चुनाव नहीं करता वह एक या एक से अधिक इंगित समाहित कर समझौतों (अथवा उसके सभी समाहित कर समझौतों के सम्बंध में) के सम्बंध में दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकारों को विकल्प ग लागू करने की अनुमति न देने का अधिकार अपने पास रख सकता है।

10. प्रत्येक पक्षकार जो पैराग्राफ 1 के तहत विकल्प लागू करना चुनता है वह निक्षेपागार को अपने विकल्प के चुनाव के सम्बंध में अधिसूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना में ये भी शामिल होंगे:

- क) उस पक्षकार के मामले में जो विकल्प क लागू करना चुनता है, उसके समाहित कर समझौतों की सूची जिनमें पैराग्राफ 3 में निर्धारित प्रावधान हो, तथा प्रत्येक ऐसे प्रावधान का अनुच्छेद एवं पैराग्राफ संख्या हो;
- ख) उस पक्षकार के मामले में जो विकल्प ख लागू करना चुनता है, उसके समाहित कर समझौतों की सूची जिनमें पैराग्राफ 5 में निर्धारित प्रावधान हो, तथा प्रत्येक ऐसे प्रावधान का अनुच्छेद एवं पैराग्राफ संख्या हो;

- ग) उस पक्षकार के मामले में जो विकल्प ग लागू करना चुनता है, उसके समाहित कर समझौतों की सूची जिनमें पैराग्राफ 7 में निर्धारित प्रावधान हो, तथा प्रत्येक ऐसे प्रावधान का अनुच्छेद एवं पैराग्राफ संख्या हो;

किसी समाहित कर समझौते के प्रावधान के सम्बंध में कोई विकल्प केवल वहीं लागू होगा जहाँ उस पक्षकार ने जिसने वह विकल्प लागू करना चुना है, उस प्रावधान के सम्बंध में ऐसी अधिसूचना की है।

भाग III

संधि का दुरुपयोग

अनुच्छेद 6 - समाहित कर समझौते का उद्देश्य

1. निम्नलिखित प्रस्तावना विषय सामग्री को शामिल करने के लिए समाहित कर समझौते को संशोधित किया जाएगा:

“कर अपवंचन अथवा परिहार के द्वारा गैर-कराधान अथवा कम कराधान हेतु अवसर उत्पन्न किए बिना इस करार में शामिल करों के सम्बंध में दोहरे कराधान को समाप्त करने के इरादे से (तीसरे क्षेत्राधिकारों के निवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ हेतु इस करार में प्रदत्त छूटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी की व्यवस्था के माध्यम सहित),”।

2. पैराग्राफ 1 में वर्णित पाठ को दोहरे कराधान को समाप्त करने के इरादे का उल्लेख करने वाले समाहित कर समझौते की प्रस्तावना भाषा की अनुपस्थिति में या उसके स्थान पर, चाहे उस भाषा में गैर-कराधान या कम कराधान के लिए अवसर उत्पन्न न करने के इरादे का भी उल्लेख किया गया हो या नहीं, सम्मिलित कर सम्बंधी करार में शामिल किया जाएगा।

3. कोई पक्षकार अपने उस समाहित कर समझौते के सम्बंध में निम्नलिखित प्रस्तावना पाठ को भी शामिल करना चुन सकती है जिसमें कर मामलों में सहयोग को बढ़ाने अथवा आर्थिक सम्बंध विकसित करने की इच्छा का उल्लेख करने वाली प्रस्तावना भाषा शामिल न हो:

“अपने आर्थिक संबंध और विकसित करने तथा कर मामलों में अपना सहयोग बढ़ाने की इच्छा से,”।

4. कोई पक्षकार अपने उन समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 1 लागू न करने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है जिनमें पहले ही वह प्रस्तावना भाषा शामिल है जिसमें संविदाकारी क्षेत्राधिकारों का, गैर-कराधान अथवा कम कराधान हेतु अवसर उत्पन्न किए बिना दोहरे कराधान को समाप्त करने के इरादे का उल्लेख किया गया हो, चाहे वह भाषा कर अपवंचन अथवा परिहार के मामलों तक सीमित हो या अधिक प्रयोग में लाई जाती हो (तीसरे क्षेत्राधिकारों के निवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ हेतु समाहित कर समझौते में प्रदत्त छूटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी की व्यवस्था के माध्यम सहित)।

5. प्रत्येक पक्षकार निक्षेपागार को यह अधिसूचित करेगा कि क्या उसके समाहित कर समझौतों में से प्रत्येक में, उनके अलावा जो पैराग्राफ 4 के तहत आरक्षण के दायरे में हैं, पैराग्राफ 2 में वर्णित प्रस्तावना भाषा शामिल है, यदि हाँ, तो संगत प्रस्तावना पैराग्राफ के पाठ के बारे में। जहाँ सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस प्रस्तावना भाषा के संबंध में ऐसी एक अधिसूचना की है, तो वह प्रस्तावना भाषा पैराग्राफ 1 में वर्णित पाठ के साथ प्रतिस्थापित की जाएगी। अन्य मामलों में, विद्यमान प्रस्तावना भाषा के अलावा पैराग्राफ 1 में वर्णित पाठ को जोड़ा जाएगा।

6. प्रत्येक पक्षकार जो पैराग्राफ 3 लागू करना चुनता है वह निक्षेपागार को अपने चुनाव के सम्बंध में अधिसूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना में उसके उन समाहित कर समझौतों की सूची भी शामिल होगी जिनमें कर मामलों में सहयोग को बढ़ाने अथवा आर्थिक सम्बंध विकसित करने की इच्छा का उल्लेख करने वाली प्रस्तावना भाषा पहले ही शामिल न हो: पैराग्राफ 3 में वर्णित पाठ को समाहित कर समझौते में केवल वहाँ शामिल किया जाएगा जहाँ सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस पैराग्राफ को लागू करना चुना है तथा समाहित कर समझौते के सम्बंध में ऐसी अधिसूचना की है।

अनुच्छेद 7 - संधि दुरुपयोग की रोकथाम

1. समाहित कर समझौते में किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, आय अथवा पूंजी के सम्बंध में समाहित कर समझौते के तहत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, यदि यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है, सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कि वह लाभ प्राप्त करना किसी व्यवस्था अथवा संव्यवहार के मुख्य उद्देश्यों में से एक था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वह लाभ हुआ है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता हो कि इन परिस्थितियों में उस लाभ का प्रदान किया जाना इस समाहित कर समझौते के संगत उपबंधों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुरूप है।

2. पैराग्राफ 1 समाहित कर समझौते के उन प्रावधानों की अनुपस्थिति में या उनके स्थान पर लागू होगा जो उन सभी लाभों अथवा लाभों के भाग से मना करते हैं जो अन्यथा समाहित कर समझौते के तहत दिए जाते जहाँ किसी व्यवस्था अथवा

संव्यवहार का अथवा किसी व्यवस्था अथवा संव्यवहार से सम्बंधित किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से एक उन लाभों को प्राप्त करना होता।

3. कोई पक्षकार जिसने पैराग्राफ 15 के उप-पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है वह उसके समाहित कर समझौतों के सम्बंध में पैराग्राफ 4 लागू करना भी चुन सकता है।

4. जहाँ किसी समाहित कर समझौते के तहत कोई लाभ उस समाहित कर समझौते के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को मना किया जाता है जो उन सभी लाभों अथवा लाभों के भाग से मना करता है जो अन्यथा समाहित कर समझौते के तहत दिए जाते जहाँ किसी व्यवस्था अथवा संव्यवहार का अथवा किसी व्यवस्था अथवा संव्यवहार से सम्बंधित किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से एक उन लाभों को प्राप्त करना होता, उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी जो अन्यथा यह लाभ प्रदान कर देते, फिर भी उस व्यक्ति को इस लाभ का अथवा किसी विशिष्ट आय या पूंजी के सम्बंध में विभिन्न लाभों का हकदार मानेंगे, यदि ऐसे सक्षम प्राधिकारी, उस व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने पर संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे लाभ संव्यवहार या व्यवस्था की अनुपस्थिति में उस व्यक्ति को दे दिए जाते। उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा इस पैराग्राफ के तहत अनुरोध किया गया है, अनुरोध को ठुकराने से पूर्व दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेंगे।

5. पैराग्राफ 4 समाहित कर समझौते (जैसाकि इसे इस अभिसमय के द्वारा संशोधित किया जा सकता है) के उन प्रावधानों पर लागू होगा जो उन सभी लाभों अथवा लाभों के भाग से मना करते हैं जो अन्यथा समाहित कर समझौते के तहत दिए जाते जहाँ किसी व्यवस्था अथवा संव्यवहार का अथवा किसी व्यवस्था अथवा संव्यवहार से सम्बंधित किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से एक उन लाभों को प्राप्त करना होता।

6. कोई पक्षकार पैराग्राफ 8 से 13 में समाहित प्रावधानों (इसके बाद उन्हें "लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को पैराग्राफ 17 के उप-पैराग्राफ ग) में निर्धारित अधिसूचना करके उसके समाहित कर समझौतों पर भी लागू करना चुन सकता है। लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन केवल उस समाहित कर समझौते के सम्बंध में लागू होगा जहाँ सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उसे लागू करना चुना है।

7. उन मामलों में जहाँ समाहित कर समझौते के कुछ परंतु सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकार नहीं, पैराग्राफ 6 के अनुसरण में लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लगाना चुनते हैं, तब, उस पैराग्राफ के प्रावधानों में कुछ भी होते हुए, लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन समाहित कर समझौते के तहत लाभ देने के सम्बंध में लागू होगा:

- क) सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों द्वारा, यदि सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकार जो पैराग्राफ 6 के अनुसरण में लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू करना नहीं चुनते हैं, इस उप-पैराग्राफ को लागू करने का चुनाव करके तथा तदनुसार निक्षेपागार को अधिसूचित करके ऐसी प्रयोज्यता के लिए सहमत होते हैं; अथवा
- ख) केवल उन संविदाकारी क्षेत्राधिकारों द्वारा जो लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू करना चुनते हैं, यदि सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकार जो पैराग्राफ 6 के अनुसरण में लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू करना नहीं चुनते हैं, इस उप-पैराग्राफ को लागू करने का चुनाव करके तथा तदनुसार निक्षेपागार को अधिसूचित करके ऐसी प्रयोज्यता के लिए सहमत होते हैं।

लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन

8. लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन में अन्यथा दिए गए को छोड़कर समाहित कर समझौते के संविदाकारी क्षेत्राधिकार का कोई निवासी उस लाभ का हकदार नहीं होगा जो समाहित कर समझौते के प्रावधानों के तहत लाभ के अलावा अन्यथा सम्मिलित कर सम्बंधी करार द्वारा दिया जाता:

- क) जो किसी व्यष्टि के अलावा किसी उस व्यक्ति के निवास को निर्धारित करता है जो उस समाहित कर समझौते के प्रावधानों के कारण एक से अधिक संविदाकारी क्षेत्राधिकार का निवासी है जिसमें संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी को परिभाषित किया गया है;
- ख) जिसमें प्रावधान है कि एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के किसी उद्यम को समाहित कर समझौते के अनुसार दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा किए गए प्रारम्भिक समायोजन के अनुपालन में, किसी सहयोगी उद्यम के लाभों पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार में प्रभारित कर की राशि के अनुरूप समायोजन प्रदान करेगा; अथवा

- ग) जो एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासियों को यह अनुरोध करने की अनुमति देता है कि उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी करानान के उन मामलों पर विचार करे जो समाहित कर समझौते के अनुसार नहीं हैं,

जब तक कि ऐसा निवासी एक "अर्हता प्राप्त व्यक्ति" न हो, पैराग्राफ 9 में परिभाषित अनुसार उस समय जब लाभ दिया जाएगा।

9. समाहित कर समझौते के किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार का कोई निवासी उस समय जब समाहित कर समझौते द्वारा अन्यथा लाभ दिया जाता, एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति होगा, उस समय, निवासी एक :

- क) व्यक्ति;
- ख) वह संविदाकारी क्षेत्राधिकार, अथवा कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण, अथवा ऐसे किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार, राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण की कोई एजेंसी या संस्था;
- ग) कोई कम्पनी अथवा अन्य संस्था, यदि इसके शेयरों की मुख्य श्रेणी एक या अधिक मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में नियमित तौर पर ट्रेड की जाती है;
- घ) किसी व्यक्ति के अलावा कोई एक व्यक्ति, जो:

- i) उस प्रकार का गैर-लाभकारी संगठन है जिस पर संविदाकारी क्षेत्राधिकारों द्वारा राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान के माध्यम से सहमति हुई हो; अथवा
- ii) उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार में स्थापित कोई संस्था अथवा व्यवस्था है जिसे उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के करानान कानूनों के तहत पृथक् व्यक्ति के रूप में माना जाता हो और:

क) जो व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति लाभ और सहायक या आकस्मिक लाभ प्रदान करने या प्रदान करने के लिए विशेष रूप से या लगभग अनन्य रूप से स्थापित और संचालित हो और जो उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार या उसके किसी एक राजनैतिक उप प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार विनियमित होता हो; या

ख) जो उप-प्रभाग क) में संदर्भित संस्थाओं अथवा व्यवस्थाओं के लाभ के लिए निधि निवेश करने के लिए विशेष रूप से या लगभग अनन्य रूप से स्थापित और संचालित हो;

- ड.) किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, यदि, बारह महीने की अवधि के कम से कम आधे दिनों में जिसमें वह समय शामिल होता है जब लाभ अन्यथा दिया जाता, वे व्यक्ति जो उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी हैं और जो कि उप-पैराग्राफ क) से घ) के तहत समाहित कर समझौते के लाभों के हकदार हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस व्यक्ति के कम से कम 50 प्रतिशत शेयरों के स्वामी हों।

10. क) किसी समाहित कर समझौते के एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार से अर्जित आय के सम्बंध में समाहित कर समझौते के लाभों का हकदार होगा, चाहे वह निवासी एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति है या नहीं, यदि वह निवासी प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार में किसी व्यवसाय के सक्रिय संचालन में कार्यरत हो, और दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार से प्राप्त आय उस व्यवसाय से उत्पन्न होती हो या उससे आनुषंगिक हो। लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन के प्रयोजनार्थ, "किसी व्यवसाय का सक्रिय संचालन" में निम्नलिखित गतिविधियां अथवा उनका कोई संयोजन शामिल नहीं होगा:

- i) होलिंग कम्पनी के रूप में संचालन;
- ii) कम्पनियों के समूह को सम्पूर्ण पर्यवेक्षण अथवा प्रशासन उपलब्ध करवाना;
- iii) सामूहिक वित्तपोषण उपलब्ध करवाना (कैश पूलिंग सहित); अथवा
- iv) निवेश करना अथवा उसका प्रबंधन करना, जब तक कि ये गतिविधियां किसी बैंक, बीमा कम्पनी अथवा पंजीकृत प्रतिभूति डीलर द्वारा उनके व्यवसाय की सामान्य स्थिति में न की जाती हों।

- ख) यदि किसी समाहित कर समझौते के एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार का कोई निवासी उस निवासी द्वारा दूसरे

संविदाकारी क्षेत्राधिकार में संचालित कारोबारी गतिविधि से आय अर्जित करता है, अथवा किसी सम्बंधित व्यक्ति से दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में उत्पन्न आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय के सम्बंध में उप-पैराग्राफ क) में वर्णित शर्तें केवल तभी पूरी हुई मानी जाएंगी यदि उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार में जिससे वह आय सम्बंधित है, उस निवासी द्वारा संचालित की गई कारोबारी गतिविधि उस निवासी द्वारा अथवा उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में ऐसे सम्बंधित व्यक्ति द्वारा उसी गतिविधि या सहयोगी कारोबारी गतिविधि के सम्बंध में पर्याप्त है। इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ कोई कारोबारी गतिविधि पर्याप्त है या नहीं, वह सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

- ग) यह पैराग्राफ लागू करने के लिए, समाहित कर समझौते के एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के किसी निवासी के सम्बंध में सम्बंधित व्यक्तियों द्वारा संचालित गतिविधियां ऐसे निवासी द्वारा संचालित की गई मानी जाएंगी।

11. किसी समाहित कर समझौते के एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार का कोई निवासी जो एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति नहीं है तो भी उस लाभ का हकदार होगा जो उस आय के सम्बंध में समाहित कर समझौते द्वारा अन्यथा दी जाती यदि, बारह महीने की अवधि के कम से कम आधे दिनों में जिसमें वह समय शामिल होता है जब लाभ अन्यथा दिया जाता, वे व्यक्ति जो समान लाभार्थी हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस निवासी के कम से कम 75 प्रतिशत लाभकारी हितों के स्वामी हों।

12. यदि समाहित कर समझौते के एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार का कोई निवासी न तो पैराग्राफ 9 के प्रावधानों के अनुसरण में अर्हता प्राप्त व्यक्ति है, न ही पैराग्राफ 10 अथवा 11 के तहत लाभों का हकदार है, तो फिर भी दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी समाहित कर समझौते के लाभ अथवा विशिष्ट आय के सम्बंध में लाभ दे सकते हैं, समाहित कर समझौते के ध्येय एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, परंतु केवल तभी यदि ऐसा निवासी ऐसे सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तक यह दर्शाता है कि न तो उसके संस्थान, अधिग्रहण अथवा अनुरक्षण, और न ही इसके कार्यों के संचालन का मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य समाहित कर समझौते के तहत लाभ प्राप्त करना था। संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा इस पैराग्राफ के तहत किए गए अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले, उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी जिससे अनुरोध किया गया है, उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेंगे।

13. लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन के प्रयोजनार्थ:

- क) “मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार” शब्द से तात्पर्य है:

- i) किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के कानूनों के तहत इस प्रकार स्थापित एवं विनियमित कोई भी शेयर बाज़ार; तथा
- ii) संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमत कोई अन्य शेयर बाज़ार;

ख) “शेयरों का प्रमुख वर्ग” शब्द का अर्थ है, किसी कंपनी के शेयरों की श्रेणी या श्रेणियां जो कंपनी के कुल वोट और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती हैं या किसी संस्था के लाभकारी हितों की श्रेणी या श्रेणियां जो सकल में संस्था के कुल वोट तथा मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती हैं;

ग) “समतुल्य लाभार्थी” शब्द का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के घरेलू कानूनों, समाहित कर समझौते अथवा किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय लिखित जो उस समाहित कर समझौते के तहत उस आय के मद को दिए जाने वाले लाभों के समतुल्य हैं अथवा उनसे अधिक अनुकूल, के तहत किसी समाहित कर समझौते के उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा दी गई आय के सम्बंध में लाभों का हकदार होगा; यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या कोई व्यक्ति लाभांश के संबंध में समतुल्य लाभार्थी है, उस व्यक्ति को लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी की उतनी ही पूंजी का धारक माना जाएगा जितनी पूंजी की लाभांश के संबंध में लाभ का दावा कर रही कम्पनी धारक है;

घ) उन सस्थाओं के सम्बंध में जो कम्पनियां नहीं हैं, “शेयर” शब्द का तात्पर्य हितों से है जो शेयरों के साथ तुलनीय हैं;

ड.) दो व्यक्ति “संबद्ध व्यक्ति” होंगे यदि कोई एक व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे में कम से कम 50 प्रतिशत के लाभकारी हित का मालिक हो (या, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के शेयरों के कुल वोट और मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत) या वह दूसरा व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक व्यक्ति में लाभप्रद हित के कम से कम 50 प्रतिशत (या, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के शेयरों के कुल वोट और मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत) का मालिक हो; किसी भी मामले में, एक व्यक्ति दूसरे से संबद्ध होगा, यदि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, एक का दूसरे पर नियंत्रण हो या दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के नियंत्रण में हों।

14. लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन किसी समाहित कर समझौते के उन प्रावधानों के स्थान पर या उनकी अनुपस्थिति में लागू होगा जो समाहित कर समझौते के लाभों को केवल उस निवासी तक सीमित करेंगे (या इससे निवास, संबद्ध उद्यमों या गैर-भेदभाव या वह लाभ जो केवल एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासियों तक प्रतिबंधित न हो से सम्बंधित समाहित कर समझौते के प्रावधानों के तहत लाभ को छोड़कर लाभों को सीमित किया जाएगा) जो एक या अधिक स्पष्ट परीक्षणों को पूरा करके ऐसे लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

15. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:

- क) इसके समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 1 लागू न होने के लिए इस आधार पर कि उसका इरादा लाभों के प्रावधान पर विस्तृत परिसीमन तथा वित्तपोषण ढांचे अथवा मुख्य प्रयोजन परीक्षण को दुरुस्त करने हेतु किन्हीं नियमों के समायोजन को अपनाना है, जिससे ओईसीडी/जी 20 बीईपीएस पैकेज के तहत संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यूनतम मानक अपनाए जा सकें; ऐसे मामलों में, संविदाकारी क्षेत्राधिकार पारस्परिक संतोषजनक समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे जो न्यूनतम मानकों पर खरा उतरता हो;
- ख) उसके समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 1 (तथा पैराग्राफ 4, उस पक्षकार के मामले में जिसने वह पैराग्राफ लागू करना चुना है) लागू न होने के लिए जिनमें पहले ही वह प्रावधान शामिल है जो उन सभी लाभों से मना करता है जो अन्यथा समाहित कर समझौते के तहत दिए जाते जहाँ किसी व्यवस्था अथवा संव्यवहार का अथवा किसी व्यवस्था अथवा संव्यवहार से सम्बंधित किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से एक उन लाभों को प्राप्त करना होता;
- ग) उसके उन समाहित कर समझौतों पर लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू न होने के लिए जिनमें पैराग्राफ 14 में निर्धारित प्रावधान पहले से ही समाहित हों।

16. सिवाय वहाँ जहाँ पैराग्राफ 7 के अनुसरण में एक या अधिक पक्षकारों द्वारा समाहित कर समझौते के तहत लाभ देने के सम्बंध में लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू होता हो, कोई पक्षकार जो पैराग्राफ 6 के अनुसरण में लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू करना चुनता है तो वह अपने उन समाहित कर समझौतों के सम्बंध में यह सम्पूर्ण अनुच्छेद लागू न करने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है जिसके लिए एक अथवा अधिक अन्य संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू करने का चुनाव नहीं किया है। ऐसे मामलों में, संविदाकारी क्षेत्राधिकार एक पारस्परिक संतोषजनक समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे जो ओईसीडी/जी20 बीईपीएस के तहत संधि दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यूनतम मानक पर खरा उतरे।

17. क) प्रत्येक पक्षकार जिसने पैराग्राफ 15 के उप-पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है वह निक्षेपागार को यह अधिसूचित करेगा कि क्या उसके प्रत्येक समाहित कर समझौते जो पैराग्राफ 15 के उप-पैराग्राफ ख) में वर्णित आरक्षण के अधीन नहीं है, में पैराग्राफ 2 में वर्णित प्रावधान शामिल है, और यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक प्रावधान का अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या। जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने समाहित कर समझौते के प्रावधान के संबंध में ऐसी एक अधिसूचना की है, तो वह प्रावधान पैराग्राफ 1 के प्रावधानों (और जहाँ लागू हो, पैराग्राफ 4) के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। अन्य मामलों में, पैराग्राफ 1 (और जहाँ लागू हो, पैराग्राफ 4) समाहित कर समझौते के प्रावधानों को केवल उस सीमा तक हटा देगा जहां तक वे प्रावधान पैराग्राफ 1 (और जहाँ लागू हो, पैराग्राफ 4) के साथ विसंगत हों। इस पैराग्राफ के तहत अधिसूचना करने वाला कोई भी पक्षकार यह कथन शामिल कर सकता है कि जब ऐसा पक्षकार केवल पैराग्राफ 1 की प्रयोज्यता को एक अंतरिम उपाय के तौर पर स्वीकार करता है, जहाँ सम्भव हो उसका इरादा लाभों के प्रावधान पर परिसीमन को पैराग्राफ 1 के अतिरिक्त अथवा उसके स्थान पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अपनाने का है।

ख) प्रत्येक पक्षकार जो पैराग्राफ 4 लागू करना चुनता है वह निक्षेपागार को अपने चुनाव के सम्बंध में अधिसूचित करेगा। पैराग्राफ 4 समाहित कर समझौते पर केवल वहाँ लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने ऐसी एक अधिसूचना की है।

ग) प्रत्येक ऐसा पक्षकार जो पैराग्राफ 6 के अनुसरण में लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू करना चुनता है, तो वह निक्षेपागार को अपने चुनाव के बारे में अधिसूचित करेगा। जब तक ऐसे पक्षकार ने पैराग्राफ 15 के उप-पैराग्राफ ग) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, ऐसी अधिसूचना में इसके ऐसे समाहित कर समझौतों की सूची भी शामिल होगी जिनमें पैराग्राफ 14 में वर्णित प्रावधान तथा ऐसे प्रत्येक प्रावधान का अनुच्छेद एवं पैराग्राफ संख्या समाहित हो।

- घ) प्रत्येक ऐसा पक्षकार जो पैराग्राफ 6 के अनुसरण में लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन लागू करना नहीं चुनता, परंतु पैराग्राफ 7 का उपग्राफ क) अथवा ख) लागू करना चुनता है तो वह निक्षेपागार को अपने उप-पैराग्राफ के चुनाव के बारे में अधिसूचित करेगा। जब तक ऐसे पक्षकार ने पैराग्राफ 15 के उप-पैराग्राफ ग) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, ऐसी अधिसूचना में इसके ऐसे समाहित कर समझौतों की सूची भी शामिल होगी जिनमें पैराग्राफ 14 में वर्णित प्रावधान तथा ऐसे प्रत्येक प्रावधान का अनुच्छेद एवं पैराग्राफ संख्या समाहित हो।
- ड.) जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने समाहित कर समझौते के प्रावधान के संबंध में उपग्राफ ग) अथवा घ) के तहत एक अधिसूचना की है, वह प्रावधान लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। अन्य मामलों में, लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन समाहित कर समझौते के प्रावधानों को केवल उस सीमा तक हटा देगा जहां तक वे प्रावधान लाभों के प्रावधान पर सरलीकृत परिसीमन के साथ विसंगत हों।

अनुच्छेद 8 - लाभान्श अंतरण संव्यवहार

1. एक समाहित कर समझौते के प्रावधान जो किसी क्षेत्राधिकार की निवासी किसी कंपनी द्वारा दिए गए लाभान्श को कर से छूट देते हैं या उस दर को सीमित करते हैं जिस पर लाभान्श पर कर लगाया जा सकता है, बशर्ते लाभार्थी मालिक या प्राप्तकर्ता वह कंपनी है जो दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार की निवासी है और लाभान्श का भुगतान करने वाली कंपनी की पूंजी, शेयर, स्टॉक, वोटिंग पावर, वोटिंग अधिकार, या समान स्वामित्व हितों की एक निश्चित राशि से अधिक की मालिक, धारक या नियंत्रक है, केवल तभी लागू होंगे यदि उन प्रावधानों में वर्णित स्वामित्व की शर्तें 365 उस दिन की अवधि के दौरान पूरी की जाती हैं जिसमें लाभान्श के भुगतान का दिन शामिल होता है (शेयर धारक या लाभान्श देने वाली कंपनी के उस अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए, स्वामित्व के उन परिवर्तनों का कोई भी खाता नहीं रखा जाएगा जो सीधे कॉर्पोरेट पुनर्गठन के परिणामस्वरूप होगा, जैसे विलय या विभाजन वाले पुनर्गठन)।
2. पैराग्राफ 1 में दी गई न्यूनतम धारण की अवधि पैराग्राफ 1 में वर्णित समाहित कर समझौते के प्रावधानों में न्यूनतम धारण की अवधि की अनुपस्थिति में या उसके स्थान पर लागू होगी।
3. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:
 - क) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए;
 - ख) सम्पूर्ण रूप से यह अनुच्छेद उसके समाहित कर समझौतों पर उस सीमा तक लागू न हो जब पैराग्राफ 1 में वर्णित प्रावधानों में ये पहले से ही शामिल हों:
 - i) न्यूनतम धारण अवधि;
 - ii) 365 दिनों की अवधि से कम न्यूनतम धारण अवधि
 - iii) 365 दिनों की अवधि से अधिक न्यूनतम धारण अवधि
4. प्रत्येक पार्टी, जिसने पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यास को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके सम्मिलित कर करार के प्रत्येक में इस पैराग्राफ में वर्णित उपबंध निहित है 1 जो पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ ख) में वर्णित आरक्षण के अधीन नहीं है, और यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक प्रावधान का अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या। पैराग्राफ 1 समाहित कर समझौते के प्रावधान के सम्बंध में केवल वहाँ लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस प्रावधान के सम्बंध में ऐसी एक अधिसूचना की है।

अनुच्छेद 9 - मुख्यतः अचल सम्पत्ति से अपना मूल्य हासिल करने वाली संस्थाओं के शेयरों अथवा हितों की बिक्री से पूंजीगत लाभ

1. यह प्रावधान करने वाले किसी समाहित कर समझौते के प्रावधान कि किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा शेयरों की बिक्री या किसी संस्था में भागीदारी के अन्य अधिकारों से प्राप्त लाभों पर दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर लगाया जा सकता है, बशर्ते इन शेयरों या अधिकारों के मूल्य का एक निश्चित हिस्से से अधिक उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में स्थित अचल सम्पत्ति (वास्तविक संपत्ति) से प्राप्त किया गया हो (या बशर्ते उस संस्था की संपत्ति का एक निश्चित भाग से अधिक ऐसी अचल संपत्ति (वास्तविक संपत्ति) से हो):

- क) लागू होगा यदि संगत मूल्य सीमा बिक्री से पूर्व 365 दिनों के दौरान किसी भी समय प्राप्त की जाती है; तथा

ख) शेयरों अथवा तुल्य हितों, पहले ही प्रावधानों में सम्मिलित किन्हीं शेयरों अथवा अधिकारों के अलावा भागीदारी या न्यास में हितों जैसे, पर लागू होगा।

2. पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ क) में दी गई अवधि, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पैराग्राफ 1 में वर्णित किसी समाहित कर समझौते के प्रावधानों में संगत मूल्य सीमा का पालन किया गया था, उस समयावधि के स्थान पर या उसकी अनुपस्थिति में लागू होगी।

3. कोई पक्षकार उसके समाहित कर समझौते के सम्बंध में पैराग्राफ 4 लागू करना भी चुन सकता है।

4. समाहित कर समझौते के उद्देश्यों के लिए, किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा शेयरों या किसी साझेदारी या न्यास में हितों जैसे तुलनीय हितों की बिक्री से प्राप्त किए गए लाभों पर दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर लगाया जा सकता है, यदि बिक्री से पूर्व 365 दिनों के दौरान किसी भी समय, ये शेयर या तुलनीय हित उनके मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में स्थित अचल संपत्ति (वास्तविक संपत्ति) से प्राप्त करते हैं।

5. पैराग्राफ 4 यह प्रावधान करने वाले किसी समाहित कर समझौते के प्रावधान कि किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा शेयरों की बिक्री या किसी संस्था में भागीदारी के अन्य अधिकारों से प्राप्त लाभों पर दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर लगाया जा सकता है, बशर्ते इन शेयरों या अधिकारों के मूल्य का एक निश्चित हिस्से से अधिक उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में स्थित अचल संपत्ति (वास्तविक संपत्ति) से प्राप्त किया गया हो (या बशर्ते उस संस्था की संपत्ति का एक निश्चित भाग से अधिक ऐसी अचल संपत्ति (वास्तविक संपत्ति) से हो), की अनुपस्थिति में या उनके स्थान पर लागू होंगे।

6. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:

क) उसके समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 1 लागू न हो;

ख) उसके समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 1 का उप-पैराग्राफ क) लागू न हो;

ग) उसके समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 1 का उप-पैराग्राफ ख) लागू न हो;

घ) उसके उन समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 1 का उप-पैराग्राफ क) लागू न करने के लिए जिनमें पैराग्राफ 1 में वर्णित प्रकार का प्रावधान पहले से ही है जिसमें यह निर्धारित करने के लिए वह अवधि पहले से ही शामिल है कि क्या संगत मूल्य सीमा का पालन किया गया था;

ड.) उसके उन समाहित कर समझौतों पर पैराग्राफ 1 का उप-पैराग्राफ ख) लागू न करने के लिए जिनमें पैराग्राफ 1 में वर्णित प्रकार का प्रावधान पहले से ही है जो शेयरों को छोड़कर हितों की बिक्री पर लागू हो;

च) उसके उन समाहित कर समझौतों पर जिनमें पैराग्राफ 5 में निर्धारित प्रावधान पहले से ही समाहित हो, वहां पैराग्राफ 4 लागू न हो;

7. प्रत्येक पक्षकार जिसने पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है वह निक्षेपागार को यह अधिसूचित करेगा कि क्या उसके प्रत्येक समाहित कर समझौते में पैराग्राफ 1 में वर्णित प्रावधान शामिल है, और यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक प्रावधान का अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या। पैराग्राफ 1 समाहित कर समझौते के प्रावधान के सम्बंध में केवल वहाँ लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस प्रावधान के सम्बंध में ऐसी एक अधिसूचना की है।

8. प्रत्येक पक्षकार जो पैराग्राफ 4 लागू करना चुनता है वह निक्षेपागार को अपने चुनाव के सम्बंध में अधिसूचित करेगा। पैराग्राफ 4 समाहित कर समझौते पर केवल वहाँ लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने ऐसी एक अधिसूचना की है। ऐसे मामले में, उस समाहित कर समझौते के सम्बंध में पैराग्राफ 1 लागू नहीं होगा। ऐसे पक्षकार के मामले में जिसने पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ च) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है तथा पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण किया है, ऐसी अधिसूचना में इसके ऐसे समाहित कर समझौतों की सूची भी शामिल होगी जिनमें पैराग्राफ 5 में वर्णित प्रावधान तथा ऐसे प्रत्येक प्रावधान का अनुच्छेद एवं पैराग्राफ संख्या समाहित हो। जहाँ पैराग्राफ 7 अथवा इस पैराग्राफ के तहत किसी समाहित कर समझौते के प्रावधान के सम्बंध में सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने ऐसी एक अधिसूचना की है, उस प्रावधान को पैराग्राफ 4 के प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। अन्य मामलों में, पैराग्राफ 4 समाहित कर समझौते के प्रावधानों को केवल उस सीमा तक हटा देगा जहां तक वे प्रावधान पैराग्राफ 4 के साथ विसंगत हों।

अनुच्छेद 10 - तीसरे क्षेत्राधिकार में स्थित स्थायी संस्थापनों के लिए दुरुपयोग नियम

1. जहां:

- क) सम्मिलित कर के संविदाकारी क्षेत्राधिकार का उपक्रम दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार से आय प्राप्त करता है तथा प्रथमोल्लिखित क्षेत्राधिकार ऐसी आय को तीसरे क्षेत्राधिकार में स्थित उपक्रम के स्थायी संस्थापन को आरोप्य के रूप में माना जाता है; और
- ख) उस स्थायी संस्थापन को आरोप्य लाभों को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर से छूट है,

सम्मिलित कर करार के लाभ आय की किसी मद को लागू नहीं होंगे जिन पर तीसरे क्षेत्राधिकार में कर उस कर के 60 प्रतिशत से कम है जिसे आय की उस मद पर प्रथमोल्लिखित क्षेत्राधिकार में लगाया जा सकेगा यदि वह स्थायी संस्थापन प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार में स्थित थे। ऐसे मामले में, कोई आय, जिस पर इस पैराग्राफ के उपबंध लागू होते हैं, सम्मिलित कर करार के किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के घरेलू कानूनों के अनुसार करयोग्य रहेंगे।

2. पैराग्राफ 1 लागू नहीं होगा यदि आय पैराग्राफ 1 में वर्णित दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार से प्राप्त की गई और उसे स्थायी संस्थापन के जरिए किए गए बिजनेस के सक्रिय चलाने से संबंधित है अथवा प्रासंगिक है (निर्माण, प्रबंधन अथवा साधारणतः उपक्रम के स्वयं के खाते के लिए निवेश धारण करने के बिजनेस को छोड़कर जब तक कि ये कार्यकलाप बैंक, बीमा उपक्रम अथवा पंजीकृत प्रतिभूति वितरकों द्वारा चलाए गए क्रमशः बैंकिंग, बीमा अथवा प्रतिभूति कार्यकलाप हैं।

3. यदि संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा प्राप्त आय की मद के बारे में पैराग्राफ-1 के अनुसार सम्मिलित कर करार के अन्तर्गत लाभों को मना किया जाता है तो दूसरे संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी फिर भी, आय की उस मद के बारे में इन लाभों को प्रदान कर सकते हैं यदि ऐसे निवासी द्वारा अनुरोध की प्रतिक्रिया में ऐसे सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि ऐसे लाभ प्रदान करना उन कारणों को देखते हुए तर्कसंगत है कि ऐसा निवासी ने पैराग्राफ 1 तथा 2 की जरूरतों की संतुष्टि नहीं की। संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी, जिसको दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासी द्वारा पूर्व वाक्य के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, या तो अनुरोध मंजूर करने से पूर्व अथवा मना करने से पूर्व उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी के साथ विचार विमर्श करेगा।

4. सम्मिलित कर करार के प्रावधानों के स्थान पर अथवा इसकी अनुपस्थिति में पैराग्राफ 3 के जरिए पैराग्राफ 1 लागू होगा जो लाभों को मना करता है अथवा सीमित करता है जो अन्यथा संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उपक्रम को प्रदान किए जा सकेंगे जो तीसरे क्षेत्राधिकार में स्थित उपक्रम के स्थायी संस्थापन को आरोप्य हैं।

5. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:

- क) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए;
- ख) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए जो पहले ही पैराग्राफ 4 में वर्णित उपबंध रखते हैं;
- ग) यह अनुच्छेद केवल इसके सम्मिलित कर करार के लिए ही लागू होगा जो पहले ही पैराग्राफ - 4 में वर्णित उपबंध रखते हैं।

6. प्रत्येक पक्ष, जिसने पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ क) अथवा ख) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यासी को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके सम्मिलित कर करार में से प्रत्येक में पैराग्राफ-4 में वर्णित उपबंध निहित होते हैं और यदि हां तो प्रत्येक ऐसे उपबंध का अनुच्छेद तथा पैराग्राफ संख्या। जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने सम्मिलित कर करार के उपबंध के बारे में ऐसी अधिसूचना बनाई है, तो उस उपबंध को पैराग्राफ 3 के माध्यम से पैराग्राफ 1 के उपबंधों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दूसरे मामलों में पैराग्राफ 3 के माध्यम से पैराग्राफ 1 केवल उस सीमा तक सम्मिलित कर करार के प्रावधानों का स्थान लेंगे कि वे उपबंध उन पैराग्राफों के साथ असंगत हैं।

अनुच्छेद 11 - किसी पक्ष द्वारा अपने ही निवासी पर कर लगाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कर समझौते की प्रयोज्यता

1. सम्मिलित कर करार अपने निवासियों के संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों को छोड़कर कराधान को प्रभावित नहीं करेगा:

- क) जिसमें अपेक्षा होती है कि उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उपक्रम को दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा किए गए प्रारंभिक समायोजन के अनुपालन में संविदाकारी क्षेत्राधिकार एक सहसंबंध अथवा तदनुरूपी समायोजन है, सम्मिलित कर करार के अनुसार उपक्रम के स्थायी संस्थापन के लाभों अथवा संबद्ध उपक्रम के

लाभों पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार में प्रभारित कर की राशि है;

- ख) जो यह प्रभावित कर सकती है कि कैसे वह संविदाकारी क्षेत्राधिकार वैयक्तिक पर कर लगाता है जो उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार का निवासी है यदि वह व्यक्ति दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार को अथवा राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा उसकी अन्य सक्षम निकाय को प्रदान की गई सेवाओं के बारे में आय प्राप्त करता है;
- ग) जो यह प्रभावित कर सकती है कि कैसे वह संविदाकारी क्षेत्राधिकार किसी व्यक्ति पर कर लगाता है जो उस संविदाकारी क्षेत्र का निवासी है यदि वह व्यक्ति एक विद्यार्थी, बिजनेस नौसिखिया अथवा प्रशिक्षु, अथवा अध्यापक, प्रोफेसर, वक्ता (लेक्चरर), प्रशिक्षक, अनुसंधानकर्ता अथवा अनुसंधान स्कॉलर भी है जो सम्मिलित कर करार की शर्तों को पूरा करता है;
- घ) जिसमें उपेक्षा होती है कि उस आय के बारे में उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासियों को कर क्रेडिट अथवा कर छूट प्रदान करने के लिए संविदाकारी क्षेत्राधिकार कि दूसरा संविदाकारी क्षेत्राधिकार सम्मिलित कर करार के अनुसरण में (उन लाभों सहित जो सम्मिलित कर करार के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में स्थित स्थायी संस्थापन को आरोप्य हैं);
- ङ.) जो उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा कुछ विभेदकारी कराधान पद्धतियों के विरुद्ध उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासियों का संरक्षण करती है;
- च) जो उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के निवासियों को यह अनुरोध करने की अनुमति देती है कि उस अथवा संविदाकारी क्षेत्राधिकार में से किसी के भी सक्षम प्राधिकारी कराधान के मामलों पर विचार करते हैं जो सम्मिलित कर करार के अनुसार नहीं है;
- छ) जो यह प्रभावित कर सकती है कि कैसे वह संविदाकारी क्षेत्राधिकार उस व्यक्ति पर कर लगाता है जो उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार का निवासी है जब वह व्यक्ति कूटनीतिक मिशन, सरकारी मिशन अथवा दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के काउंसलर पद का सदस्य है;
- ज) जो यह व्यवस्था करती है कि दूसरे संविदाकारी क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा विधान के अंतर्गत किए गए पेंशन अथवा अन्य भुगतान उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में ही कराधेय होंगे;
- झ) जो यह व्यवस्था करती है कि दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में होने वाले पेंशन अथवा इसी प्रकार के भुगतान, वार्षिक वृत्ति, निर्वाह व्यय भुगतान अथवा दूसरे परिरक्षण भुगतान उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में ही कराधेय होंगे; अथवा
- ञ) जो अन्यथा एक संविदाकारी क्षेत्राधिकार को अपने स्वयं के निवासियों को कर लगाने के अधिकार को स्पष्ट रूप से सीमित करती है अथवा उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से व्यवस्था करती है जिसमें आने वाली आय की मद उस आय की मद पर कर लगाने का विशेष अधिकार रखती है।

2. पैराग्राफ 1 यह बताते हुए सम्मिलित कर करार के उपबंध के स्थान पर अथवा इसकी अनुपस्थिति में लागू होगा कि सम्मिलित कर करार संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा इसके निवासियों के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा।

3. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:

- क) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए;
- ख) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए जो पहले ही पैराग्राफ 2 में वर्णित उपबंध रखते हैं।

4. प्रत्येक पक्ष, जिसने पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ क) अथवा ख) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यासी को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके सम्मिलित कर करार में से प्रत्येक में पैराग्राफ 2 में वर्णित उपबंध निहित होते हैं और यदि हां तो प्रत्येक ऐसे उपबंध का अनुच्छेद तथा पैराग्राफ संख्या। जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने सम्मिलित कर सम्बंधी करार के प्रावधान के संबंध में ऐसी एक अधिसूचना की है, वह प्रावधान पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित जाएगा। अन्य मामलों में, पैराग्राफ 1 शामिल कर समझौते के प्रावधानों को केवल उस सीमा तक अधिक्रमित करेगा, कि वो प्रावधान पैराग्राफ 1 से असंगत हैं।

भाग IV.**स्थायी स्थापना दर्जे का परिहार****अनुच्छेद 12 - आयुक्तालयीय समझौतों और इसी प्रकार की रणनीतियों के द्वारा स्थायी स्थापना दर्जे का कृत्रिम परिहार**

1. सम्मिलित कर करार के उपबंधों के होते हुए जो “स्थायी संस्थापन” पद को परिभाषित करते हैं परन्तु पैराग्राफ 2 के अधीन है, जहां एक व्यक्ति एक उपक्रम की ओर से सम्मिलित कर करार के संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कार्य कर रहा है और ऐसा कार्य करने में, आदतन संविदाओं को अंतिम रूप देता है, अथवा आदतन उन संविदाओं को अंतिम रूप देने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिसे उपक्रम द्वारा बिना सामग्री संशोधन के साधारणतः अंतिम रूप दिया जाता है और ये संविदाएं हैं:

- क) उपक्रम के नाम में; अथवा
- ख) स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए, अथवा प्रयोग के अधिकार प्रदान करने के लिए, उस उपक्रम द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति अथवा यह कि उपक्रम के पास प्रयोग करने का अधिकार है; अथवा
- ग) उस उपक्रम द्वारा सेवाओं के उपबंध के लिए,

यह कि उपक्रम को किसी कार्यकलाप के बारे में उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार को एक स्थायी संस्थापन रखना माना जाएगा जिसे वह व्यक्ति उपक्रम के लिए शुरू करता है जब तक कि ये कार्यकलाप यदि उन्हें उस संविदाकारी क्षेत्र में स्थित उस उपक्रम के बिजनेस के निश्चित स्थान के माध्यम से उपक्रम द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था, को सम्मिलित कर करार में शामिल स्थायी संस्थापन की परिभाषा के अंतर्गत स्थायी संस्थापन का गठन करना माना जाने वाले बिजनेस के उस निश्चित स्थान का कारण नहीं होंगे (जैसा कि इसे अभिसमय द्वारा संशोधित किया जा सकता है)।

2. पैराग्राफ 1 वहां लागू नहीं होगा जहां दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उपक्रम की ओर से सम्मिलित कर करार के संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करने वाला व्यक्ति एक स्वतंत्र एजेंट के रूप में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी क्षेत्राधिकार में बिजनेस जारी रखता है और उस बिजनेस के सामान्य क्रम में उपक्रम के लिए कार्य करता है। फिर भी, जहां कोई व्यक्ति विशिष्टतः अथवा लगभग विशिष्टतः एक अथवा अधिक उद्यमों की ओर से जिनसे वह करीबी रूप से जुड़ा है कामकाज करता है तो उस व्यक्ति को किसी ऐसे उद्यम के संबंध में, इस पैरा के अर्थ के भीतर एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) नहीं माना जाएगा।

3. क) पैराग्राफ 1 सम्मिलित कर करार के उपबंधों के स्थान पर लागू होगा जो उन शर्तों को वर्णित करेगा जिसके अंतर्गत एक उपक्रम को किसी कार्यकलाप के बारे में संविदाकारी क्षेत्राधिकार स्थायी संस्थापन रखना माना जाएगा (अथवा एक व्यक्ति को संविदाकारी क्षेत्राधिकार में स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा) जिसे स्वतंत्र दर्जे के एक एजेंट से अलग एक व्यक्ति उपक्रम के लिए शुरू करता है, परन्तु केवल उस सीमा तक कि ऐसे उपबंध उस स्थिति का पता लगाते हैं जिसमें ऐसा व्यक्ति उपक्रम के नाम में संविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार में एक प्राधिकारी रखता है तथा आदतन अभ्यास करता है।

ख) पैराग्राफ 2 सम्मिलित कर करार के उपबंधों के स्थान पर लागू होगा जो यह व्यवस्था करता है कि एक उपक्रम को एक कार्यकलाप के बारे में संविदाकारी क्षेत्राधिकार में स्थायी संस्थापन रखना नहीं माना जाएगा जिसे एक स्वतंत्र दर्जे का एजेंट उपक्रम के लिए शुरू करता है।

4. एक पक्ष इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं करने का अधिकार आरक्षित कर सकता है।

5. प्रत्येक पक्ष, जिसने पैराग्राफ 4 में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यासी को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके सम्मिलित कर करार में से प्रत्येक में पैराग्राफ-3 के उप पैराग्राफ ख) में वर्णित उपबंध, तथा साथ-साथ प्रत्येक ऐसे उपबंध का अनुच्छेद तथा पैराग्राफ संख्या शामिल है। पैराग्राफ 1 समाहित कर समझौते के प्रावधान के सम्बंध में केवल वहाँ लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस प्रावधान के सम्बंध में ऐसी एक अधिसूचना की है।

6. प्रत्येक पक्ष, जिसने पैराग्राफ 4 में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यासी को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके सम्मिलित कर करार में से प्रत्येक में पैराग्राफ-3 के उप पैराग्राफ ख) में वर्णित उपबंध निहित होते हैं, और साथ-साथ प्रत्येक ऐसे उपबंध का अनुच्छेद तथा पैराग्राफ संख्या। पैराग्राफ 2 सम्मिलित कर करार के उपबंध के बारे में ही लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस उपबंध के बारे में अधिसूचना बनाई है।

अनुच्छेद 13 - विनिर्दिष्ट गतिविधि ब्लॉकों के द्वारा स्थाई स्थापना दर्जों का कृत्रिम परिहार

1. एक पक्ष पैराग्राफ 2 (विकल्प ए) अथवा पैराग्राफ 3 (विकल्प बी) लागू करने अथवा किसी भी विकल्प को लागू नहीं करने का चयन कर सकता है।

विकल्प क

2. सम्मिलित कर करार के उन उपबंधों के होते हुए भी, जो “स्थायी संस्थापन” पद को परिभाषित करते हैं, पद “स्थायी संस्थापन” में इन्हें सम्मिलित होना नहीं माना जाएगा:

- क) सम्मिलित कर करार (इस अभिसमय द्वारा संशोधन से पूर्व) में विशेष रूप से सूचीबद्ध कार्यकलाप क्योंकि इन कार्यकलापों को स्थायी संस्थापन का गठन करना नहीं माना जाएगा क्या स्थायी संस्थापन दर्जा उस कार्यकलाप पर प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति वाला रहते हुए प्रासंगिक है अथवा नहीं है;
- ख) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी ऐसे कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ जिसका उपपैराग्राफ क) में वर्णन नहीं है, कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
- ग) उप पैराग्राफ क) तथा ख) में उल्लिखित कार्यकलापों के किसी संयोजन के लिए केवल बिजनेस के निश्चित स्थान का रखरखाव,

बशर्ते कि ऐसे कार्यकलाप अथवा उप पैराग्राफ ग) के मामला में बिजनेस के निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति के हैं।

विकल्प ख

3. सम्मिलित कर करार के उन उपबंधों के होते हुए भी, जो “स्थायी संस्थापन” पद को परिभाषित करते हैं, पद “स्थायी संस्थापन” में इन्हें सम्मिलित होना नहीं माना जाएगा:

क) सम्मिलित कर करार (इस अभिसमय द्वारा संशोधन से पूर्व) में विशेष रूप से सूचीबद्ध कार्यकलाप क्योंकि इन कार्यकलापों को स्थायी संस्थापन का गठन करना नहीं माना जाएगा क्या स्थायी संस्थापन दर्जा उस कार्यकलाप पर प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति वाला रहते हुए प्रासंगिक है अथवा नहीं है; इस सीमा के अलावा कि सम्मिलित कर करार का संगत उपबंध विशेष रूप से व्यवस्था करता है कि विशेष कार्यकलाप को स्थायी संस्थापन का गठन करना नहीं माना जाएगा बशर्ते कि यह कार्यकलाप प्रासंगिक अथवा सहायक प्रकृति का है;

- ख) पैराग्राफ क) में वर्णित उपक्रम किसी कार्यकलाप के लिए जारी रखने के प्रयोजनार्थ केवल बिजनेस के निश्चित स्थान का रखरखाव बशर्ते कि यह कार्यकलाप प्रासंगिक अथवा सहायक प्रकृति का है;
- ग) उपपैराग्राफ क) और ख) में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।

4. सम्मिलित कर करार का उपबंध, (जैसा इसे पैराग्राफ 2 अथवा 3 द्वारा संशोधित किया जा सकता है) जो स्थायी संस्थापन के गठन के लिए विशिष्ट कार्यकलापों का नहीं होना सूचीबद्ध करता है, बिजनेस के निश्चित स्थान को लागू नहीं होगा जिसे एक उपक्रम द्वारा प्रयोग किया गया है अथवा रखरखाव किया गया है यदि वही उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रम उसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार में उसी स्थान अथवा दूसरे स्थान पर बिजनेस कार्यकलाप जारी रखता है तथा:

- क) वह स्थान अथवा दूसरा स्थान स्थायी संस्थापन को परिभाषित करते हुए सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अंतर्गत उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रम हेतु स्थायी संस्थापन का गठन करता है; अथवा
- ख) एक ही स्थान पर दो उपक्रमों द्वारा अथवा दो स्थानों पर उसी उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रमों द्वारा किए गए कार्यकलापों के संयोजन से होने वाले समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति के नहीं हैं,

बशर्ते कि उसी स्थान पर दो उपक्रमों द्वारा अथवा दो स्थानों पर उसी उपक्रम द्वारा अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रमों द्वारा किए गए बिजनेस कार्यकलाप पूरक कार्यों का गठन करते हैं जो सशक्त बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है।

5. क) पैराग्राफ 2 अथवा 3 सम्मिलित कर करार के उपबंधों के संगत भागों के स्थान पर लागू होंगे जो उन विशिष्ट

कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें स्थायी संस्थापन गठित नहीं करना माना जाता है यहां तक कि कार्यकलाप बिजनेस के निश्चित स्थान के माध्यम से चलाया जाता है (अथवा सम्मिलित कर करार के उपबंध जो तुलनात्मक पद्धति में संचालित होते हैं)।

- ख) पैराग्राफ 4 सम्मिलित कर करार के उपबंधों को लागू होगा (जैसा कि उन्हें पैराग्राफ 2 अथवा 3 द्वारा संशोधित किया जा सकता है) जो उन विशिष्ट कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें स्थायी संस्थापन गठित नहीं करना माना जाता है यहां तक कि कार्यकलाप बिजनेस के निश्चित स्थान के माध्यम से चलाया जाता है (अथवा सम्मिलित कर करार के उपबंध जो तुलनात्मक पद्धति में संचालित होते हैं)।

6. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:

- क) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए;
- ख) इसके सम्मिलित कर करार को पैराग्राफ 2 के लिए लागू नहीं जो विशेष रूप से उल्लेख करता है कि विशेष कार्यकलापों की सूची को केवल स्थायी संस्थापन के गठन करना नहीं माना जाएगा यदि प्रत्येक कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति का है;
- ग) इसके सम्मिलित कर करार को पैराग्राफ 4 के लिए लागू नहीं

7. प्रत्येक पक्षकार जो पैराग्राफ 1 के तहत विकल्प लागू करना चुनता है वह निक्षेपागार को अपने विकल्प के चुनाव के सम्बंध में अधिसूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना में अपने उन सम्मिलित कर करारों की सूची भी शामिल होगी जो पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ क के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे उपबंध के अनुच्छेद तथा पैराग्राफ संख्या में वर्णित उपबंध रखता है। एक विकल्प सम्मिलित कर करार के उपबंध के संबंध में ही लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उसी विकल्प को लागू करने के लिए चयन किया है तथा उस उपबंध के संबंध में ऐसी अधिसूचना बनाई है।

8. प्रत्येक पार्टी, जिसने पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ क) अथवा ग) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है और पैराग्राफ 1 के अंतर्गत एक विकल्प लागू करने के लिए चयन नहीं करता है, न्यासी को अधिसूचित करेगा कि क्या सम्मिलित कर करार का प्रत्येक करार में पैराग्राफ 5 के उपपैराग्राफ ख) के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे उपबंध के अनुच्छेद तथा पैराग्राफ सं. में वर्णित उपबंध निहित है। पैराग्राफ 4 सम्मिलित कर करार के उपबंध के बारे में ही लागू होगा जहां इस पैराग्राफ अथवा पैराग्राफ 7 के अंतर्गत सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस उपबंध के बारे में अधिसूचना बनाई है।

अनुच्छेद 14 - संविदाओं का विभाजन

1. अकेले यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या सम्मिलित कर करार के उपबंध में संदर्भित अवधि (अथवा अवधियां) जो एक समयावधि (अथवा अवधियां) निर्धारित करती है जिसके बाद विशिष्ट परियोजनाएं अथवा कार्यकलाप स्थायी संस्थापन का गठन करेंगे, बढ़ा दी गई है:

- क) जहां संविदाकारी क्षेत्राधिकार का एक उपक्रम एक स्थान पर दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कार्यकलाप जारी रखता है जो एक बिल्डिंग साइट, निर्माण परियोजना, अधिष्ठापना परियोजना अथवा दूसरे विशिष्ट परियोजना जिन्हें सम्मिलित कर करार के संगत उपबंध में वर्गीकृत किया गया है, का गठन करता है अथवा ऐसे स्थान के संबंध में पर्यवेक्षी अथवा परामर्शदायी कार्यकलाप चलाता है, सम्मिलित कर करार के उपबंध के मामला में जो ऐसे कार्यकलापों का संदर्भ लेता है तथा ये कार्यकलापों को एक अथवा एक से ज्यादा अवधि के दौरान चलाया जाता है समुच्चय में सम्मिलित कर करार के संगत उपबंध में संदर्भित अवधि अथवा अवधियों को बढ़ाए बिना 30 दिन तक बढ़ जाती है; तथा
- ख) जहां संबंधित कार्यकलाप उसी बिल्डिंग साइट, परियोजना का निर्माण अथवा अधिष्ठापना, स्थित उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में अथवा विभिन्न समयावधि के दौरान सम्मिलित कर करार के संगत उपबंध में वर्गीकृत दूसरे स्थान में (अथवा जहां पर्यवेक्षी अथवा परामर्शी कार्यकलाप के संबंध में सम्मिलित कर करार के संगत उपबंध) चलाए जाते हैं तो प्रथमोल्लिखित उपक्रम से घनिष्ठ रूप से संबंधित एक अथवा एक से अधिक उपक्रमों द्वारा प्रत्येक में 30 दिन बढ़ जाते हैं,

ये विभिन्न समयावधियां समुच्चय समयावधि में जोड़ी जाएंगी जिसके दौरान प्रथमोल्लिखित उपक्रम ने उस बिल्डिंग साइट, परियोजना के निर्माण अथवा अधिष्ठापना अथवा सम्मिलित कर करार के संगत उपबंध में वर्गीकृत दूसरे स्थान पर कार्यकलाप चलाए हैं।

2. पैराग्राफ 1 उस सीमा तक सम्मिलित कर करार के उपबंधों के स्थान पर अथवा इसकी अनुपस्थिति में लागू होगा कि ऐसे उपबंध पैराग्राफ 1 में वर्णित विशिष्ट परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए संस्थापन की मौजूदगी के संबंध में समयावधि अथवा अवधियों के अनुप्रयोग से बचने के लिए संविदाओं के डिविजन का बहु भागों में पता लगाते हैं।
3. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:
 - क) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए;
 - ख) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा दोहन के संबंध में इसके सम्मिलित कर करार के उपबंधों के संबंध में लागू नहीं करने के लिए।
4. प्रत्येक पार्टी, जिसने पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यास को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके सम्मिलित कर करार के प्रत्येक में इस पैराग्राफ में वर्णित उपबंध निहित है 2 जो पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ ख) के अंतर्गत आरक्षण के अध्यधीन नहीं है और यदि हां तो प्रत्येक ऐसे उपबंध की मद तथा पैराग्राफ संख्या। जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने सम्मिलित कर करार के उपबंध के बारे में ऐसी एक अधिसूचना बना ली है तो उस उपबंध को पैराग्राफ 2 में प्रदान की गई सीमा तक पैराग्राफ 1 के उपबंधों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अन्य मामलों में, पैराग्राफ 1 शामिल कर समझौते के प्रावधानों को केवल उस सीमा तक अधिक्रमित करेगा, कि वो प्रावधान पैराग्राफ 1 से असंगत हैं।

अनुच्छेद 15 - उपक्रम से घनिष्ठ रूप से संबंधित व्यक्ति की परिभाषा

1. सम्मिलित कर करार के उप उपबंधों के प्रयोजनार्थ जिन्हें अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 (आयुक्तालयीय करारों तथा इसी तरह की रणनीतियों के जरिए स्थायी संस्थापन दर्जे का कृत्रिम परिहार), अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4 (विशिष्ट कार्यकलाप छूट के माध्यम से स्थायी संस्थापन दर्जे का कृत्रिम परिहार) अथवा अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 1 (संविदाओं का विभाजन) द्वारा संशोधित किया गया है, एक व्यक्ति एक उपक्रम से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों पर आधारित एक व्यक्ति का दूसरे पर नियंत्रण है अथवा दोनों व्यक्ति उपक्रम के उसी व्यक्ति के नियंत्रणाधीन है। किसी भी सूरत में, किसी व्यक्ति को किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि वह प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित रखता है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है) अथवा यदि अन्य किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति तथा उस उद्यम में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है)।
2. एक पार्टी जिसने अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 4 (आयुक्तालयीय करारों तथा इसी प्रकार की रणनीतियों के माध्यम से स्थायी संस्थापन दर्जे का कृत्रिम परिहार), अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ क) अथवा ग) (विशेष कार्यकलाप छूट के माध्यम से स्थायी संस्थापन दर्जे का कृत्रिम परिहार) तथा अनुच्छेद-14 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ क) (संविदाओं का विभाजन) में वर्णित आरक्षण किए हैं तो वह पार्टी सम्मिलित कर करार को लागू नहीं करने के लिए इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए अधिकार आरक्षित कर सकती है जिसे ये आरक्षण लागू होते हैं।

भाग V.

विवाद समाधान में सुधार करना

अनुच्छेद 16 - पारस्परिक करार की विधि

1. जहां एक व्यक्ति विचार करता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों की कार्यवाही से उस व्यक्ति के लिए सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अनुसार कराधान में फल आता है अथवा फल आएगा तो वह व्यक्ति उन संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के घरेलू कानून द्वारा प्रदान किए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना मामला को किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। इस मामले को उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के समाहित कर उपबंधों के अनुरूप नहीं है।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस समाहित कर करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी करार को संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।

3. इस समाहित कर करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाई अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस समाहित कर करार में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. क) i) पैराग्राफ 1 का प्रथम वाक्य सम्मिलित कर करार (अथवा इसके भागों) के उपबंधों के स्थान पर अथवा अनुपस्थिति में लागू होगा जो व्यवस्था करता है कि जहां एक व्यक्ति विचार करता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों की कार्यवाही से उस व्यक्ति के लिए सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अनुसार कराधान में फल आता है अथवा फल आएगा तो वह व्यक्ति उन संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के घरेलू कानून द्वारा प्रदान किए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना मामले को उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह व्यक्ति निवासी है, उन उपबंधों सहित जिसके तहत यदि उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला राष्ट्रीयता पर आधारित गैर भेदभाव से संबंधित सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अंतर्गत आता है, तो मामले को उस संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसका वह व्यक्ति राष्ट्रिक है।

ii) पैराग्राफ 1 का दूसरा वाक्य एक सम्मिलित कर करार के उपबंधों के स्थान पर लागू होगा जो व्यवस्था करता है कि पैराग्राफ 1 के प्रथम वाक्य में बताया गया मामला विशिष्ट समयावधि के भीतर, जो कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्ष से कम है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके फलस्वरूप सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अनुसार अथवा उस समयावधि का वर्णन करते हुए सम्मिलित कर करार के उपबंध की अनुपस्थिति में कराधान नहीं होगा जिसके भीतर मामले को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ख) i) पैराग्राफ 2 का प्रथम वाक्य सम्मिलित कर करार के उपबंधों की अनुपस्थिति में लागू होगा जो व्यवस्था करता है कि सक्षम प्राधिकारी जिसे पैराग्राफ 1 में संदर्भित व्यक्ति द्वारा मामले के साथ प्रस्तुत किया गया है, प्रयास करेगा, यदि आपत्ति इसके लिए उचित होना प्रतीत होती है और यदि यह दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर समझौते द्वारा मामलेको हल करने के लिए स्वयं संतोषजनक समाधान पर पहुंचने में सक्षम है ताकि कराधान का अपवंचन हो सके जो सम्मिलित कर करार के अनुसार नहीं है।

ii) पैराग्राफ 2 का दूसरा वाक्य यह व्यवस्था करते हुए सम्मिलित कर करार के उपबंधों की अनुपस्थिति में लागू होगा कि किया गया कोई करार संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के घरेलू कानून में किसी समय सीमा के होते हुए क्रियान्वित किया जाएगा।

ग) i) पैराग्राफ 3 का प्रथम वाक्य सम्मिलित कर करार के उपबंधों की अनुपस्थिति में लागू होगा जो व्यवस्था करता है कि संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी सम्मिलित कर करार की व्याख्या करने अथवा अनुप्रयोग करने में होने वाली किसी कठिनाई अथवा संदेह को परस्पर समझौते द्वारा समाधान करने का प्रयास करेंगे।

ii) पैराग्राफ 3 का दूसरा वाक्य सम्मिलित कर करार के उपबंधों की अनुपस्थिति में लागू होगा जो व्यवस्था करता है कि संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी सम्मिलित कर करार में व्यवस्था नहीं किए गए मामलों में दोहरे कराधान का लोप करने के लिए साथ-साथ परामर्श कर सकते हैं।

5. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:

क) इस आधार पर इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं करने के पैराग्राफ 1 के प्रथम वाक्य के लिए कि इसका आशय यह सुनिश्चित करते हुए ओईसीडी/जी 20बीईपीएस पैकेज के अंतर्गत विवाद समाधान सुधारने के लिए न्यूनतम मानदण्ड पूरा करना है कि इसके प्रत्येक सम्मिलित कर करार के अंतर्गत (उस सम्मिलित कर करार को छोड़कर जो एक व्यक्ति को किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को मामला प्रस्तुत करने की अनुमति देता है) जहां एक व्यक्ति विचार करता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों की कार्यवाही से उस व्यक्ति के लिए सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अनुसार कराधान में फल आता है अथवा फल आएगा तो वह व्यक्ति उन संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के घरेलू कानून द्वारा प्रदान किए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना मामले को उस संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह व्यक्ति निवासी है, उन उपबंधों सहित जिसके तहत यदि उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया

मामला राष्ट्रीयता पर आधारित गैर भेदभाव से संबंधित सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अंतर्गत आता है, तो मामले को उस संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसका वह व्यक्ति राष्ट्रिक है और उस संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी उन मामलों के लिए दूसरे संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के साथ द्विपक्षीय अधिसूचना तथा परामर्श प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगा जिसमें वह सक्षम प्राधिकारी, जिससे परस्पर करार प्रक्रिया मामला प्रस्तुत किया गया था, करदाता की आपत्ति को उचित होने पर विचार नहीं करता है;

- ख) इसके सम्मिलित कर करार के लागू नहीं करने के पैराग्राफ 1 के द्वितीय वाक्य के लिए जो यह व्यवस्था नहीं करता है कि पैराग्राफ 1 के प्रथम वाक्य में संदर्भित मामला इस आधार पर विशिष्ट समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि इसका आशय यह सुनिश्चित करते हुए ओईसीडी/जी 20 बीईपीएस पैकेज के अंतर्गत विवाद समाधान सुधारने के लिए न्यूनतम मानदण्ड पूरा करना है कि ऐसे सभी सम्मिलित कर करारों के प्रयोजनार्थ पैराग्राफ 1 में संदर्भित करदाता को कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के भीतर मामला प्रस्तुत करने की अनुमति है फलस्वरूप कराधान सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अनुसार नहीं है;

ग) इस आधार पर इसके सम्मिलित कर करारों को लागू नहीं करने के पैराग्राफ 2 के द्वितीय वाक्य के लिए कि इसके सम्मिलित कर करारों के प्रयोजनार्थ

- i) परस्पर समझौता प्रक्रिया के माध्यम से किया गया कोई करार संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के घरेलू कानून में किसी सीमा के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा; अथवा
- ii) इसका आशय इसके द्विपक्षीय संधि बातचीत में यह स्वीकार करके ओईसीडी/जी 20 बीईपीएस पैकेज के अंतर्गत विवाद समाधान सुधारने के लिए न्यूनतम मानदण्ड पूरा करना है, एक संधि उपबंध यह व्यवस्था करते हुए कि:

क) संविदाकारी क्षेत्र उन लाभों में कोई समायोजन नहीं करेंगे जो एक अवधि के बाद संविदाकारी क्षेत्राधिकारों में से एक के उपक्रम के स्थायी संस्थापन को प्राप्य हैं जिसे उस कराधेय वर्ष के अंत से दोनों संविदाकारी क्षेत्रों के बीच परस्पर सहमत हुए हैं जिसमें लाभ स्थायी संस्थापन को प्राप्य हो गए होंगे (यह उपबंध जालसाजी, घोर उपेक्षा अथवा जानबूझकर गलती के मामले में लागू नहीं होगा); तथा

ख) एक उपक्रम के लाभों में संविदाकारी क्षेत्र शामिल नहीं होंगे और तदनुसार उन लाभों पर कर लगेगा जो उपक्रम को प्राप्त होंगे परन्तु यह कि सहयोगी उपक्रम से संबंधित सम्मिलित कर करार में उपबंध में संदर्भित शर्त के कारण से ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं, उस अवधि के बाद जिस पर दोनों संविदाकारी क्षेत्रों के बीच कराधेय वर्ष के अंत से परस्पर सहमति है जिसमें लाभ उपक्रम को प्राप्त हुए होंगे (यह उपबंध जालसाजी, घोर उपेक्षा अथवा जानबूझकर गलती के मामले में लागू नहीं होगा)।

6. क) प्रत्येक पार्टी, जिसने पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ क) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यास को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके सम्मिलित कर करार के प्रत्येक में पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ क) की खण्ड (i) में वर्णित उपबंध निहित है और यदि हां, तो प्रत्येक ऐसे उपबंध की मद तथा पैराग्राफ संख्या। जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने सम्मिलित कर करार के उपबंध के बारे में ऐसी एक अधिसूचना बना ली है तो उस उपबंध को पैराग्राफ 1 के प्रथम वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दूसरे मामलों में, पैराग्राफ 1 का पहला वाक्य उस सीमा तक ही सम्मिलित कर करार के उपबंधों का स्थान लेगा जहां तक वे उपबंध उस वाक्य से असंगत हैं।

ख) प्रत्येक पार्टी जिसने पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ ख) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है तो वह न्यास को अधिसूचित करेगा:

- i) इसके सम्मिलित कर करारों की सूची जिसमें एक उपबंध निहित है जो व्यवस्था करता है कि पैराग्राफ 1 के प्रथम वाक्य में संदर्भित मामला विशिष्ट समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्ष से कम है, फलस्वरूप सम्मिलित कर करार के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे उपबंध की मद तथा पैराग्राफ संख्या के उपबंधों के अनुसार कराधान नहीं होगा; सम्मिलित कर करार के उपबंध को पैराग्राफ 1 के द्वितीय वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्रों ने उस

उपबंध के बारे में ऐसी एक अधिसूचना बनाई है; दूसरे मामलों में खण्ड ii) की शर्त के अध्याधीन पैराग्राफ 1 का द्वितीय वाक्य उस सीमा तक ही सम्मिलित कर करार के उपबंधों का स्थान लेगा कि वे उपबंध पैराग्राफ 1 के द्वितीय वाक्य से असंगत हैं।

- ii) इसके सम्मिलित कर करारों की सूची जिसमें एक उपबंध निहित है जो व्यवस्था करता है कि पैराग्राफ 1 के प्रथम वाक्य में संदर्भित मामला विशिष्ट समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से कम से कम तीन वर्ष है, फलस्वरूप सम्मिलित कर करार के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे उपबंध की मद तथा पैराग्राफ संख्या के उपबंधों के अनुसार कराधान नहीं होगा; पैराग्राफ 1 का द्वितीय वाक्य सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होगा जहां किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार ने उस सम्मिलित कर करार के बारे में ऐसी एक अधिसूचना बनाई है।

ग) प्रत्येक पार्टी न्यासी को अधिसूचित करेगी:

- i) इसके सम्मिलित कर करारों की सूची जिनमें पैराग्राफ-4 के उप पैराग्राफ ख) की खण्ड i) में वर्णित एक उपबंध निहित नहीं होता है; पैराग्राफ 2 का प्रथम वाक्य सम्मिलित कर करार को ही लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस सम्मिलित कर करार के बारे में ऐसी एक अधिसूचना बनाई है;
- ii) एक पार्टी के मामले में जिसने पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ ग) में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, इसके सम्मिलित कर करारों की सूची जिनमें पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ ख) की खण्ड ii) में वर्णित उपबंध निहित नहीं है; पैराग्राफ 2 का द्वितीय वाक्य सम्मिलित कर करार को ही लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस सम्मिलित कर करार के बारे में ऐसी एक अधिसूचना बनाई है।

घ) प्रत्येक पार्टी न्यासी को अधिसूचित करेगी:

- i) उन सम्मिलित कर करारों की सूची जिसमें पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ ग) की खण्ड i) में वर्णित उपबंध निहित नहीं होता है; पैराग्राफ 3 के प्रथम वाक्य सम्मिलित कर करार को ही लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस सम्मिलित कर करार के बारे में ऐसी एक अधिसूचना बनाई है;
- ii) इसके सम्मिलित कर करारों की सूची जिनमें पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ ग) की खण्ड ii) में वर्णित एक उपबंध निहित नहीं है; पैराग्राफ 3 का द्वितीय वाक्य उस सम्मिलित कर करार को ही लागू होगा जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस सम्मिलित कर करार के बारे में ऐसी एक अधिसूचना बनाई है।

अनुच्छेद 17 - संगत समायोजन

1. जहां संविदाकारी क्षेत्राधिकार में उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उद्यम में लाभ शामिल हैं और तदनुसार कर लगाए जाते हैं- लाभ- जिन पर दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उद्यम को दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार में कर प्रभारित किया गया है और शामिल लाभ ऐसे लाभ हैं जिन्हें प्रथम-वर्णित संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उद्यम में प्राप्त किया जाएगा अगर दो उद्यमों के बीच की गई शर्तें वें रही थीं जोकि स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनी हुई हैं, तब वह दूसरा संविदाकारी क्षेत्राधिकार उन लाभों पर इसमें प्रभारित कर की राशि का उपयुक्त समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस समाहित कर करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

2. पैराग्राफ 1 एक उपबंध के स्थान पर अथवा इसकी अनुपस्थिति में लागू होगा जिसे उस संविदाकारी क्षेत्र के उपक्रम के लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि में उपयुक्त समायोजन करने के लिए संविदाकारी क्षेत्राधिकार की जरूरत होती है जहां दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकारों में उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उपक्रम के लाभों में वे लाभ शामिल हैं तथा तदनुसार उन लाभों पर कर लगाया जाता है और इस प्रकार सम्मिलित लाभ वे लाभ हैं जिन्हें उस दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के उपक्रम को प्राप्त हुए होंगे यदि दो उपक्रमों के बीच की गई शर्तें वे रही थीं जिन्हें स्वतंत्र उपक्रमों के बीच किया गया है।

3. कोई पक्ष अधिकार आरक्षित रख सकता है:

- क) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं होने के लिए जो पहले ही पैराग्राफ 2 में वर्णित उपबंध रखते हैं;
- ख) इस अनुच्छेद की समग्रता के लिए इस आधार पर इसके सम्मिलित कर करारों को लागू नहीं करना कि इसके सम्मिलित कर करार के पैराग्राफ 2 में संदर्भित उपबंध की अनुपस्थिति में

- i) यह पैराग्राफ 1 में संदर्भित उपयुक्त समायोजन करेगा; अथवा
 - ii) इसके सक्षम प्राधिकारी परस्पर समझौता प्रक्रिया से संबंधित सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अंतर्गत मामले का समाधान करने का प्रयास करेंगे;
- ग) उस पार्टी के मामले में जिसने अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ ग) की खण्ड ii) के अंतर्गत (परस्पर समझौता प्रक्रिया) इस आधार पर इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं करने के लिए आरक्षण किया है कि इसकी द्विपक्षीय बातचीत में यह पैराग्राफ 1 में निहित किस्म के संधि उपबंध को स्वीकार करेगा, बशर्ते कि संविदाकारी क्षेत्राधिकार उस उपबंध और अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ ग) की खण्ड ii) में (परस्पर समझौता प्रक्रिया) वर्णित उपबंधों पर करार करने में सक्षम थे।

प्रत्येक पार्टी जिसने पैराग्राफ 3 में वर्णित आरक्षण नहीं किया है, न्यासी को अधिसूचित करेगा कि क्या इसके प्रत्येक सम्मिलित कर करार पैराग्राफ 2 में वर्णित उपबंध रखते हैं और यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक उपबंध का पैराग्राफ संख्या। जहां सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने सम्मिलित कर सम्बंधी करार के प्रावधान के संबंध में ऐसी एक अधिसूचना की है, वह प्रावधान पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित जाएगा। अन्य मामलों में, पैराग्राफ 1 शामिल कर समझौते के प्रावधानों को केवल उस सीमा तक अधिक्रमित करेगा, कि वो प्रावधान पैराग्राफ 1 से असंगत हैं।

भाग VI.

मध्यस्थता

अनुच्छेद 18 – भाग VI को लागू करने का विकल्प

एक पार्टी इस भाग को सम्मिलित कर करार के संबंध में लागू करने का चयन कर सकती है और न्यासी को तदनुसार अधिसूचित कर सकती है। यह भाग सम्मिलित कर करारों के संबंध में दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के संबंध में वहीं लागू होगा जहां दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने ऐसी अधिसूचना बनाई है।

अनुच्छेद 19 – अनिवार्य बाध्यकारी मध्यस्थता

1. जहां:

- क) सम्मिलित कर करार के उपबंध (जैसा कि इसे अनुच्छेद 16 (परस्पर समझौता प्रक्रिया) के पैराग्राफ 1 द्वारा संशोधित किया जा सकता है) जो व्यवस्था करता है कि एक व्यक्ति संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को मामला प्रस्तुत कर सकता है जहां वह व्यक्ति विचार करता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी क्षेत्रों की कार्रवाई के फलस्वरूप सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अनुसार उस व्यक्ति का कराधान होगा अथवा नहीं होगा (जैसा इसे अभिसमय द्वारा संशोधित किया जा सकता है), एक व्यक्ति ने इस आधार पर संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को मामला प्रस्तुत किया है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के लिए सम्मिलित कर करार (जैसा इसे अभिसमय द्वारा संशोधित किया जा सकता है) के उपबंधों के अनुसार कराधान में है; अथवा
- ख) सक्षम प्राधिकारी सम्मिलित कर करार के उपबंध के अनुसार उस मामले का समाधान करने के लिए किसी समझौते पर पहुंचने में असक्षम है (जैसा इसे अनुच्छेद 16 (परस्पर समझौता प्रक्रिया) के पैराग्राफ 2 द्वारा संशोधित किया जा सकता है)) जो व्यवस्था करता है कि सक्षम प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर समझौता से मामले का समाधान दो वर्ष की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे जो पैराग्राफ 8 अथवा 9 में संदर्भित शुरुआत तिथि को शुरू होगा, जैसा भी मामला हो, (जब तक कि संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी उस अवधि के समाप्त हो जाने से पूर्व उस मामले के बारे में भिन्न समयावधि पर सहमत हुए हों और उन्होंने उस व्यक्ति को अधिसूचित किया हो जिसने ऐसे समझौते के मामले को प्रस्तुत किया है),

मामले से होने वाली किसी अविवादित मुद्दे को यदि व्यक्ति ऐसा अनुरोध लिखित में करता है तो इसे इस भाग में वर्णित पद्धति में पैराग्राफ 10 के उपबंधों के अनुसार संविदाकारी क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमत हुए किसी निमावली अथवा प्रक्रियाओं द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. जहां एक सक्षम प्राधिकारी ने पैराग्राफ 1 में संदर्भित परस्पर समझौता प्रक्रिया को निलंबित किया है क्योंकि उन्होंने मामलों के एक अथवा अधिक के बारे में मामला न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ

ख) में प्रदान की गई अवधि रूक जाएगी जब तक कि या तो एक अंतिम निर्णय न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है अथवा मामले को निलंबित किया गया है अथवा वापिस लिया गया है। इसके अलावा, जहां एक व्यक्ति जिसने मामला प्रस्तुत किया है और सक्षम प्राधिकारी परस्पर समझौता प्रक्रिया का निलंबन करने के लिए सहमत हुआ है, और पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ ख) में प्रदान की गई अवधि बंद हो जाएगी जब तक कि निलंबन नहीं उठाया जाता है।

3. जहां दोनों सक्षम प्राधिकारी सहमत होते हैं कि मामले द्वारा सीधे प्रभावित एक व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ ख) में प्रदान की गई अवधि के प्रारंभ होने के बाद किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध की गई अतिरिक्त सामग्री सूचना समयबद्ध पद्धति में प्रदान करने में विफल हुआ है, तो पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ ख) में प्रदान की गई अवधि का उस तिथि की अवधि के समान समय के लिए विस्तार किया जाएगा जिस तक सूचना का अनुरोध किया गया था और उस तिथि को समाप्त हो रही थी जिस तक वह सूचना प्रदान की गई थी।

4. क) मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए मामलों के बारे में मध्यस्थता निर्णय पैराग्राफ 1 में संदर्भित संबंधित मामला परस्पर समझौते के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा। मध्यस्थता निर्णय अंतिम होगा।

ख) मध्यस्थता निर्णय निम्नलिखित मामलों को छोड़कर दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों को बाध्यकारी होगा:

- i) यदि मामले द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित एक व्यक्ति परस्पर समझौते को, जो मध्यस्थता निर्णय को क्रियान्वित करता है, स्वीकार नहीं करता है। ऐसे मामले में, वह मामला सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आगे और किसी विचारार्थ पात्र नहीं होगा। परस्पर समझौता, जो मामले पर मध्यस्थता निर्णय क्रियान्वित करता है, मामले द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने पर विचार किया जाएगा यदि मामले द्वारा सीधे प्रभावित, कोई व्यक्ति उस तिथि के 60 दिन के भीतर जिसको परस्पर समझौते की अधिसूचना उस व्यक्ति को भेजी जाती है किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण द्वारा विचार विमर्श करने से मध्यस्थता निर्णय को क्रियान्वित करने वाले परस्पर समझौते में समाधान किए गए सभी मामले वापिस नहीं लेता है अथवा अन्यथा उस परस्पर समझौते के साथ संगत पद्धति में ऐसे मामलों के बारे में किसी लंबित न्यायालय अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समाप्त नहीं करता है।
- ii) यदि संविदाकारी क्षेत्राधिकार के एक न्यायालय का अंतिम निर्णय बताता है कि मध्यस्थता निर्णय अवैध है। ऐसे मामले में, पैराग्राफ 1 के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु अनुरोध नहीं किए जाने पर विचार किया जाएगा और मध्यस्थता प्रक्रिया नहीं हुई होने पर (अनुच्छेद 21 (मध्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता) तथा 25 (मध्यस्थता प्रक्रिया की लागत को छोड़कर) विचार किया जाएगा। ऐसे मामले में मध्यस्थता के लिए नया अनुरोध किया जा सकता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी सहमत होते हैं कि ऐसे नए अनुरोध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- iii) यदि मामले द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति उन मामलों पर मुकदमा जारी रखता है जिनका किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण में मध्यस्थता निर्णय का क्रियान्वयन करते हुए परस्पर समझौते में समाधान किया गया था।

5. सक्षम प्राधिकारी, जो पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) में यथा वर्णित परस्पर समझौता प्रक्रिया हेतु शुरूआती अनुरोध प्राप्त करता है, तो अनुरोध प्राप्त करने के दो कलेण्डर माह के भीतर:

- क) उस व्यक्ति को अधिसूचना भेजता है जिसने मामले को प्रस्तुत किया कि यह अनुरोध प्राप्त हुआ है; तथा
- ख) दूसरे संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध की एक प्रति सहित उस अनुरोध की अधिसूचना भेजता है।

6. तीन कलेण्डर माह के भीतर जब सक्षम प्राधिकारी परस्पर समझौता प्रक्रिया के लिए अनुरोध प्राप्त करता है (अथवा दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी से उसकी एक प्रति), तो यह या तो:

- क) उस व्यक्ति को अधिसूचित करेगा जिसने मामले को प्रस्तुत किया है तथा दूसरा सक्षम प्राधिकारी जिसने मामले का वास्तविक विचार विमर्श शुरू करने के लिए जरूरी सूचना प्राप्त की है; अथवा
- ख) उस प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति से अतिरिक्त सूचना का अनुरोध भेजता है।

7. जहां पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ के अनुसार एक अथवा दोनों सक्षम प्राधिकारियों ने उस व्यक्ति से अनुरोध किया है जिसने मामले पर वास्तविक विचार विमर्श शुरू करने के लिए जरूरी अतिरिक्त सूचना के लिए मामला प्रस्तुत किया तो वह

सक्षम प्राधिकारी, जिसने अतिरिक्त सूचना के लिए अनुरोध किया, उस व्यक्ति से अतिरिक्त सूचना के प्राप्त करने के तीन कलेण्डर माह के भीतर उस व्यक्ति तथा दूसरे सक्षम प्राधिकारी में से किसी

क) को अधिसूचित करेगा कि इसने अनुरोधित सूचना प्राप्त की है; अथवा

ख) यह कि अनुरोधित सूचना में से कुछ अभी भी गायब रही है।

8. जहां किसी भी सक्षम प्राधिकारी ने पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ ख) के अनुसार अतिरिक्त सूचना का अनुरोध किया है, वहां पैराग्राफ 1 में संदर्भित प्रारंभिक तिथि इससे पूर्व की होगी:

क) वह तिथि जिसको दोनों सक्षम प्राधिकारियों ने उस व्यक्ति को अधिसूचित किया है जिसने पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ ख) के अनुसार मामला प्रस्तुत किया; तथा

ख) वह तिथि जो पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ ख) के अनुसार दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचना के बाद तीन कलेण्डर माह है।

9. जहां अतिरिक्त सूचना का पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ ख) के अनुसार अनुरोध किया गया है तो पैराग्राफ 1 में संदर्भित प्रारंभिक तिथि इससे पूर्व की होगी:

क) वह अद्यतन तिथि जिसको वह सक्षम प्राधिकारी जिसने अनुरोधित अतिरिक्त सूचना को उस व्यक्ति को अधिसूचित किया है जिसने मामला पैराग्राफ 7 के उप पैराग्राफ क) के अनुसार दूसरे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया है; तथा

ख) वह तिथि जो उस व्यक्ति से किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध की गई सभी सूचना दोनों सक्षम प्राधिकारियों ने प्राप्त की है इसके तीन कलेण्डर माह बाद है जिसने मामले प्रस्तुत किया है।

तथापि, यदि, एक अथवा दोनों सक्षम प्राधिकारी पैराग्राफ 7 के उप पैराग्राफ ख) में संदर्भित अधिसूचना भेजते हैं तो ऐसी अधिसूचना को पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ ख) के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध के रूप में माना जाएगा।

10. संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर समझौते (परस्पर समझौते के लिए प्रक्रियाओं से संबंधित संगत सम्मिलित कर करार के अनुच्छेद के अनुसार) इस भाग में निहित उपबंधों के अनुप्रयोग की पद्धति का समाधान करेंगे, जिसमें मामले का वास्तविक विचार विमर्श शुरू करने के लिए प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी हेतु जरूरी न्यूनतम सूचना शामिल है। ऐसे एक समझौते को उस तिथि से पूर्व अंतिम रूप दिया जाएगा जिस तिथि को किसी मामले में विवादित मुद्दों मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए पहले पात्र हैं तथा इसके बाद इन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

11. इसके सम्मिलित कर करारों को इस अनुच्छेद के लागू करने के प्रयोजनार्थ एक पार्टी पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ ख) में बताई गई दो वर्ष की अवधि को तीन वर्ष की अवधि से प्रतिस्थापित करने का अधिकार रखती है।

12. एक पार्टी इस अनुच्छेद के दूसरे उपबंधों के होते हुए भी इसके सम्मिलित कर करारों के बारे में लागू करने के लिए निम्नलिखित नियमों के लिए अधिकार को सुरक्षित रख सकती है:

क) पारस्परिक समझौता प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई विवादित मामला जो इस अभिसमय के द्वारा बनाई मध्यस्थता प्रक्रिया के भीतर हो यदि उस मामले पर पहले ही दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों में से किसी के न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण द्वारा निर्णय दिया जा चुका है तो उसे मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाएगा;

ख) यदि मध्यस्थता के अनुरोध के कभी भी बाद तथा मध्यस्थता पैनल के द्वारा संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा निर्णय लेने से पहले संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के किसी भी न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

अनुच्छेद 20 – मध्यस्थों की नियुक्ति

1. विभिन्न नियमों के संबंध में संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा तय किए जाने को छोड़कर, इस भाग के उद्देश्यार्थ पैराग्राफ 2 से 4 लागू होंगे।

2. किसी मध्यस्थता पैनल के सदस्यों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

क) मध्यस्थता पैनल में तीन विशेषज्ञता प्राप्त अथवा अंतरराष्ट्रीय कर मामलों में अनुभव प्राप्त सदस्य होंगे।

- ख) अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत (आदेशात्मक बाध्यकारी मध्यस्थता) मध्यस्थता के अनुरोध के 60 दिन के भीतर प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी एक पैनल सदस्य की नियुक्ति करेगा। इस तरह से नियुक्त दो पैनल सदस्य, बाद की नियुक्ति वाले सदस्य की नियुक्ति के 60 दिन के भीतर एक तीसरे सदस्य को नियुक्त किया जाएगा, जो मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार का नागरिक अथवा निवासी नहीं होगा।
- ग) मध्यस्थता पैनल में नियुक्त प्रत्येक सदस्य नियुक्ति स्वीकार करते समय तटस्थ तथा संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों, कर प्रशासन तथा वित्त मंत्रालयों तथा मामले से संबंधित सभी व्यक्तियों से स्वतंत्र होना चाहिए तथा पूरी प्रक्रिया के दौरान तटस्थ तथा स्वतंत्रता बने रहना चाहिए तथा तत्पश्चात् उसे युक्ति-युक्त अवधि तक ऐसे आचरण से बचना चाहिए जिससे कार्रवाई के संबंध में मध्यस्थों की तटस्थता अथवा स्वतंत्रता नष्ट होती प्रतीत हो।

3. किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट पद्धति तथा समय-सीमा अथवा संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा बनाई गई सहमति के भीतर मध्यस्थता पैनल के किसी सदस्य की नियुक्ति करने में विफल होने पर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के केन्द्रीय कर नीति प्रशासन के उच्चतम रैंक के अधिकारी द्वारा उस सक्षम प्राधिकारी की ओर से एक ऐसे सदस्य की नियुक्ति की जाएगी जो किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार का नागरिक नहीं है।

4. यदि मध्यस्थता पैनल के दो प्रारंभिक सदस्य द्वारा पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट पद्धति तथा समय-सीमा अथवा संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा बनाई गई सहमति के भीतर मध्यस्थता पैनल के किसी सदस्य की नियुक्ति करने में विफल होने पर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के केन्द्रीय कर नीति प्रशासन के उच्चतम रैंक के अधिकारी द्वारा उस सक्षम प्राधिकारी की ओर से एक ऐसे सदस्य की नियुक्ति की जाएगी जो किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार का नागरिक नहीं है।

अनुच्छेद 21 - मध्यस्थता कार्यवाहियों की गोपनीयता

1. इस भाग के उपबंधों तथा सूचना के विनिमयन के संबंध में संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के घरेलू कानूनों और संगत समाहित कर समझौतों के उद्देश्यार्थ मध्यस्थता पैनल के सदस्य तथा प्रत्येक सदस्य के लिए अधिकतम तीन स्टाफ (मध्यस्थता की अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से भावी मध्यस्थता की आवश्यकतानुसार) की नियुक्ति हेतु उन व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों पर विचार किया जाएगा जिनके साथ सूचना को प्रकट किया जा सकता है। मध्यस्थता पैनल अथवा भावी मध्यस्थता से प्राप्त जानकारी और मध्यस्थता पैनल से सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त होने वाली जानकारी वह सूचना मानी जाएगी जो सूचना के विनिमय तथा प्रशासनिक सहायता से संबंधित समाहित कर समझौते के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित की जा सके।

2. संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थता पैनल के सदस्य तथा उनके स्टाफ मध्यस्थता प्रक्रिया में कार्य करने से पूर्व लिखित में इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि वे सूचना के विनिमय तथा प्रशासनिक सहायता से संबंधित समाहित कर समझौते तथा संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के लागू होने वाले कानूनों के उपबंधों की सुसंगतता के अनुसार ही मध्यस्थता कार्यवाई से संबंधित जानकारी का प्रयोग करें।

अनुच्छेद 22 - मध्यस्थता के निष्कर्ष से पहले मामले का निपटान

इस भाग के प्रयोजनों के लिए और संबंधित कवर समझौते के प्रावधानों के लिए जो आपसी समझौते के माध्यम से मामलों के समाधान के लिए प्रदान करते हैं, एक मामले के संबंध में आपसी समझौते की प्रक्रिया, साथ ही साथ मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, यदि, मध्यस्थता के लिए अनुरोध किए जाने के बाद किसी भी समय और मध्यस्थता पैनल ने अनुबंध के अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारियों को पहले अपना निर्णय दिया है:

- क) यदि उस मामले के निपटान अथवा वह व्यक्ति जो मामले को लेकर आया मध्यस्थता के अनुरोध अथवा पारस्परिक समझौता कार्रवाई को वापस ले लेता है; या
- ख) और संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक रूप से सहमत होते हुए संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने से पहले इस बाबत एक अनुरोध करते हैं।

अनुच्छेद 23 - मध्यस्थता प्रक्रिया के प्रकार

1. विभिन्न नियमों के संबंध में उस सीमा तक जहां तक संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हो, को छोड़कर, इस भाग के अनुपालनार्थ किसी मध्यस्थता कार्यवाई में निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- क) मध्यस्थता पैनल के समक्ष किसी मामले के प्रस्तुत किए जाने के बाद, प्रत्येक क्षेत्राधिकार के सक्षम

प्राधिकारी, समझौते में निर्धारित समय-सीमा में मध्यस्थता पैनल को एक प्रस्तावित समाधान प्रस्तुत करेंगे जो संबंधित मामले के सभी विवादित मसलों का समाधान करता हो (संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच उस मामले से जुड़े सभी पिछले समझौतों को ध्यान में रखते हुए)। प्रस्तावित समाधान केवल किसी धनराशि-विशिष्ट के निपटान तक सीमित होगा (उदाहरण के लिए आय अथवा व्यय) अथवा जहां निर्दिष्ट हो, प्रत्येक समायोजन तथा इसी प्रकार के मसलों के लिए समाहित कर समझौते के अनुपालनार्थ भारत कर की अधिकतम दर। ऐसे मामले, जिसमें संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी संगत समाहित कर समझौते (तत्पश्चात 'श्रीशेल्ड प्रश्न' के रूप में संदर्भित) के किसी उपबंध के लागू होने के संबंध में पारस्परिक सहमति नहीं बना पाते, जैसे कि क्या कोई व्यक्ति निवासी है अथवा क्या कोई स्थाई स्थापना मौजूद है, तो उस मामले के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एक वैकल्पिक समाधान का प्रस्ताव कर सकते हैं, जो उस श्रीशेल्ड प्रश्न के समाधान हेतु आवश्यक हो।

- ख) प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकारी का सक्षम प्राधिकारी मध्यस्थता पैनल के विचारार्थ एक समर्थक स्थिति दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तावित समाधान अथवा अनुसमर्थक दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित समाधान तथा अनुसमर्थक स्थिति की देय तारीख तक अन्य सक्षम प्राधिकारी को उसकी एक प्रतिलिपि प्रदान करेगा। समझौते के द्वारा निर्धारित तारीख तक प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी मध्यस्थता पैनल को अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित समाधान तथा अनुसमर्थक दस्तावेज के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्युत्तर प्रस्तुतिकरण निर्धारित देय तारीख तक अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रदान किया जाएगा।
- ग) मध्यस्थता पैनल अपने निर्णय के रूप में प्रत्येक मामले तथा श्रेषहोल्ड प्रश्न के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित समाधान में से किसी को चुन सकता है तथा इसमें निर्णय के संबंध में कोई अन्य युक्तिसंगतता शामिल नहीं होगी। मध्यस्थता निर्णय को पैनल सदस्यों के साधारण बहुमत से अपनाया जाएगा। मध्यस्थता पैनल संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों को लिखित में अपना निर्णय सौंपेगा। मध्यस्थता निर्णय को किसी पूर्ववर्ती उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. समाहित का समझौतों के संबंध में इस अनुच्छेद के क्रियान्वयन करने के संबंध में कोई भी पक्ष पैराग्राफ 1 का अधिकार संरक्षित कर सकता है कि उसे समाहित कर समझौतों पर नहीं लागू किया जाएगा। ऐसे मामले में, उस सीमा को छोड़कर जहां तक विभिन्न नियमों के संबंध में संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक रूप से सहमत हो, मध्यस्थता कार्यवाई के संबंध में निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- क) मध्यस्थता हेतु मामले के प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी मध्यस्थता निर्णय हेतु आवश्यक प्रत्येक सूचना बिना विलंब किए सभी पैनल सदस्यों को मुहैया कराएंगे। ऐसी स्थिति को छोड़कर जब संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी राजी नहीं हो, दोनों सक्षम प्राधिकारियों के पास अनुरोध प्राप्त होने से पहले ही कोई सूचना जो, दोनों के पास उपलब्ध नहीं हो, उसे निर्णय लेने की दृष्टि से प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- ख) मध्यस्थता पैनल मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत मामले में समाहित कर समझौते के लागू उपबंधों तथा इन उपबंधों के अधीन, संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के घरेलू कानूनों के अनुसार ही निर्णय लेंगे। पैनल के सदस्य अन्य स्रोतों पर भी विचार करेंगे जिनकी संविदाकारी क्षेत्राधिकार साफ तौर पर पहचान करेंगे।
- ग) मध्यस्थता निर्णय को लिखित में संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों को सौंपा जाएगा तथा उसमें जिन कानूनों को आधार बनाया गया है तथा जिन कारणों से परिणाम सामने आया उसका उल्लेख किया जाएगा। मध्यस्थता निर्णय को पैनल सदस्यों के साधारण बहुमत से अपनाया जाएगा। मध्यस्थता निर्णय को किसी पूर्ववर्ती उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. वह पक्ष जिसने पैराग्राफ 2 में उल्लिखित आरक्षण का उपयोग नहीं किया है उसे उन पक्षों जिन्होंने ऐसा आरक्षण किया है के साथ समाहित कर समझौतों के संबंध में इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफ का लागू नहीं करने का अधिकार होगा। ऐसे मामले में प्रत्येक ऐसे समाहित कर समझौते के संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी समाहित कर समझौतों के संबंध में लागू होने वाली मध्यस्थता कार्यवाई के प्रकार पर सहमति का प्रयास करेंगे। जब तक कि ऐसा करार नहीं होता है तब तक किसी ऐसे समाहित कर समझौते के संबंध में अनुच्छेद 19 (आदेशात्मक बाध्यकारी मध्यस्थता) लागू नहीं होगी।

4. कोई पक्ष अपने समाहित कर समझौतों के संबंध में पैराग्राफ 5 का लागू होना भी चुन सकता है तथा तदनुसार न्यासी को सूचित किया जाएगा। पैराग्राफ 5 किसी ऐसे समाहित कर समझौते के संबंध में जहां संविदाकर क्षेत्राधिकारों में ऐसी अधिसूचना की है के दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों पर लागू होगा।

5. मध्यस्थता कार्रवाई के आरंभ होने से पहले, किसी समाहित कर समझौते के संविदाकारी क्षेत्राधिकारी के सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मामले को प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा उसके सलाहकार लिखित में सहमत होंगे कि वे प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी अथवा मध्यस्थता पैनल की मध्यस्थता कार्रवाई के दौरान प्राप्त सूचना का किसी को प्रकटिकरण नहीं करेंगे। समाहित कर समझौते के अंतर्गत पारस्परिक करार कार्रवाई तथा इस भाग के अंतर्गत मध्यस्थता कार्रवाई, मामलों के संबंध में समाप्त हो जाएगी, यदि मध्यस्थता का अनुरोध किए जाने तथा मध्यस्थता पैनल के संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारी को अपना निर्णय देने से पहले कभी भी यह पाया जाता है कि जिस व्यक्ति ने मामला प्रस्तुत किया था उसने या उसके किसी सलाहकार ने समझौते का उल्लंघन किया है।

6. पैराग्राफ 4 की किसी शर्त के बावजूद, उस पक्ष को जो पैराग्राफ 5 को लागू नहीं करना चाहता उसे एक अथवा अधिक चुने समाहित कर समझौतों अथवा उसके सभी समाहित कर समझौतों के संबंध में पैराग्राफ 5 लागू नहीं करने का अधिकार होगा।

7. वह पक्ष जो पैराग्राफ 5 लागू करना चाहता है उसे उन सभी समाहित कर समझौतों के संबंध में उस भाग को लागू नहीं करने का अधिकार होगा जिसके लिए पैराग्राफ 6 के अनुपालन में अन्य संविदाकारी क्षेत्राधिकार नहीं चाहते।

अनुच्छेद 24 – किसी भिन्न समाधान पर सहमति

1. किसी समाहित कर समझौते के संबंध में इस भाग को लागू करने के उद्देश्य से कोई पक्ष पैराग्राफ 2 को लागू करने का विकल्प दे सकता है तथा तदनुसार न्यासी को सूचित करेगा। दो संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के संबंध में पैराग्राफ 2 किसी ऐसे समाहित कर समझौते के संबंध में लागू होगा जिसके लिए दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकार ने कोई अधिसूचना दी है।

2. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 4 की किसी बात के बावजूद (आदेशात्मक बाध्यकारी मध्यस्थता), इस भाग के लिए कोई मध्यस्थता निर्णय किसी समाहित कर समझौते के संविदाकारी क्षेत्राधिकार पर बाध्यकारी नहीं होगा और कार्यान्वित नहीं किया जाएगा, यदि संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी मध्यस्थता निर्णय के बाद तीन कैलेंडर माह के भीतर सभी विवादित मुद्दों के लिए अलग समाधान पर राजी हो।

3. वह पक्ष जो पैराग्राफ 2 लागू करना चाहता है उसे अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 2 (मध्यस्थता कार्रवाई के प्रकार) को अपने किसी समाहित कर समझौते के संबंध में पैराग्राफ 2 को लागू करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 25 – मध्यस्थता कार्रवाई की लागत

इस भाग के अंतर्गत किसी मध्यस्थता कार्रवाई में, मध्यस्थता पैनल के सदस्यों का शुल्क तथा व्यय तथा संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के द्वारा मध्यस्थता कार्रवाई से जुड़ी अन्य कोई लागत को संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पारस्परिक रूप से तय की गई पद्धति के अनुसार वहन किया जाएगा। ऐसे किसी समझौते के नहीं होने की दशा में, प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार अपने और उसके द्वारा नियुक्त पैनल सदस्यों के व्यय का वहन करेगा। मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष का खर्च तथा मध्यस्थता कार्रवाई से जुड़े अन्य किसी कार्य का खर्च दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद 26 – समरूपता

1. अनुच्छेद 18 के अधीन (भाग VI लागू करने का विकल्प), इस भाग के उपबंध किसी ऐसे समाहित कर समझौते, जो किसी पारस्परिक कार्रवाई से उत्पन्न मसलों की मध्यस्थता का प्रावधान करते हैं, के स्थान अथवा अनुपस्थिति में लागू होंगे। इस भाग के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक पक्ष न्यासी को सूचित करेगा कि क्या, पैराग्राफ 4 अंतर्गत छूट की सीमा के प्रावधान के भीतर आने वाले उपबंधों को छोड़कर, उसके प्रत्येक समाहित कर समझौते में इस प्रकार का प्रावधान है और यदि हो तो कौन से अनुच्छेद तथा पैराग्राफ संख्या में ऐसा प्रावधान है। जहां दो संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने किसी समाहित कर समझौते के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना की है कि ऐसे प्रावधान को उन संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के बीच किए गए अनुसार उस प्रावधान को इस भाग के प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. कोई ऐसा विवादित मुद्दा जो पारस्परिक समझौता कार्रवाई से उत्पन्न हो परन्तु अन्यथा, इस भाग में की गई मध्यस्थता प्रक्रिया के अंतर्गत आता हो, उसे मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाएगा यदि वह मुद्दा ऐसे मामले के भीतर आता है द्विपक्षीय

तथा बहुपक्षीय अभिसमय के अनुसार पहले मध्यस्थता पैनल अथवा ऐसा कोई निकाय स्थापित किया गया है जो पारस्परिक समझौता कार्रवाई मामले से उत्पन्न विवादित मुद्दे हेतु आदेशात्मक बाध्यकारी मध्यस्थता के प्रावधान हेतु गठित किया गया हो।

3. पैराग्राफ 1 की शर्तों के अधीन, उन अन्य कनवेंशनों, जिनके संविदाकारी क्षेत्राधिकार पक्षकार हो अथवा पक्षकार बनने जा रहे हों, के परिणामस्वरूप किसी पारस्परिक समझौता कार्रवाई के परिपेक्ष्य में उत्पन्न विवादित मुद्दे की मध्यस्थता के संबंध में इस भाग को व्यापक दायित्व की पूर्ति हेतु अन्य कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।

प्रत्येक पक्ष को कतिपय रूप से चुने एक अथवा अधिक समाहित कर समझौतों के संबंध में उस भाग को (अथवा उसके सभी समाहित कर समझौतों) लागू नहीं करने का विकल्प होगा जिसमें किसी पारस्परिक समझौता कार्रवाई मामले से उत्पन्न विवादित मुद्दे के लिए पहले ही आदेशात्मक बाध्यकारी मध्यस्थता का प्रावधान है।

भाग VII.

अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद 27 – हस्ताक्षर तथा अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन

1. दिसंबर 31, 2016 से यह अभिसमय हस्ताक्षर हेतु निम्नलिखित सभी देशों हेतु:

- क) खुला होगा,
- ख) गुअर्नसे (यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड); आइल ऑफ मैन (यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड); जर्सी (यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड); तथा
- ग) पक्षकारों तथा हस्ताक्षरकर्ताओं के बहुमत से लिए निर्णय के द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई क्षेत्राधिकार।

2. यह अभिसमय, अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के अधीन हैं।

अनुच्छेद 28 – आरक्षण

1. पैराग्राफ 2 के अधीन, इस अभिसमय में स्पष्टतः अभिव्यक्त स्वीकृति को छोड़कर कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा।

- क) अनुच्छेद 3 का पैराग्राफ 5 (पारदर्शी संस्था)
- ख) अनुच्छेद 4 का पैराग्राफ 3 (दोहरी आवासी संस्था);
- ग) अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 8 तथा 9 (दोहरा कराधान समाप्त करने हेतु लागू की जाने वाली पद्धतियां)
- घ) अनुच्छेद 6 का पैराग्राफ 4 (समाहित कर समझौते का उद्देश्य);
- ङ.) अनुच्छेद 7 का पैराग्राफ 15 और 16 (संधि के दुरुपयोग को रोकना);
- च) अनुच्छेद 8 का पैराग्राफ 3 (लाभांश अंतरण संव्यवहार);
- छ) अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 6 (संस्थाओं को मूलतः अचल संपत्ति से हासिल मूल्य पर शेयरों अथवा हितों के हस्तांतरण से हुआ पूंजी लाभ);
- ज) अनुच्छेद 10 का पैराग्राफ 5 (तृतीय क्षेत्राधिकार में स्थित स्थाई स्थापनाओं हेतु दुरुपयोग-निरोध नियम)
- झ) अनुच्छेद 11 का पैराग्राफ 3 (किसी पक्ष द्वारा अपने ही निवासी पर कर लगाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कर समझौते की प्रयोज्यता);
- ञ) अनुच्छेद 12 का पैराग्राफ 4 (आयुक्तालयीय समझौतों और इसी प्रकार की रणनीतियों के द्वारा स्थायी स्थापना दर्जे का कृत्रिम परिहार);
- ट) अनुच्छेद 13 का पैराग्राफ 6 (विनिर्दिष्ट गतिविधि ब्लूटों के द्वारा स्थाई स्थापना दर्जे का कृत्रिम परिहार);
- ठ) अनुच्छेद 14 का पैराग्राफ 3 (संविदाओं का विभाजन);
- ड) अनुच्छेद 15 का पैराग्राफ 2 (उपक्रम से घनिष्ठ रूप से संबंधित व्यक्ति की परिभाषा);
- ढ) अनुच्छेद 16 का पैराग्राफ 5 (पारस्परिक करार की विधि);

- ण) अनुच्छेद 17 का पैराग्राफ 3 (संगत समायोजन);
- त) अनुच्छेद 19 का पैराग्राफ 11 और 12 (अनिवार्य बाध्यकारी मध्यस्थता);
- थ) अनुच्छेद 23 का पैराग्राफ 2, 3, 6, और 7 (मध्यस्थता प्रक्रिया का प्रकार);
- द) अनुच्छेद 24 का पैराग्राफ 3 (किसी भिन्न समाधान पर करार);
- ध) अनुच्छेद 26 का पैराग्राफ 4 (संगति);
- न) 35 का पैराग्राफ 6 और 7 (प्रभावी होना); और
- प) 36 का पैराग्राफ 2 (भाग VI का प्रभावी होना)।
2. क) पैराग्राफ 1 की किसी शर्त के बावजूद, वह पक्ष जो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत (भाग VI हेतु आवेदन करने का विकल्प) भाग VI (मध्यस्थता) लागू करना चुनता है वह मसलों की सीमा के संबंध में ऐसे एक या अधिक आरक्षण कर सकता है जो भाग VI (मध्यस्थता) के उपबंधों के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु पात्र होंगे। ऐसा कोई पक्ष जो इस अभिसमय का पक्षकार बनने के बाद अनुच्छेद 18 (भाग VI लागू करने का विकल्प) के अंतर्गत भाग VI (मध्यस्थता) को चुनता है तो उप पैराग्राफ के अनुपालनार्थ आरक्षण अनुच्छेद 18 (भाग VI चुनने का विकल्प) के अनुपालनार्थ न्यासी को उस पक्ष के द्वारा की गई अधिसूचना के समय दिया जाएगा।
- ख) उप पैराग्राफ क के अंतर्गत दिया आरक्षण) स्वीकृति के अधीन होगा। उप पैराग्राफ क के अंतर्गत किए गए आरक्षण) को किसी पक्ष द्वारा स्वीकृत मान जाएगा यदि उसने न्यासी द्वारा आरक्षण की अधिसूचना की तारीख से आरंभ करते हुए माह कैलेंडर माह की अवधि के अंत तक अथवा उस तारीख तक जिस पर वह अपना अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन जमा करता है, जो भी बाद में हो, ऐसे आरक्षण के संबंध में न्यासी को अपनी आपत्ति अधिसूचित नहीं करता। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत विकल्प देने वाले पक्ष के लिए (भाग VI का विकल्प देना) भाग VI (मध्यस्थता) को इस अभिसमय के पक्षकार बनने के बाद लागू करने की स्थिति में, उप पैराग्राफ क के अनुपालनार्थ अन्य पक्षों द्वारा पूर्ववर्ती आरक्षणों के प्रति आपत्ति अनुच्छेद 18 (भाग VI लागू करने का विकल्प) के अनुपालनार्थ न्यासी को प्रथमो-उल्लिखित अधिसूचना के समय की जाएगी। जहां कोई पक्ष उप पैराग्राफ क के अंतर्गत किसी आरक्षण के संबंध में कोई आपत्ति उठाता है तो भाग VI (मध्यस्थता) समग्र रूप से लागू नहीं होगा, जैसा कि आपत्तिकार तथा आरक्षणकार के बीच होता है।
3. जब तक कि इस अभिसमय के संगत उपबंधों में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, पैराग्राफ 1 अथवा 2 के अनुसार किया गया आरक्षण:
- क) अन्य पक्ष के संबंध में आरक्षणकर्ता पक्ष के लिए इस अभिसमय के वे उपबंध जिनका आरक्षण के संबंध आरक्षण की सीमा से हो, संशोधित करेगा।
- ख) आरक्षणकर्ता पक्ष के संबंध में अन्य पक्ष के लिए भी उसी सीमा तक उन उपबंधों को संशोधित करेगा।
4. किसी समाहित का समझौते पर लागू आरक्षण जो किसी ऐसे क्षेत्राधिकार अथवा प्रदेश द्वारा अथवा उसकी ओर से जिसके लिए अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ ख) तथा ग) (हस्ताक्षर तथा अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के अनुपालनार्थ वह पक्ष जिम्मेवार नहीं है, उसे एक जिम्मेवार पक्ष बनाया जाएगा और वह उस पक्ष द्वारा अपने समाहित कर समझौतों के लिए किए गए आरक्षण से भिन्न हो सकता है।
5. आरक्षण, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2, 6 तथा 9 और अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के पैराग्राफ 5 के अधीन हस्ताक्षर अथवा अनुप्रमाणन लेख-पत्र, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के समय किया जाए। तथापि, किसी ऐसे पक्ष जो इस अभिसमय के पक्षकार बनने के बाद अनुच्छेद 18 (भाग VI को चुनने का विकल्प) के अंतर्गत भाग VI (मध्यस्थता) हेतु आवेदन करता है, के संबंध में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ त), थ), द तथा ध) में उल्लिखित आरक्षण उसी समय किया जाएगा जब वह पक्ष अनुच्छेद 18 (भाग VI को चुनने का विकल्प) के अनुपालनार्थ न्यासी को अधिसूचित करता है।
6. यदि हस्ताक्षर के समय आरक्षण किया जाता है तो उसे लेख-पत्र, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के समय संपुष्ट किया जाएगा जब तक कि आरक्षण के दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं करते हो कि उसे इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2, 5 तथा 9 और अनुच्छेद 29 तथा पैराग्राफ 5 (अधिसूचनाएं) के उपबंधों के अधीन सुनिश्चित माना जाए।
7. यदि हस्ताक्षर के समय आरक्षण नहीं किया जाता है तो उस समय न्यासी को आशातीत आरक्षणों के अनंतिम सूची प्रदान

की जाएगी।

8. प्रत्येक निम्नलिखित उपबंध के अनुपालनार्थ किए गए आरक्षण हेतु अनुच्छेद 2 (शब्दावली की व्याख्या) के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) के खण्ड ii), जो संगत उपबंधों में पारिभाषित आरक्षण के दायरे में आते हैं, एक सूची (और उप पैराग्राफ सी), डी) तथा एन) में सूचीबद्ध किए गए को छोड़कर निम्नलिखित किसी उपबंध के अंतर्गत किए आरक्षण के मामले में ऐसा आरक्षण करते हुए प्रत्येक संगत उपबंध की अनुच्छेद तथा पैराग्राफ संख्या प्रदान करनी होगी।

- क) अनुच्छेद 3 (पारदर्शी संस्था) के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ ख), ग), घ), ङ.) तथा छ);
- ख) अनुच्छेद 4 (दोहरी आवासी संस्था) के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ ख), ग) तथा घ);
- ग) अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 8 तथा 9 (दोहरा कराधान समाप्त करने हेतु लागू की जाने वाली पद्धतियां)
- घ) अनुच्छेद 6 का पैराग्राफ 4 (समाहित कर समझौते का उद्देश्य);
- ङ.) अनुच्छेद 7 (संधि दुरुपयोग निवारण) का पैराग्राफ 15 का उप पैराग्राफ ख) तथा ग);
- च) अनुच्छेद 8 (लाभांश अंतरण लेन-देन) का पैराग्राफ 3 का उप पैराग्राफ ख) का खण्ड i), ii) तथा iii);
- छ) अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 6 के उपपैराग्राफ घ) ङ) और च) (संस्थाओं को मूलतः अचल संपत्ति से हासिल मूल्य पर शेयरों अथवा हितों के हस्तांतरण से हुआ पूंजी लाभ);
- ज) अनुच्छेद 10 (तृतीय क्षेत्राधिकार में स्थित स्थायी स्थापना हेतु दुरुपयोग-निरोध) का पैराग्राफ 5 का उप पैराग्राफ ख) तथा ग);
- झ) अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 का उपपैराग्राफ ख) (किसी पक्ष द्वारा अपने ही निवासी पर कर लगाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कर समझौते की प्रयोज्यता);
- ञ) अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 6 का उप पैराग्राफ ख) (विनिर्दिष्ट गतिविधि छूटों के द्वारा स्थाई स्थापना दर्जे का कृत्रिम परिहार);
- ट) अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 3 का उपपैराग्राफ ख) (संविदाओं का विभाजन);
- ठ) अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 5 का उपपैराग्राफ ख) (पारस्परिक करार की विधि);
- ड) अनुच्छेद 17 के पैराग्राफ 3 का उपपैराग्राफ ख) (संगत समायोजन);
- ढ) अनुच्छेद 23 का पैराग्राफ 6 (मध्यस्थता प्रक्रिया का प्रकार); और
- ण) अनुच्छेद 26 का पैराग्राफ 4 (संगति)

उपर्युक्त क) से ण) तक में उल्लिखित आरक्षण इस पैराग्राफ में उल्लिखित सूची में नहीं शामिल किसी समाहित कर समझौते पर लागू नहीं होगा।

9. कोई भी पक्ष जिसने पैराग्राफ 1 अथवा 2 के अनुसार कोई आरक्षण किया है उसे न्यासी को संशोधित अधिसूचना के माध्यम से उसे कभी भी वापस ले सकता है और सीमित आरक्षण से प्रतिस्थापित कर सकता है। ऐसा पक्ष अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के पैराग्राफ 6 के अनुपालन में ऐसी कोई अतिरिक्त अधिसूचना कर सकता है जो आरक्षण के वापस लेने अथवा उसके अंतःस्थापन का परिणाम है। अनुच्छेद 35 (प्रभावित होने की तारीख) के पैराग्राफ 7 के अधीन वापस लिया जाना अथवा अंतः स्थापन निम्नलिखित रूप से प्रभावित होगा:

- क) किसी समाहित कर समझौते के संबंध में उन देशों अथवा क्षेत्राधिकारों जो न्यासी को आरक्षण के वापस लेने तथा अंतः स्थापना की अधिसूचना के समय इस अभिसमय के पक्षकार हैं:
 - i) स्रोत पर विद्‌हैल्ड किए गए करों से संबंधित उपबंधों के संबंध में किया ऐसा आरक्षण उन मामलों में जिनमें न्यासी के द्वारा आरक्षण के वापस लेने अथवा अंतःस्थापन की अधिसूचना के अधिसूचित करने की तारीख से आरंभ करते हुए छः कैलेंडर माह की अवधि समाप्त के अगले वर्ष की 1 जनवरी अथवा बाद में करदेयता बनती है; तथा
 - ii) अन्य उन सभी उपबंधों के संबंध में जहां कर अवधि के संबंध में तथा करदेयता अधिसूचित करने की तारीख से आरंभ करते हुए छः कैलेंडर माह की अवधि समाप्त के अगले वर्ष की 1 जनवरी अथवा बाद में

करदेयता बनती है; तथा

- ख) किसी ऐसे समाहित कर समझौते के संबंध में जिसमें एक अथवा अधिक पक्ष आरक्षण के वापस लिए जाने अथवा अंतः स्थापना के लिए न्यासी द्वारा दी गई सूचना की तारीख में से उस बाद की तारीख को जिससे उन संविदाकारी पक्षकारों के लिए अभिसमय प्रवृत्त होता है।

अनुच्छेद 29 – अधिसूचनाएं

1. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 तथा 6 तथा अनुच्छेद 35 के पैराग्राफ 7 (प्रभावित होने की तारीख) के अधीन निम्नलिखित उपबंधों के अनुपालनार्थ की गई अधिसूचनाएं हस्ताक्षर अथवा अनुप्रमाणन लेख-पत्र, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के समय की जाएगी:

- क) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) का खण्ड ii) (शब्दावली की व्याख्या)
- ख) अनुच्छेद 3 का (पारदर्शी संस्था) पैराग्राफ 6;
- ग) अनुच्छेद 4 (दोहरी आवासी संस्था) का पैराग्राफ 4;
- घ) अनुच्छेद 5 (दोहरा कराधान समाप्त करने हेतु लागू पद्धति) का पैराग्राफ 10;
- ङ.) अनुच्छेद 6 (समाहित कर समझौते का उद्देश्य) का पैराग्राफ 5 तथा 6;
- च) अनुच्छेद 7 (संधि दुरुपयोग निवारण) का पैराग्राफ 17;
- छ) अनुच्छेद 8 का पैराग्राफ 4 (लाभांश अंतरण संव्यवहार);
- ज) अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 7 और 8 (संस्थाओं को मूलतः अचल संपत्ति से हासिल मूल्य पर शेयरों अथवा हितों के हस्तांतरण से हुआ पूंजी लाभ);
- झ) अनुच्छेद 10 (तृतीय क्षेत्राधिकारों में स्थित स्थायी स्थापनाओं हेतु दुरुपयोग निरोध नियम) का पैराग्राफ 6;
- ञ) अनुच्छेद 11 का पैराग्राफ 4 (किसी पक्ष द्वारा अपने ही निवासी पर कर लगाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कर समझौते की प्रयोज्यता);
- ट) अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 5 और 6 (आयुक्तालयीय समझौतों और इसी प्रकार की रणनीतियों के द्वारा स्थायी स्थापना दर्जे का कृत्रिम परिहार);
- ठ) अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 7 और 8 (विनिर्दिष्ट गतिविधि छूटों के द्वारा स्थाई स्थापना दर्जे का कृत्रिम परिहार);
- ड) अनुच्छेद 14 का पैराग्राफ 4 (संविदाओं का विभाजन);
- ढ) अनुच्छेद 16 का पैराग्राफ 6 (पारस्परिक करार की विधि);
- ण) अनुच्छेद 17 का पैराग्राफ 4 (संगत समायोजन);
- त) अनुच्छेद 18 (भाग VI को लागू करने का विकल्प);
- थ) अनुच्छेद 23 का पैराग्राफ 4 (मध्यस्थता प्रक्रिया का प्रकार);
- द) अनुच्छेद 24 का पैराग्राफ 1 (किसी भिन्न समाधान पर करार);
- ध) अनुच्छेद 26 का पैराग्राफ 1 (संगति); और
- न) अनुच्छेद 35 का पैराग्राफ 1, 2, 3, 5 और 7 (प्रभावी होना)।

2. किसी समाहित का समझौते के संबंध में अधिसूचनाएं जो किसी ऐसे क्षेत्राधिकार अथवा प्रदेश द्वारा अथवा उसकी ओर से जिसके लिए अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ ख) तथा ग) (हस्ताक्षर तथा अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन) के अनुपालनार्थ वह पक्ष जिम्मेवार नहीं है, उसे जिम्मेवार पक्ष द्वारा किया जाएगा और वह उस पक्ष द्वारा अपने समाहित कर समझौतों के लिए किए गए अधिसूचनाओं से भिन्न हो सकती हैं।

3. यदि हस्ताक्षर के समय अधिसूचनाएं की जाती हैं तो उन्हें लेख-पत्र, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के समय संपुष्ट किया जाएगा जब तक कि आरक्षण के दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं करते हो कि उसे इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 तथा 6

और अनुच्छेद 35 (प्रविष्टि की तारीख) का पैराग्राफ 7

4. यदि हस्ताक्षर के समय अधिसूचनाएं नहीं की जाती है तो उस समय आशातीत अधिसूचनाओं की एक अनंतिम सूची प्रदान की जाएगी।

5. कोई भी पक्ष न्यासी को संबंधित करते हुए एक अधिसूचना के माध्यम से अनुच्छेद 2 (शब्दावली की व्याख्या) के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) के खण्ड ii) के अंतर्गत अधिसूचित समझौतों की सूची का विस्तार कर सकता है। प्रत्येक पक्ष इस अधिसूचना में निर्दिष्ट करेगा कि क्या वह समझौता पार्टी द्वारा किए अनुच्छेद 28 (आरक्षण) के पैराग्राफ 8 में सूचित किसी आरक्षण के दायरे में आता है। पक्षकार अनुच्छेद 28 (आरक्षण) के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित किए आरक्षणों में नया आरक्षण भी कर सकते हैं, यदि ऐसा अतिरिक्त आरक्षण ऐसे आरक्षण के दायरे में सबसे पहले आएगा। कोई भी पक्ष पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ बी) से एस) तक के अंतर्गत अतिरिक्त समझौतों को दर्शाने के लिए कोई अतिरिक्त अधिसूचना भी विनिर्दिष्ट करेगा। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे विस्तार के कारण पहली बार किसी ऐसे क्षेत्राधिकार अथवा प्रदेश जिसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए कोई पक्ष जिम्मेवार है, के द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी कर को शामिल किया जाता है, तो वह पक्ष उस क्षेत्राधिकार अथवा प्रदेश जिसके द्वारा अथवा जिसकी ओर से 4 समाहित कर समझौते पर लागू अधिसूचना (इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अनुपालन में) अथवा अनुच्छेद 28 (आरक्षण) में आरक्षण को लागू किया जा रहा है, विनिर्दिष्ट करेगा। वह तारीख जिससे अनुच्छेद 2 (शब्दावली की व्याख्या) के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) के खण्ड ii) के अंतर्गत अधिसूचित ऐसा विस्तारित समझौता समाहित कर समझौता बन जाता है, अनुच्छेद 35 (प्रवृत्त होने की तारीख) के उपबंध उस तारीख को शासित करेंगे जिससे वह समाहित कर समझौता अशोधित होता है।

6. कोई भी पक्ष पैराग्राफ 1 के एस) के द्वारा उप पैराग्राफ ख) के अनुपालन में न्यासी को संबोधित किसी अधिसूचना के माध्यम से अतिरिक्त अधिसूचनाएं कर सकता है। ये अधिसूचनाएं निम्नलिखित रूप से प्रभावित होंगी:

- क) किसी समाहित कर समझौते के संबंध में उन देशों अथवा क्षेत्राधिकारों जो न्यासी को प्राप्त अतिरिक्त अधिसूचनाओं के समय इस अभिसमय के पक्षकार हैं।
 - i) स्रोत पर विद्वहल किए गए करों से संबंधित उपबंधों के संबंध में किया ऐसा आरक्षण उन मामलों में जिनमें की ऐसी अधिसूचना के लिए न्यासी के द्वारा सूचित अतिरिक्त सूचना की तारीख के अधिसूचित करने की तारीख से आरंभ करते हुए छः कैलेंडर माह की अवधि समाप्त के अगले वर्ष की 1 जनवरी अथवा बाद में करदेयता बनती है; तथा
 - ii) अन्य उन सभी उपबंधों के संबंध में अधिसूचनाओं जहां कर अवधि अधिसूचित करने की तारीख से आरंभ करते हुए न्यासी द्वारा सूचित अतिरिक्त अधिसूचनाओं की तारीख से छः कैलेंडर माह की अवधि समाप्ति के अगले वर्ष की 1 जनवरी अथवा बाद में करदेयता बनती है; तथा
- ख) किसी ऐसे समाहित कर समझौते के संबंध में जिसमें एक अथवा अधिक पक्ष आरक्षण के वापस लिए जाने अथवा अंतः स्थापना के लिए न्यासी द्वारा दी गई अतिरिक्त अधिसूचना की तारीख में से उस बाद की तारीख को जिससे उन संविदाकारी पक्षकारों के लिए अभिसमय प्रवृत्त होता है।

अनुच्छेद 30 – समाहित कर समझौतों में तदनुरूपी संशोधन

इस अभिसमय के उपबंध किसी ऐसे समाहित कर समझौतों में तदनुरूपी संशोधन को प्रभावित नहीं करेंगे जो समाहित कर समझौते के संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के बीच तय किए गए हों।

अनुच्छेद 31 – पक्षकारों का सम्मेलन

1. पक्षकार किसी निर्णय अथवा किसी कार्य को पूर्ण करने जो इस अभिसमय के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित अथवा उपयुक्त हो के उद्देश्य से पक्षकारों का सम्मेलन कर सकते हैं।
2. पक्षकारों के सम्मेलन को न्यासी द्वारा सर्व किया जाएगा।
3. कोई भी पक्ष न्यासी को अनुरोध सूचित करते हुए पक्षकारों के सम्मेलन का निवेदन कर सकता है। न्यासी सभी पक्षों को ऐसे किसी अनुरोध के बारे में सूचित करेगी। तत्पश्चात्, न्यासी इस शर्त के अधीन की ऐसा अनुरोध न्यासी को प्राप्त सूचना के छः कैलेंडर माह के भीतर पक्षकारों के एक-तिहाई जनमत द्वारा समर्थित हो पक्षकारों का एक सम्मेलन बुलाएगा।

अनुच्छेद 32 – व्याख्या तथा कार्यान्वयन

1. इस सम्मेलन के द्वारा संशोधित किए जाने वाले किसी समाहित कर समझौते की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन से उत्पन्न प्रश्नों का निर्धारण समाहित कर समझौते की व्याख्या तथा कार्यान्वयन के प्रश्नों के संबंध में पारस्परिक रूप से हुई सहमति के समाधानों के अनुसार किया जाएगा (क्योंकि ऐसे उपबंध इस सम्मेलन के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं)।

2. इस अभिसमय के संबंध में व्याख्या अथवा कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्नों को अनुच्छेद 31 (पक्षकारों का सम्मेलन) के पैराग्राफ 3 के अनुसार बुलाए गए पक्षकारों के सम्मेलन को संबोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 33 – संशोधन

1. कोई भी पक्ष न्यासी को संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इस अभिसमय में संशोधन प्रस्तावित कर सकता है।

2. अनुच्छेद 31 (पक्षकारों का सम्मेलन) के पैराग्राफ 3 के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने हेतु पक्षकारों का एक सम्मेलन बुलाया जा सकता है।

अनुच्छेद 34 – प्रभावी होना

1. यह अभिसमय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उसके पांचवें लेखपत्र की संपुष्टि, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के जमा किए जाने की तिथि से शुरू करके तीन कैलेंडर माह की अवधि के समाप्त होने के बाद आने वाले माह के प्रथम दिवस को लागू होगा।

2. अनुप्रमाणन के पांचवें लेख-पत्र, स्वीकृति अथवा अनुमोदन जमा करने के बाद इस अभिसमय के अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक पक्ष के लिए यह अभिसमय उस हस्ताक्षरकर्ता के अनुप्रमाणन लेख-पत्र, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के जमा करने की तारीख से आरंभ करते हुए तीन कैलेंडर माह की अवधि समाप्त होने के बाद आने वाले माह की प्रथम तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 35 – प्रभावी होना

1. इस अभिसमय के उपबंध किसी समाहित कर समझौते के संबंध में प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार में प्रभावित होंगे।

क) ऐसे करों के संबंध में जहां उन्हें स्रोत पर की गई भुगतान राशि अथवा गैर-आवासी को क्रेडिट किए जाने पर विद्दोल्ड किया जाता है, जहां ऐसा मामला समाहित कर समझौते के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार हेतु इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख के बाद की तारीख अथवा शुरू होने वाले अगले कैलेंडर वर्ष की पहली तारीख को अथवा उसके बाद का है; तथा

ख) संविदाकारी क्षेत्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले सभी अन्य करों तथा समाहित कर समझौते के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद की तारीख से छः कैलेंडर माह की अवधि (कम अवधि हेतु यदि सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकार न्यासी को ऐसी कम अवधि लागू करने के संबंध में सूचित करते हैं) की समाप्ति अथवा उसके बाद की करयोग्य अवधि के संबंध में लगाए जाने वाले कर।

2. पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) तथा पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ क) को लागू करने के लिए कोई भी पक्ष अपने उद्देश्यार्थ 'करयोग्य अवधि' के स्थान पर 'कैलेंडर वर्ष' का विकल्प दे सकता है और तदनुसार वह न्यासी को सूचित करेगा।

3. कोई भी पक्ष पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ ख) तथा पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ ख) के 'किसी अवधि की करयोग्य अवधि की करयोग्य अवधि के आरंभ होने अथवा उसके बाद में' के संदर्भ को अपने उद्देश्यार्थ 'अगले वर्ष की करयोग्य अवधि को 1 जनवरी से आरंभ अथवा उसके बाद अथवा उस अवधि की समाप्ति के पश्चात' करने को विकल्प दे सकता है तथा तदनुसार वह इसके बारे में न्यासी को सूचित करेगा।

4. इस अनुच्छेद के पिछले उपबंधों की किसी बात के बावजूद, अनुच्छेद 16 (पारस्परिक समझौता कार्रवाई) मामलों की करयोग्य अवधि के संबंध में इस अभिसमय के द्वारा किए गए संशोधनों के पूर्ववर्ती समाहित कर समझौतों के अंतर्गत उस तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य-पात्र मामलों को छोड़कर, समाहित कर समझौतों के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तत्पश्चाती तारीखों अथवा बाद में किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार को समाहित कर समझौते के संबंध में प्रस्तुत मामलों को प्रभावित करेगी।

5. अनुच्छेद 2 (शब्दावली की व्याख्या) के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) के खण्ड ii) के अंतर्गत सूचित समझौतों की सूची के अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के पैराग्राफ 5 के अनुपालन में विस्तार के परिणामस्वरूप किसी नए समाहित कर समझौते के लिए

इस अभिसमय के उपबंध प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित रूप से प्रभावित होंगे:

- क) गैर-आवासी को स्रोत पर क्रेडिट अथवा भुगतान की राशि हेतु विद्‌होल्ड किए गए कर के संबंध में, जहां ऐसी करयोग्य घटना समझौतों की सूची के विस्तार की न्यासी द्वारा की गई अधिसूचना की सूचना की तारीख के बाद 30 दिन के बाद आरंभ होने वाले अगले कैलेंडर वर्ष की प्रथम तारीख अथवा उसके बाद होती है; तथा
 - ख) उस संविदाकारी क्षेत्राधिकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य सभी करों के संबंध में, समझौतों की सूची के विस्तार की न्यासी द्वारा की गई अधिसूचना के सूचित किए जाने की तारीख से नौ कैलेंडर माह (कम अवधि हेतु, यदि सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकार न्यासी को सूचित करें की वे इसके लिए कम अवधि चाहते हैं) से आरंभ अथवा उसकी समाहित से संबंधित करयोग्य अवधि के लिए लगाए जाने वाले करों के संबंध में।
6. पैराग्राफ 4 के लिए पक्षकारों को उसे अपने समाहित कर समझौतों पर नहीं लागू करने का अधिकार होगा।
7. क) पक्षकारों को प्रतिस्थापन का अधिकार:
- i) पैराग्राफ 1 तथा 4 के 'समाहित का समाहित कर समझौतों के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद की तारीख' के संदर्भ के लिए प्रतिस्थापन का अधिकार होगा; तथा
 - ii) पैराग्राफ 5 'समझौतों की सूची के विस्तार की न्यासी द्वारा की गई अधिसूचना को सूचित किए जाने की तारीख' के संदर्भ में प्रतिस्थापन का अधिकार
- “अनुच्छेद 35 के पैराग्राफ 7 (प्रवृत्त होने की तारीख) में उल्लिखित आरक्षण करते हुए कि उसने विशिष्ट समाहित कर समझौतों के संबंध में इस अभिसमय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के लिए आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है, प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार को, न्यासी के द्वारा बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना की प्राप्ति के 30 दिन के बाद' के संदर्भ में प्रतिस्थापन का अधिकार होगा”;
- iii) अनुच्छेद 28 (आरक्षण) के पैराग्राफ 9 के उप पैराग्राफ क) के संदर्भ 'आरक्षण के वापस लेने अथवा उसके प्रतिस्थापन की न्यासी द्वारा की गई अधिसूचना के सूचित किए जाने की तारीख' में प्रतिस्थापन का अधिकार होगा; तथा
 - iv) अनुच्छेद 28 (आरक्षण) के पैराग्राफ 9 के उप पैराग्राफ ख) के संदर्भ “उन संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद की तारीख' में प्रतिस्थापन”;
- “अनुच्छेद 35 के पैराग्राफ 7 (प्रवृत्त होने की तारीख) में उल्लिखित आरक्षण करते हुए कि उसने विशिष्ट समाहित कर समझौतों के संबंध में इस अभिसमय के वापस लेने अथवा प्रतिस्थापन हेतु आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है, प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार को, न्यासी के द्वारा बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना की प्राप्ति के 30 दिन के बाद' के संदर्भ में प्रतिस्थापन का अधिकार होगा”;
- v) अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ क) का संदर्भ “न्यासी द्वारा की गई अतिरिक्त अधिसूचना के सूचित किए जाने की तारीख' में प्रतिस्थापन; तथा
 - vi) अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ ख) का संदर्भ “उन संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद की तारीख' में प्रतिस्थापन”;
- “अनुच्छेद 35 के पैराग्राफ 7 (प्रवृत्त होने की तारीख) में उल्लिखित आरक्षण करते हुए कि उसने विशिष्ट समाहित कर समझौतों के संबंध में इस अभिसमय के उपबंधों के संबंध में अतिरिक्त अधिसूचनाओं के प्रवृत्त होने के लिए आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है, प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार को, न्यासी के द्वारा बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना की प्राप्ति के 30 दिन के बाद' के संदर्भ में प्रतिस्थापन का अधिकार होगा”;
- vii) अनुच्छेद 36 (भाग VI के प्रवृत्त होने की तारीख) के पैराग्राफ 1 तथा 2 का संदर्भ 'समाहित कर समझौते के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद की तारीख' ;
- “अनुच्छेद 35 के पैराग्राफ 7 (प्रवृत्त होने की तारीख) में उल्लिखित आरक्षण करते हुए कि उसने विशिष्ट समाहित कर समझौतों के संबंध में इस अभिसमय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के लिए आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है, प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार को, न्यासी के द्वारा बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना की प्राप्ति के 30 दिन के बाद' के संदर्भ में प्रतिस्थापन का अधिकार होगा”;

- viii) पैराग्राफ 36 (भाग VI के प्रवृत्त होने की तारीख) के पैराग्राफ 3 का संदर्भ 'समझौतों की सूची के विस्तार की न्यासी द्वारा की गई अधिसूचना को सूचित किए जाने की तारीख' के संदर्भ में प्रतिस्थापन कर अधिकार
- ix) अनुच्छेद 36 (भाग VI के प्रवृत्त होने की तारीख) के पैराग्राफ 4 'न्यासी द्वारा आरक्षण के वापस लिए जाने की अधिसूचना के सूचना की तारीख', न्यासी द्वारा आरक्षण के प्रतिस्थापन की अधिसूचना की सूचना की तारीख, 'न्यासी द्वारा आरक्षण की आपत्ति के वापस लिए जाने की अधिसूचना की सूचना की तारीख' के संदर्भ का प्रतिस्थापन"; तथा
- x) अनुच्छेद 36 (भाग VI के प्रवृत्त होने की तारीख) के पैराग्राफ 5 का संदर्भ 'न्यासी द्वारा की गई अतिरिक्त सूचना के सूचित किए जाने की तारीख' में प्रतिस्थापन"; तथा
- “अनुच्छेद 35 के पैराग्राफ 7 (प्रवृत्त होने की तारीख) में उल्लिखित आरक्षण करते हुए कि उसने विशिष्ट समाहित कर समझौतों के संबंध में इस अभिसमय के भाग VI (मध्यस्थता) के उपबंधों के प्रवृत्त होने के लिए आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है, प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार को, न्यासी के द्वारा बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना की प्राप्ति के 30 दिन के बाद' के संदर्भ में प्रतिस्थापन का अधिकार होगा”।
- ख) उप पैराग्राफ क) के अनुसार आरक्षण करने वाला पक्षकार अपनी आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने की संपुष्टि एक साथ न्यासी तथा अन्य संविदाकारी क्षेत्राधिकार को देगा
- ग) यदि किसी समाहित कर समझौते एक या अधिक संविदाकारी क्षेत्राधिकार इस पैराग्राफ के अंतर्गत आरक्षण करते हैं तो इस अभिसमय के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख, आरक्षण के वापस लिए जाने अथवा प्रतिस्थापन, समाहित कर समझौते अथवा भाग VI (मध्यस्थता) के संबंध में कोई अतिरिक्त अधिसूचना, समाहित कर समझौते के सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के लिए इस पैराग्राफ द्वारा शासित होंगे।

अनुच्छेद 36 – भाग VI का प्रभावी होना

1. किसी समाहित कर समझौते के दो संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 28 (आरक्षण) के पैराग्राफ 9, अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के पैराग्राफ 6 तथा अनुच्छेद 35 (प्रवृत्त होने की तारीख) के पैराग्राफ 1 से 6 में किसी बात के बावजूद, भाग VI (मध्यस्थता) के उपबंध निम्नलिखित रूप से प्रभावित होंगे:

- क) अनुच्छेद 19 (आदेशात्मक बाध्यकारी मध्यस्थता) के पैराग्राफ 1 के किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार (जैसा कि उप पैराग्राफ क में उल्लिखित है) के सक्षम प्राधिकारी को, समाहित कर समझौते के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकारी के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने अथवा बाद की किसी तारीख को प्रस्तुत मामलों के संबंध में; तथा
- ख) समाहित कर समझौते के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद की तारीख से पूर्व किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को उस तारीख को प्रस्तुत मामलों के संबंध में जब दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों ने उस तारीख अथवा तारीखों की सूचना सहित जब पारस्परिक समझौते की शर्तों के अनुसार अनुच्छेद 19 (आदेशात्मक बाध्यकारी मध्यस्थता) के पैराग्राफ 1 के (जैसा कि उप पैराग्राफ क में उल्लिखित है) किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को जब इन मामलों को प्रस्तुत माना जाएगा, अनुच्छेद 19 (आदेशात्मक बाध्यकारी मध्यस्थता) के पैराग्राफ 10 के अनुपालनार्थ आपस में पारस्परिक समझौते पर पहुंचने के संबंध में उस तारीख को प्रस्तुत मामलों के संबंध में जब दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों द्वारा न्यासी को अधिसूचित किया।

2. किसी पक्षकार प्रत्येक को किसी समाहित कर समझौते के संविदाकारी क्षेत्राधिकार के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की पश्चाती तारीख से पूर्व किसी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को मामला प्रस्तुत करने के संबंध में भाग VI (मध्यस्थता) का अधिकार केवल उसी सीमा तक होगा जिस तक दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी उसे किसी मामले विशिष्ट पर ही लागू करने हेतु सहमत हुए हो।

3. अनुच्छेद 2 (शब्दावली की व्याख्या) के पैराग्राफ के उप पैराग्राफ क) के खण्ड ii) के अंतर्गत अधिसूचित समझौतों की सूची अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के पैराग्राफ 5 के अंतर्गत विस्तार दिए जाने के परिणामस्वरूप 1 किसी नए समाहित कर समझौते के मामले में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 में “किसी समाहित कर समझौते के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की बाद की तारीख” के संदर्भ को ‘समझौतों की सूची के विस्तार की न्यासी द्वारा की गई अधिसूचना के

सूचना की तारीख' के संदर्भ से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. अनुच्छेद 28 (आरक्षण) के पैराग्राफ 9 के अनुपालनार्थ अनुच्छेद 26 (सुसंगति) के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत किए किसी आरक्षण को वापस लेने अथवा अनुच्छेद 28 (आरक्षण) के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत किए गए किसी आरक्षण के प्रति आपत्ति को वापस लेने के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप किसी समाहित कर समझौते के दो संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के बीच भाग VI (मध्यस्थता) लागू होती है, "किसी समाहित कर समझौते के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद की तारीख" के संदर्भ को छोड़कर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) तथा ख) के अनुसार इसे क्रमशः "न्यासी द्वारा आरक्षण के वापस लिए जाने की अधिसूचना की सूचना", "न्यासी द्वारा आरक्षण के प्रतिस्थापन की अधिसूचना की सूचना की तारीख" अथवा "न्यासी द्वारा आरक्षण पर आपत्ति को वापस लिए जाने की अधिसूचना की सूचना" के संदर्भों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ त) के अनुपालनार्थ की गई अतिरिक्त अधिसूचना "किसी समाहित कर समझौते के प्रत्येक संविदाकारी क्षेत्राधिकार के लिए इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद की तारीख" से संबंधित इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के संदर्भ को छोड़कर, पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ क) तथा ख) को "न्यासी द्वारा अतिरिक्त अधिसूचना के सूचना की तारीख" के संदर्भ से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 37 - हटना

1. कोई भी पक्ष न्यासी को संबोधित करते हुए की गई अधिसूचना के माध्यम से कभी भी इस अभिसमय को समाप्त कर सकता है।
2. पैराग्राफ 1 के अनुपालन हेतु ऐसी समाहित न्यासी को ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी। किसी समाहित कर समझौते के सभी संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के लिए किसी पक्षकार द्वारा ऐसी समाहित के प्रभावी होने से पूर्व की तारीख जिन मामलों में यह अभिसमय के प्रवृत्त हो जाता है वहां वह समाहित कर समझौता इस अभिसमय के द्वारा संशोधित हो जाएगा।

अनुच्छेद 38 – प्रोटोकॉल के साथ संबंध

1. इस अभिसमय को एक अथवा दो प्रोटोकॉल द्वारा अनुपूरक किया जा सकता है।
2. किसी प्रोटोकॉल में एक पक्षकार बनने के लिए, किसी देश अथवा क्षेत्राधिकार को इस अभिसमय का पक्षकार होना अपेक्षित है।
3. इस अभिसमय का कोई पक्षकार किसी प्रोटोकॉल के प्रति तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि वह इसके उपबंधों के अनुसार उस प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं बनता।

अनुच्छेद 39 – न्यासी

1. आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का महासचिव इस अभिसमय तथा अनुच्छेद 38 (प्रोटोकॉल के साथ संबंध) के अनुपालनार्थ किसी प्रोटोकॉल हेतु न्यासी होगा।
2. न्यासी पक्षकारों को तथा हस्ताक्षरकर्ताओं को निम्नलिखित के एक कैलेंडर माह के भीतर अधिसूचित करेगा:
 - क) अनुच्छेद 27 के अनुसरण में किए गए किसी हस्ताक्षर(हस्ताक्षर तथा अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन)
 - ख) अनुच्छेद 27 के अनुसरण में जमा किए गए अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन(हस्ताक्षर तथा अनुप्रमाणन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन)के किसी विलेख
 - ग) अनुच्छेद 28 (आरक्षण) के अनुपालनार्थ किसी आरक्षण अथवा उसकी वापसी अथवा प्रतिस्थापन;
 - घ) अनुच्छेद 29 (अधिसूचनाएं) के अनुपालनार्थ की गई कोई अधिसूचना अथवा अतिरिक्त अधिसूचना;
 - ङ.) अनुच्छेद 33 (संशोधन) के अनुपालनार्थ इस अभिसमय में किए किसी प्रस्तावित संशोधन
 - च) अनुच्छेद 37 (वापसी) के अनुसरण में इस अभिसमय से किसी वापसी; और
 - छ) इस अभिसमय के संबंध में की गई किसी अन्य सूचना के संबंध में।
3. न्यासी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचियों को बनाए रखेगा:

- क) शामिल कर समझौतों की;
 ख) पक्षकारों द्वारा किए गए आरक्षणों की ; तथा
 ग) पक्षकारों द्वारा की गयी अधिसूचनाओं की।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

पेरिस में, नवंबर 2016 के 24 वें दिन , अंग्रेजी और फ्रेंच में, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, एकल प्रति में निष्पादित जिसे आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा।

भारत

संपुष्टि के लिखत के जमा करने पर आरक्षणों एवं अधिसूचनाओं की सूची की स्थिति

इस दस्तावेज़ में अभिसमय के अनुच्छेद 28 (5) और 29 (1) के अनुसार संपुष्टि के लिखत को जमा करने पर भारत द्वारा किए गए आरक्षण और अधिसूचनाओं की सूची है।

अनुच्छेद 2 - पदों की व्याख्या

अधिसूचना - अभिसमय में शामिल करार

अभिसमय के अनुच्छेद 2(1)(क)(ii) के अनुसरण में, भारत की इच्छा है कि इस अभिसमय में निम्नलिखित करारों को शामिल किया जाए:

संख्या	शीर्षक	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	मूल/संशोधनकारी लिखत	हस्ताक्षर की तारीख	प्रवृत्त होने की तारीख
1	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा अल्बानिया गणराज्य की सरकार के बीच करार।	अल्बानिया	मूल	08.07.2013	04.12.2013
2	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा आर्मेनिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय।	आर्मेनिया	मूल	31.10.2003	09.09.2004 ¹
			संशोधनकारी लिखत (ए)	27.01.2016	14.06.2017
3	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच करार	ऑस्ट्रेलिया	मूल	25.07.1991	30.12.1991
			संशोधनकारी लिखत (ए)	16.12.2011	02.04.2013
4	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय	ऑस्ट्रिया	मूल	08.11.1999	05.09.2001
			संशोधनकारी लिखत	06.02.2017	लागू नहीं

¹ भारत समझता है कि आर्मेनिया मानता है कि यह संधि 01.04.2004 को लागू हुई थी

	अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय।		(ए)		
5	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय	बांग्लादेश	मूल	27-08-1991	27-05-1992
			संशोधनकारी लिखत (ए)	16-02-2013	13-06-2013
6	आय तथा संपत्ति (पूंजी) पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेलारूस गणराज्य की सरकार के बीच करार।	बेलारूस (यूएसएसआर का हिस्सा)	मूल	27.09.1997	17.07.1998
			संशोधनकारी लिखत (ए)	03.06.2015	19.11.2015
7	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेल्जियम साम्राज्य की सरकार के बीच करार।	बेल्जियम	मूल	26.04.1993	01.10.1997
			संशोधनकारी लिखत (ए)	09.03.2017	लागू नहीं
8	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा भूटान की सरकार के बीच करार	भूटान	मूल	04-03-2013	17-07-2014
9	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत और बोत्सवाना के बीच अभिसमय	बोत्सवाना	मूल	08-12-2006	30-01-2008
10	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राज़ील संघीय गणराज्य की	ब्राज़ील	मूल	26.04.1988	11.03.1992
			संशोधनकारी लिखत (ए)	15.10.2013	06.08.2017

	सरकार के बीच अभिसमय				
11	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बुल्गारिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय।	बुल्गारिया	मूल	26.05.1994	23.06.1995
12	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कनाडा की सरकार के बीच करार।	कनाडा	मूल	11.01.1996	06.05.1997
13	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कोलम्बिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय	कोलम्बिया	मूल	13.05.2011	07.07.2014
14	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा क्रोएशिया गणराज्य की सरकार के बीच करार।	क्रोएशिया	मूल	12.02.2014	06.02.2015 ²
15	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा साइप्रस गणराज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल।	साइप्रस	मूल	18.11.2016	14.12.2016
16	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चेक गणराज्य की सरकार के	चेक गणराज्य	मूल	01.10.1998	27.09.1999

² भारत समझता है कि क्रोएशिया मानता है कि यह संधि 11.02.2015 को लागू हुई थी

	बीच अभिसमय।				
17	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क साम्राज्य की सरकार के बीच अभिसमय।	डेनमार्क	मूल संशोधनकारी लिखत (ए)	08.03.1989 10.10.2013	13.06.1989 01.02.2015
18	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत और मिश्र के बीच करार	मिश्र	मूल	20-02-1969	30-09-1969
19	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा एस्टोनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार।	एस्टोनिया	मूल	19.09.2011	20.06.2012
20	आय और पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत और इथोपिया के बीच अभिसमय।	इथोपिया	मूल	25-05-2011	15-10-2012
21	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा फ़ीजी की सरकार के बीच करार	फ़ीजी	मूल	30.01.2014	15.05.2014
22	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा फ़िनलैंड गणराज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल।	फ़िनलैंड	मूल	15.01.2010	19.04.2010
23	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा	फ़्रांस	मूल	29.09.1992	01.08.1994

	फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय।				
24	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जॉर्जिया की सरकार के बीच करार।	जॉर्जिया	मूल	24.08.2011	08.12.2011
25	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार के बीच करार।	जर्मनी	मूल	19.06.1995	26.10.1996
26	आय पर दोहरे कराधान का परिहार करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ग्रीस संघीय गणराज्य की सरकार के बीच करार।	ग्रीस	मूल	11.02.1965	17.03.1967
27	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार के बीच करार।	हांगकांग	मूल	19.03.2018	30.11.2018
28	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा हंगरी की सरकार के बीच करार।	हंगरी	मूल	03.11.2003	04.03.2005
29	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा आइसलैंड की सरकार के बीच करार।	आइसलैंड	मूल	23.11.2007	21.12.2007
30	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार	इंडोनेशिया	मूल	27-07-2012	05-02-2016

	करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय				
31	आय तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा आयरलैंड की सरकार के बीच अभिसमय।	आयरलैंड	मूल	06.11.2000	26.12.2001 ³
32	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा इज़राइल राज्य की सरकार के बीच अभिसमय	इज़राइल	मूल	29-01-1996	15-05-1996
			संशोधनकारी लिखत (ए)	14-10-2015	19-12-2016
33	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा इटली गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय	इटली	मूल	19.02.1993	23.11.1995
34	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान की सरकार के बीच अभिसमय	जापान	मूल	07.03.1989	29.12.1989
			संशोधनकारी लिखत (ए)	24.02.2006	28.06.2006
			संशोधनकारी लिखत (सी)	11.12.2015	29.10.2016
35	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जॉर्डन हैशेमाइट साम्राज्य की सरकार के बीच अभिसमय	जॉर्डन	मूल	20-04-1999	16-10-1999
36	आय पर तथा पूंजी पर करों के	कज़ाकस्तान	मूल	09-12-1996	02-10-1997

³ भारत समझता है कि आयरलैंड मानता है कि यह संधि 27.12.2001 को लागू हुई थी

	संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कजाकस्तान गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय		संशोधनकारी लिखत (ए)	06-01-2017	12-03-2018
37	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत और केन्या के बीच करार	केन्या	मूल	11-07-2016	30-08-2017
38	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय	कोरिया	मूल	18-05-2015	12-09-2016
39	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार के बीच करार	कुवैत	मूल	15-06-2006	17-10-2007
			संशोधनकारी लिखत (ए)	15-01-2017	26-03-2018
40	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा किरगिज गणराज्य की सरकार के बीच करार	किरगिज गणराज्य	मूल	13-04-1999	10-01-2001
41	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा लातविया गणराज्य की सरकार के बीच करार	लातविया	मूल	18.09.2013	28.12.2013
42	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत और लीबिया की सरकार के	लीबिया	मूल	02-03-1981	01-07-1982

	बीच अभिसमय				
43	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा लिथुआनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल।	लिथुआनिया	मूल	26.07.2011	10.07.2012
44	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा गैड डिची ऑफ लक्ज़म्बर्ग की सरकार के बीच करार।	लक्ज़म्बर्ग	मूल	02.06.2008	09.07.2009
45	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मेसिडोनिया गणराज्य की सरकार के बीच करार।	मेसिडोनिया	मूल	17.12.2013	12.09.2014
46	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मलेशिया की सरकार के बीच करार	मलेशिया	मूल	09-05-2012	26-12-2012
47	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा माल्टा गणराज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल	माल्टा	मूल	08.04.2013	07.02.2014
48	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मारीशस की सरकार के बीच करार	मारीशस	मूल	24.08.1982	06.12.1983
			संशोधनकारी लिखत (ए)	10.05.2016	19.07.2016
49	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार	मेक्सिको	मूल	10.09.2007	01.02.2010

	करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य मेक्सिको की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल				
50	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मंगोलिया की सरकार के बीच करार	मंगोलिया	मूल	22-02-1994	29-03-1996
51	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा सर्बिया एवं मॉन्टेनेग्रो के मंत्रिमंडल की सरकार के बीच अभिसमय।	मॉन्टेनेग्रो	मूल	08.02.2006	23.09.2008
52	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा मोरक्को साम्राज्य के बीच करार	मोरक्को	मूल संशोधनकारी लिखत (ए)	30.10.1998 08.08.2013	20.02.2000 लागू नहीं
53	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच करार	मोजाम्बिक	मूल	30.09.2010	28.02.2011
54	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा म्यांमार संघ की सरकार के बीच करार	म्यांमार	मूल	02-04-2008	30-01-2009
55	आय पर तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा	नामीबिया	मूल	15.02.1997	22.01.1999

	नामीबिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय				
56	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा नेपाल की सरकार के बीच करार	नेपाल	मूल	27-11-2011	16-03-2012
57	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा नीदरलैंड साम्राज्य के बीच अभिसमय।	नीदरलैंड	मूल	30.07.1988	21.01.1989
			संशोधनकारी लिखत (ए)	10.05.2012	02.11.2012
58	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा न्यूज़ीलैंड की सरकार के बीच अभिसमय	न्यूज़ीलैंड	मूल	17.10.1986	03.12.1986
			संशोधनकारी लिखत (ए)	29.08.1996	09.01.1997
			संशोधनकारी लिखत (सी)	21.06.1999	30.12.1999 ⁴
			संशोधनकारी लिखत (सी)	26.10.2016	07.09.2017
59	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा नॉर्वे साम्राज्य के बीच करार।	नॉर्वे	मूल	02.02.2011	20.12.2011
60	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा ओमान की सल्तनत के बीच करार	ओमान	मूल	02-04-1997	03-06-1997
61	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा फ़िलिपींस गणराज्य के बीच अभिसमय	फ़िलिपींस	मूल	12-02-1990	21-03-1994

⁴ भारत समझता है कि न्यूज़ीलैंड मानता है कि दूसरा प्रोटोकॉल 17.12.1999 को लागू हुआ था

62	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा पोलिस जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार।	पोलैंड	मूल	21.06.1989	26.10.1989
			संशोधनकारी लिखत (ए)	29.01.2013	01.06.2014
63	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा पुर्तगाल गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय।	पुर्तगाल	मूल	11.09.1998	30.04.2000 ⁵
			संशोधनकारी लिखत (ए)	24.06.2017	08.08.2018
64	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा क्रतर राज्य की सरकार के बीच करार	क्रतर	मूल	07-04-1999	15-01-2000
65	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य और रोमानिया के बीच करार।	रोमानिया	मूल	08.03.2013	16.12.2013
66	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा रूस परिसंघ की सरकार के बीच करार।	रूस	मूल	25.03.1997	11.04.1998
67	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सऊदी अरब साम्राज्य की सरकार के बीच अभिसमय	सऊदी अरब	मूल	25-01-2006	01-11-2006
68	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत	सर्बिया	मूल	08.02.2006	23.09.2008

⁵ भारत समझता है कि पुर्तगाल मानता है कि यह संधि 5.4.2000 को लागू हुई थी

	गणराज्य तथा सर्बिया एवं मॉन्टेनेग्रो के मंत्रिमंडल की सरकार के बीच अभिसमय।				
69	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार	सिंगापुर	मूल	24-01-1994	27-05-1994
			संशोधनकारी लिखत (ए)	29-06-2005	01-08-2005
			संशोधनकारी लिखत (सी)	24-06-2011	01-09-2011
			संशोधनकारी लिखत (सी)	30-12-2016	27/02/2017
70	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत सरकार तथा चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार।	स्लोवाक गणराज्य	मूल	27.01.1986	13.03.1987
71	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा स्लोवेनिया गणराज्य के बीच अभिसमय।	स्लोवेनिया	मूल	13.01.2003	17.02.2005
			संशोधनकारी लिखत (ए)	17.5.2016	21.12.2016
72	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच करार	दक्षिण अफ्रीका	मूल	04.12.1996	28.11.1997
			संशोधनकारी लिखत (ए)	26.7.2013	26.11.2014
73	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा स्पेन साम्राज्य के बीच अभिसमय।	स्पेन	मूल	08.02.1993	12.01.1995
			संशोधनकारी लिखत (ए)	26.10.2012	लागू नहीं
74	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार	श्री लंका	मूल	22-01-2013	22-10-2013

75	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सूडान गणराज्य की सरकार के बीच करार	सूडान	मूल	22.10.2003	15.04.2004
76	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा स्वीडन साम्राज्य की सरकार के बीच अभिसमय।	स्वीडन	मूल	24.06.1997	25.12.1997
			संशोधनकारी लिखत (ए)	07.02.2013	16.08.2013
77	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य और स्विस् परिसंघ के बीच करार।	स्विस् परिसंघ	मूल	02.11.1994	29.12.1994
			संशोधनकारी लिखत (ए)	16.02.2000	20.12.2000
			संशोधनकारी लिखत (सी)	30.08.2010	07.10.2011
78	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सीरिया अरब गणराज्य की सरकार के बीच करार	सीरिया	मूल	18-06-2008	10-11-2008
79	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच करार	ताजिकिस्तान	मूल	20-11-2008	10-04-2009
			संशोधनकारी लिखत (ए)	17-12-2016	20-02-2018
80	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा तंजानिया गणराज्य की सरकार के बीच करार	तंजानिया	मूल	27.05.2011	12.12.2011
81	आय पर करों के संबंध में	थाईलैंड	मूल	29-06-2015	13-10-2015 ⁶

⁶ भारत समझता है कि थाईलैंड मानता है कि यह संधि 05/01/2016 को लागू हुई थी

	दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा थाईलैंड साम्राज्य की सरकार के बीच करार				
82	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ट्रिनीडाड एवं टोबैगो गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय।	ट्रिनीडाड एवं टोबैगो	मूल	08.02.1999	13.10.1999
83	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा टर्की गणराज्य के बीच करार।	टर्की	मूल	31.01.1995	01.02.1997 ⁷
84	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा तुर्कमेनिस्तान की सरकार के बीच अभिसमय	तुर्कमेनिस्तान	मूल	25-02-1997	07-07-1997
85	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा युगांडा गणराज्य की सरकार के बीच करार	युगांडा	मूल	30.04.2004	27.08.2004
86	आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा यूक्रेन की सरकार के बीच अभिसमय।	यूक्रेन	मूल	07.04.1999	31.10.2001

⁷ भारत समझता है कि तुर्की मानता है कि यह संधि 30.12.1996 को लागू हुई थी

87	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच एक करार	संयुक्त अरब अमीरात	मूल	29-04-1992	22-09-1993
			संशोधनकारी लिखत (ए)	26-03-2007	03-10-2007
			संशोधनकारी लिखत (सी)	16-04-2012	12-03-2013
88	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के बीच अभिसमय।	यूनाइटेड किंगडम	मूल	25.01.1993	26.10.1993 ⁸
			संशोधनकारी लिखत (ए)	30.10.2012	27.12.2013
89	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा उरुग्वे गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय	उरुग्वे	मूल	08.09.2011	21.06.2013
90	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच अभिसमय।	यूएसए	मूल	12.09.1989	18.12.1990
91	आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा उजबेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच करार	उजबेकिस्तान	मूल	29-07-1993	25-01-1994
			संशोधनकारी लिखत (ए)	11-04-2012	20-07-2012
92	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच करार	वियतनाम	मूल	07-09-1994	02-02-1995
			संशोधनकारी लिखत (ए)	03-09-2016	21-02-2017

⁸ भारत समझता है कि यूके मानता है कि यह संधि 25.10.1993 को लागू हुई थी

93	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जाम्बिया की सरकार के बीच करार	जाम्बिया	मूल	05.06.1981	18.01.1984
----	--	----------	-----	------------	------------

अनुच्छेद 3 - पारदर्शी संस्थाएं

आरक्षण

अभिसमय के अनुच्छेद 3(5)(क) के अनुसरण में, भारत अपने शामिल कर समझौतों पर अनुच्छेद 3 की संपूर्णता लागू न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

अनुच्छेद 4 - दोहरी निवासी संस्थाएं

सूचीबद्ध समझौतों में मौजूदा प्रावधानों की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 4(4) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 4(2) में वर्णित एक प्रावधान शामिल है जो अनुच्छेद 4(3)(ख) से (घ) के तहत किसी आरक्षण का विषय नहीं है। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
1	अल्बानिया	अनुच्छेद 4(3)
2	आर्मेनिया	अनुच्छेद 4(3)
3	ऑस्ट्रेलिया	अनुच्छेद 4(3)
4	ऑस्ट्रिया	अनुच्छेद 4(3)
5	बांग्लादेश	अनुच्छेद 4(3)
6	बेलारूस	अनुच्छेद 4(3)
7	बेल्जियम	अनुच्छेद 4(3)
8	भूटान	अनुच्छेद 4(3)
9	बोत्सवाना	अनुच्छेद 4(3)
10	ब्राज़ील	अनुच्छेद 4 (3)
11	बुल्गारिया	अनुच्छेद 4(3)
12	कनाडा	अनुच्छेद 4(3)
13	कोलम्बिया	अनुच्छेद 4 (3)
14	क्रोएशिया	अनुच्छेद 4(3)
15	साइप्रस	अनुच्छेद 4(3)
16	चेक गणराज्य	अनुच्छेद 4(3)
17	डेनमार्क	अनुच्छेद 4(3)
18	मिश्र	अनुच्छेद 4(3)

19	एस्टोनिया	अनुच्छेद 4(3)
20	इथोपिया	अनुच्छेद 4(3)
21	फिजी	अनुच्छेद 4(3)
22	फिनलैंड	अनुच्छेद 4(3)
23	फ्रांस	अनुच्छेद 4(3)
24	जॉर्जिया	अनुच्छेद 4(3)
25	जर्मनी	अनुच्छेद 4(3)
27	हांगकांग	अनुच्छेद 4(3)
28	हंगरी	अनुच्छेद 4(3)
29	आइसलैंड	अनुच्छेद 4(3)
30	इंडोनेशिया	अनुच्छेद 4(3)
31	आयरलैंड	अनुच्छेद 4(3)
32	इज़राइल	अनुच्छेद 4(3)
33	इटली	अनुच्छेद 4(3)
34	जापान	अनुच्छेद 4 (2)
35	जॉर्डन	अनुच्छेद 4(3)
36	कजाकस्तान	अनुच्छेद 4(3)
37	केन्या	अनुच्छेद 4(3)
38	कोरिया	अनुच्छेद 4(3)
39	कुवैत	अनुच्छेद 4(4)
40	किरगिज गणराज्य	अनुच्छेद 4(3)
41	लातविया	अनुच्छेद 4(3)
43	लिथुआनिया	अनुच्छेद 4(3)
44	लक्ज़म्बर्ग	अनुच्छेद 4(3)
45	मेसिडोनिया	अनुच्छेद 4(3)
46	मलेशिया	अनुच्छेद 4(3)
47	माल्टा	अनुच्छेद 4(3)
48	मारीशस	अनुच्छेद 4(3)
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 4(3)
50	मंगोलिया	अनुच्छेद 4(3)
51	मॉन्टेनेग्रो	अनुच्छेद 4(3)
52	मोरक्को	अनुच्छेद 4(3)
53	मोज़ाम्बीक	अनुच्छेद 4(3)

54	म्यांमार	अनुच्छेद 4(3)
55	नामीबिया	अनुच्छेद 4(3)
56	नेपाल	अनुच्छेद 4(3)
57	नीदरलैंड	अनुच्छेद 4(3)
58	न्यूज़ीलैंड	अनुच्छेद 4(3)
59	नॉर्वे	अनुच्छेद 4(3)
60	ओमान	अनुच्छेद 4(3)
61	फ़िलिपींस	अनुच्छेद 4(3)
62	पोलैंड	अनुच्छेद 4(3)
63	पुर्तगाल	अनुच्छेद 4(3)
64	क्रतर	अनुच्छेद 4(3)
65	रोमानिया	अनुच्छेद 4(3)
66	रूस	अनुच्छेद 4(3)
67	सऊदी अरब	अनुच्छेद 4(3)
68	सर्बिया	अनुच्छेद 4(3)
69	सिंगापुर	अनुच्छेद 4(3)
70	स्लोवाक गणराज्य	अनुच्छेद 4(3)
71	स्लोवेनिया	अनुच्छेद 4(3)
72	दक्षिण अफ़्रीका	अनुच्छेद 4(3)
73	स्पेन	अनुच्छेद 4(3)
74	श्री लंका	अनुच्छेद 4(3)
75	सूडान	अनुच्छेद 4(3)
76	स्वीडन	अनुच्छेद 4(3)
77	स्विस परिसंघ	अनुच्छेद 4(3)
78	सीरिया	अनुच्छेद 4(3)
79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 4(3)
80	तंजानिया	अनुच्छेद 4(3)
81	थाईलैंड	अनुच्छेद 4(3)
82	ट्रिनीडाड & टोबैगो	अनुच्छेद 4(3)
83	टर्की	अनुच्छेद 4(3)
84	तुर्कमेनिस्तान	अनुच्छेद 4(3)
85	युगांडा	अनुच्छेद 4(3)
86	यूक्रेन	अनुच्छेद 4(3)

87	संयुक्त अरब अमीरात	अनुच्छेद 4(4)
88	यूनाइटेड किंगडम	अनुच्छेद 4(3)
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 4 (3)
90	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनुच्छेद 4(3) और (4)
91	उजबेकिस्तान	अनुच्छेद 4(3)
92	वियतनाम	अनुच्छेद 4(3)
93	जाम्बिया	अनुच्छेद 4(3)

अनुच्छेद 5 - दोहरे कराधान के निरसन की विधि की प्रयोज्यता

वैकल्पिक प्रावधानों की पसंद की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 5(10) के अनुसरण में, भारत इसके द्वारा अनुच्छेद 5 (1) के तहत इस अनुच्छेद के विकल्प ग को लागू करने का चयन करता है।

विकल्प ग चुनने वाले क्षेत्राधिकारों के लिए:

अभिसमय के अनुच्छेद 5(10) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 5(7) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
11	बुल्गारिया	अनुच्छेद 25(2),(3)
18	मिश्र	अनुच्छेद 24(1),(2)
26	ग्रीस	अनुच्छेद XVII (2),(4)
70	स्लोवाक गणराज्य	अनुच्छेद 23(2),(3)

अनुच्छेद 7 - संधि दुरुपयोग की रोकथाम

एक अंतरिम उपाय के रूप में पीपीटी की स्वीकृति का विवरण

अभिसमय के अनुच्छेद 7 (17)(क) के अनुसरण में, भारत इसके द्वारा एक वक्तव्य देता है कि भारत जहां एक अंतरिम उपाय के रूप में अकेले अनुच्छेद 7 (1) की प्रयोज्यता को स्वीकार करता है, वहीं जहाँ सम्भव हो उसका इरादा लाभों के प्रावधान पर परिसीमन को पैराग्राफ 1 के अतिरिक्त अथवा उसके स्थान पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अपनाने का है।

वैकल्पिक प्रावधानों की पसंद की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 7(17) (ग) के अनुसरण में, भारत इसके द्वारा अनुच्छेद 7 (6) के तहत एलओबी के सरलीकृत प्रावधान को लागू करने का चयन करता है।

सूचीबद्ध समझौतों में मौजूदा प्रावधानों की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 7(17)(क) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करार अनुच्छेद 7(15)(ख) के तहत आरक्षण के विषय नहीं हैं तथा उनमें अनुच्छेद 7(2) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
1	अल्बानिया	अनुच्छेद 29 (6)
8	भूटान	अनुच्छेद 27(2) और (3)
13	कोलम्बिया	अनुच्छेद 28 (2) और (3)

19	एस्टोनिया	अनुच्छेद 28(2) से (4) तक
20	इथोपिया	अनुच्छेद 28(2) और (3)
21	फ़िजी	अनुच्छेद 28(2) और (3)
22	फ़िनलैंड	अनुच्छेद 27 (1) और (2)
24	जॉर्जिया	अनुच्छेद 30(2) से (4) तक
29	आइसलैंड	अनुच्छेद 24(6)
30	इंडोनेशिया	अनुच्छेद 24(2) और (3)
32	इज़राइल	अनुच्छेद 27क(1)
36	कज़ाक़स्तान	अनुच्छेद 28क(2)
37	केन्या	अनुच्छेद 29(2) और (3)
38	कोरिया	अनुच्छेद 28(2)
39	कुवैत	अनुच्छेद 27
41	लातविया	अनुच्छेद 28 (1)
43	लिथुआनिया	अनुच्छेद 30 (1) और (2)
44	लक्ज़म्बर्ग	अनुच्छेद 29 (2) और (3)
45	मेसिडोनिया	अनुच्छेद 28(2) से (4) तक
46	मलेशिया	अनुच्छेद 28(2) और (3)
47	माल्टा	अनुच्छेद 27(2) और (3)
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 28 (6)
53	मोज़ाम्बीक	अनुच्छेद 28
54	म्यांमार	अनुच्छेद 27(1) और (2)
56	नेपाल	अनुच्छेद 28
59	नॉर्वे	अनुच्छेद 29
62	पोलैंड	अनुच्छेद 28क
65	रोमानिया	अनुच्छेद 27
74	श्री लंका	अनुच्छेद 28(6)
78	सीरिया	अनुच्छेद 27
79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 28(6)
80	तंजानिया	अनुच्छेद 28(6)
87	संयुक्त अरब अमीरात	अनुच्छेद 29
88	यूनाइटेड किंगडम	अनुच्छेद 28ग
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 29 (7)
91	उजबेकिस्तान	अनुच्छेद 28ख(2) और (3)

अभिसमय के अनुच्छेद 7(17)(ग) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 7(14) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
1	अल्बानिया	अनुच्छेद 29(1) से (5) तक
2	आर्मेनिया	अनुच्छेद 28
29	आइसलैंड	अनुच्छेद 24(1) से (5) तक
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 28(1) से (5) तक
74	श्री लंका	अनुच्छेद 28(1) से (5) तक
79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 28(1) से (5) तक
80	तंजानिया	अनुच्छेद 28(1) से (5) तक
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 29(2) से (6) तक
90	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनुच्छेद 24

अनुच्छेद 8 - लाभांश अंतरण संव्यवहार

आरक्षण

अभिसमय के अनुच्छेद 8(3)(ख)(iii) के अनुसरण में, भारत अनुच्छेद 8 की संपूर्णता के लिए अपने शामिल कर समझौतों को इस सीमा तक लागू नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखता है कि अनुच्छेद 8 (1) में वर्णित प्रावधानों में पहले से ही 365 दिनों की अवधि से अधिक की न्यूनतम अवधि शामिल है। निम्नलिखित समझौते में ऐसे प्रावधान हैं जो इस आरक्षण के दायरे में हैं।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
63	पुर्तगाल	अनुच्छेद 10(2)

सूचीबद्ध समझौतों में मौजूदा प्रावधानों की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 8(4) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 8(1) में वर्णित एक प्रावधान शामिल है जो अनुच्छेद 8(3)(ख) के तहत आरक्षण का विषय नहीं है। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
5	बांग्लादेश	अनुच्छेद 11(2)(क)
6	बेलारूस	अनुच्छेद 10(2)(क)
9	बोत्सवाना	अनुच्छेद 10(2)(क)
12	कनाडा	अनुच्छेद 10(2)(क)
14	क्रोएशिया	अनुच्छेद 10(2)(क)
17	डेनमार्क	अनुच्छेद 11(2)(क)
33	इटली	अनुच्छेद 11(2)(क)
43	लिथुआनिया	अनुच्छेद 10(2)(क)

48	मारीशस	अनुच्छेद 10(2)(क)
51	मॉन्टेनेग्रो	अनुच्छेद 10(2)(1)
56	नेपाल	अनुच्छेद 10(2)(क)
60	ओमान	अनुच्छेद 11(2)(क)
61	फिलिपींस	अनुच्छेद 11(2)(क)
64	क्रतर	अनुच्छेद 10(2)(क)
68	सर्बिया	अनुच्छेद 10(2)(1)
69	सिंगापुर	अनुच्छेद 10(2)(क)
70	स्लोवाक गणराज्य	अनुच्छेद 10(2)(क)
71	स्लोवेनिया	अनुच्छेद 10(2)(क)
78	सीरिया	अनुच्छेद 10(2)(क)
79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 10(2)(क)
80	तंजानिया	अनुच्छेद 10(2)(क)
86	यूक्रेन	अनुच्छेद 10(2)(क)
90	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनुच्छेद 10(2)(क)
93	जाम्बिया	अनुच्छेद 10(2)(क)

अनुच्छेद 9 - मुख्यतः अचल सम्पत्ति से अपना मूल्य हासिल करने वाली संस्थाओं के शेयरों अथवा हितों की बिक्री से पूंजीगत लाभ

वैकल्पिक प्रावधानों की पसंद की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 9(8) के अनुसरण में, भारत इसके द्वारा अनुच्छेद 9 (4) को लागू करने का चयन करता है।

सूचीबद्ध समझौतों में मौजूदा प्रावधानों की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 9(7) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 9(1) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
2	आर्मेनिया	अनुच्छेद 13(4)
3	ऑस्ट्रेलिया	अनुच्छेद 13(4)
4	ऑस्ट्रिया	अनुच्छेद 13(4)
6	बेलारूस	अनुच्छेद 13(4)
7	बेल्जियम	अनुच्छेद 13(4)
8	भूटान	अनुच्छेद 13(4)
9	बोत्सवाना	अनुच्छेद 13(4)
11	बुल्गारिया	अनुच्छेद 14(4)

13	कोलम्बिया	अनुच्छेद 13 (4)
14	क्रोएशिया	अनुच्छेद 13(4)
15	साइप्रस	अनुच्छेद 13(4)
16	चेक गणराज्य	अनुच्छेद 13(4)
17	डेनमार्क	अनुच्छेद 14(4)
19	एस्टोनिया	अनुच्छेद 13(2)
20	इथोपिया	अनुच्छेद 13(4)
21	फ़िजी	अनुच्छेद 13(4)
23	फ़्रांस	अनुच्छेद 14(4)
24	जॉर्जिया	अनुच्छेद 13(4)
27	हांगकांग	अनुच्छेद 14(4)
28	हंगरी	अनुच्छेद 13(2)
29	आइसलैंड	अनुच्छेद 13(4)
30	इंडोनेशिया	अनुच्छेद 13(4)
31	आयरलैंड	अनुच्छेद 13(4)
32	इज़राइल	अनुच्छेद 14(4)
33	इटली	अनुच्छेद 14(4)
35	जॉर्डन	अनुच्छेद 13(4)
36	कज़ाकस्तान	अनुच्छेद 13(4)
37	केन्या	अनुच्छेद 14(4)
38	कोरिया	अनुच्छेद 13(4)
39	कुवैत	अनुच्छेद 13(4)
40	किरगिज गणराज्य	अनुच्छेद 13(4)
41	लातविया	अनुच्छेद 13(4)
44	लक्ज़म्बर्ग	अनुच्छेद 13(4)
45	मेसिडोनिया	अनुच्छेद 13(4)
46	मलेशिया	अनुच्छेद 14(4)
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 13(4)
50	मंगोलिया	अनुच्छेद 13(4)
51	मॉन्टेनेग्रो	अनुच्छेद 14(4)
52	मोरक्को	अनुच्छेद 13(4)

53	मोज़ाम्बीक	अनुच्छेद 13(4)
54	म्यांमार	अनुच्छेद 13(4)
55	नामीबिया	अनुच्छेद 13(4)
56	नेपाल	अनुच्छेद 13(4)
57	नीदरलैंड	अनुच्छेद 13(4)
58	न्यूज़ीलैंड	अनुच्छेद 13(4)
60	ओमान	अनुच्छेद 15(4)
61	फ़िलिपींस	अनुच्छेद 14(4)
62	पोलैंड	अनुच्छेद 14(4)
63	पुर्तगाल	अनुच्छेद 13(4)
64	क़तर	अनुच्छेद 13(4)
67	सऊदी अरब	अनुच्छेद 13(4)
68	सर्बिया	अनुच्छेद 14(4)
70	स्लोवाक गणराज्य	अनुच्छेद 13(4)
71	स्लोवेनिया	अनुच्छेद 13(4)
72	दक्षिण अफ़्रीका	अनुच्छेद 13(4)
73	स्पेन	अनुच्छेद 14(4)
74	श्री लंका	अनुच्छेद 13(4)
75	सूडान	अनुच्छेद 13(4)
76	स्वीडन	अनुच्छेद 13(4)
77	स्विस परिसंघ	अनुच्छेद 13(4)
80	तंजानिया	अनुच्छेद 13(4)
81	थाईलैंड	अनुच्छेद 13(4)
82	ट्रिनीडाड & टोबैगो	अनुच्छेद 13(4)
83	टर्की	अनुच्छेद 13(4)
84	तुर्कमेनिस्तान	अनुच्छेद 13(4)
85	युगांडा	अनुच्छेद 13(4)
86	यूक्रेन	अनुच्छेद 13(4)
87	संयुक्त अरब अमीरात	अनुच्छेद 13(3)
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 13 (4)
91	उजबेकिस्तान	अनुच्छेद 14(4)
92	वियतनाम	अनुच्छेद 14(4)

अनुच्छेद 12 - आयुक्तालयीय प्रबंधनों और इसी प्रकार की रणनीतियों के द्वारा स्थायी स्थापना दर्जे का कृत्रिम परिहार
सूचीबद्ध समझौतों में मौजूदा प्रावधानों की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 12(5) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 12(3)(क) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
1	अल्बानिया	अनुच्छेद 5(5)(क)
2	आर्मेनिया	अनुच्छेद 5(5)(क)
3	ऑस्ट्रेलिया	अनुच्छेद 5(5)(क)
4	ऑस्ट्रिया	अनुच्छेद 5(5)(क)
5	बांग्लादेश	अनुच्छेद 5(4)(क)
6	बेलारूस	अनुच्छेद 5(4)(क)
7	बेल्जियम	अनुच्छेद 5(4)(क)
8	भूटान	अनुच्छेद 5(5)(क)
9	बोत्सवाना	अनुच्छेद 5(5) (क)
10	ब्राज़ील	अनुच्छेद 5 (4)
11	बुल्गारिया	अनुच्छेद 5(4)(क)
12	कनाडा	अनुच्छेद 5(4)(क)
13	कोलम्बिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
14	क्रोएशिया	अनुच्छेद 5(6)(क)
15	साइप्रस	अनुच्छेद 5(5)(क)
16	चेक गणराज्य	अनुच्छेद 5(5)(क)
17	डेनमार्क	अनुच्छेद 5(4)(क)
18	मिश्र	अनुच्छेद 5(4)(i)
19	एस्टोनिया	अनुच्छेद 5(5)(क)
20	इथोपिया	अनुच्छेद 5(5)(क)
21	फिजी	अनुच्छेद 5(5)(क)
22	फिनलैंड	अनुच्छेद 5(5) (क)
23	फ्रांस	अनुच्छेद 5(5) (क)
24	जॉर्जिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
25	जर्मनी	अनुच्छेद 5(5) (क)
26	ग्रीस	अनुच्छेद II(1)(ज)(घघ)(1)
27	हांगकांग	अनुच्छेद 5(5) (क)
28	हंगरी	अनुच्छेद 5(5) (क)

29	आइसलैंड	अनुच्छेद 5(5) (क)
30	इंडोनेशिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
31	आयरलैंड	अनुच्छेद 5(6) (क)
32	इज़राइल	अनुच्छेद 5 (5)
33	इटली	अनुच्छेद 5(4) (क)
34	जापान	अनुच्छेद 5(7) (क)
35	जॉर्डन	अनुच्छेद 5 (6)
36	कज़ाकस्तान	अनुच्छेद 5 (5)
37	केन्या	अनुच्छेद 5(5) (क)
38	कोरिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
39	कुवैत	अनुच्छेद 5(6) (क)
40	किरगिज गणराज्य	अनुच्छेद 5(6) (क)
41	लातविया	अनुच्छेद 5(5) (क)
42	लीबिया	अनुच्छेद 4(4)
43	लिथुआनिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
44	लक्ज़म्बर्ग	अनुच्छेद 5(5) (क)
45	मेसिडोनिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
46	मलेशिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
47	माल्टा	अनुच्छेद 5(5) (क)
48	मारीशस	अनुच्छेद 5(4)(i)
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 5(5) (क)
50	मंगोलिया	अनुच्छेद 5 (4)
51	मॉन्टेनेग्रो	अनुच्छेद 5(5)(1)
52	मोरक्को	अनुच्छेद 5(5)
53	मोज़ाम्बीक	अनुच्छेद 5(5) (क)
54	म्यांमार	अनुच्छेद 5(5) (क)
55	नामीबिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
56	नेपाल	अनुच्छेद 5(5) (क)
57	नीदरलैंड	अनुच्छेद 5(5) (क)
58	न्यूज़ीलैंड	अनुच्छेद 5(4) (क)
59	नॉर्वे	अनुच्छेद 5(5) (क)
60	ओमान	अनुच्छेद 5 (4)
61	फ़िलिपींस	अनुच्छेद 5(4) (क)

62	पोलैंड	अनुच्छेद 4(5) (क)
63	पुर्तगाली गणराज्य	अनुच्छेद 5(5) (क)
64	क्रतर	अनुच्छेद 5(6) (क)
65	रोमानिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
66	रूस	अनुच्छेद 4(5) (क)
67	सऊदी अरब	अनुच्छेद 5(5) (क)
68	सर्बिया	अनुच्छेद 5(5)(1)
69	सिंगापुर	अनुच्छेद 5(8) (क)
70	स्लोवाक गणराज्य	अनुच्छेद 4(5) (क)
71	स्लोवेनिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
72	दक्षिण अफ्रीका	अनुच्छेद 5(5)
73	स्पेन	अनुच्छेद 4(5) (क)
74	श्री लंका	अनुच्छेद 5(5) (क)
75	सूडान	अनुच्छेद 5(5) (क)
76	स्वीडन	अनुच्छेद 6(5) (क)
77	स्विस परिसंघ	अनुच्छेद 5(5)(i)
78	सीरिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 5 (5)
80	तंजानिया	अनुच्छेद 5(5) (क)
81	थाईलैंड	अनुच्छेद 5(5) (क)
82	ट्रिनीडाड & टोबैगो	अनुच्छेद 5(4) (क)
83	टर्की	अनुच्छेद 4(5) (क)
84	तुर्कमेनिस्तान	अनुच्छेद 5(5) (क)
85	युगांडा	अनुच्छेद 5(4) (क)
86	यूक्रेन	अनुच्छेद 5(5) (क)
87	संयुक्त अरब अमीरात	अनुच्छेद 5 (4)
88	यूनाइटेड किंगडम	अनुच्छेद 4(5) (क)
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 5(5) (क)
90	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनुच्छेद 5(4) (क)
91	उजबेकिस्तान	अनुच्छेद 5 (4)
92	वियतनाम	अनुच्छेद 5(4) (क)
93	जाम्बिया	अनुच्छेद 5(4) (i)

अभिसमय के अनुच्छेद 12(6) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 12(3)(ख) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
1	अल्बानिया	अनुच्छेद 5 (7)
2	आर्मेनिया	अनुच्छेद 5 (7)
3	ऑस्ट्रेलिया	अनुच्छेद 5(6)
4	ऑस्ट्रिया	अनुच्छेद 5 (6)
5	बांग्लादेश	अनुच्छेद 5 (5)
6	बेलारूस	अनुच्छेद 5 (5)
7	बेल्जियम	अनुच्छेद 5 (5)
8	भूटान	अनुच्छेद 5 (7)
9	बोत्सवाना	अनुच्छेद 5(7)
10	ब्राज़ील	अनुच्छेद 5 (5)
11	बुल्गारिया	अनुच्छेद 5 (5)
12	कनाडा	अनुच्छेद 5 (5)
13	कोलम्बिया	अनुच्छेद 5(7)
14	क्रोएशिया	अनुच्छेद 5 (8)
15	साइप्रस	अनुच्छेद 5 (7)
16	चेक गणराज्य	अनुच्छेद 5 (7)
17	डेनमार्क	अनुच्छेद 5 (5)
18	मिश्र	अनुच्छेद 5(5)
19	एस्टोनिया	अनुच्छेद 5 (6)
20	इथोपिया	अनुच्छेद 5(6)
21	फ़िजी	अनुच्छेद 5(7)
22	फ़िनलैंड	अनुच्छेद 5 (7)
23	फ़्रांस	अनुच्छेद 5 (6)
24	जॉर्जिया	अनुच्छेद 5 (7)
25	जर्मनी	अनुच्छेद 5 (6)
26	ग्रीस	अनुच्छेद II(1)(ज)(ड.ड.)
27	हांगकांग	अनुच्छेद 5 (6)
28	हंगरी	अनुच्छेद 5 (6)
29	आइसलैंड	अनुच्छेद 5 (7)
30	इंडोनेशिया	अनुच्छेद 5 (7)

31	आयरलैंड	अनुच्छेद 5 (8)
32	इज़राइल	अनुच्छेद 5 (6)
33	इटली	अनुच्छेद 5 (5)
34	जापान	अनुच्छेद 5(8)
35	जॉर्डन	अनुच्छेद 5 (8)
36	कज़ाकस्तान	अनुच्छेद 5 (7)
37	केन्या	अनुच्छेद 5(7)
38	कोरिया	अनुच्छेद 5 (7)
39	कुवैत	अनुच्छेद 5 (8)
40	किरगिज गणराज्य	अनुच्छेद 5 (8)
41	लातविया	अनुच्छेद 5 (6)
42	लीबिया	अनुच्छेद 4(5)
43	लिथुआनिया	अनुच्छेद 5 (6)
44	लक्ज़म्बर्ग	अनुच्छेद 5 (7)
45	मेसिडोनिया	अनुच्छेद 5(7)
46	मलेशिया	अनुच्छेद 5 (7)
47	माल्टा	अनुच्छेद 5(7)
48	मारीशस	अनुच्छेद 5(5)
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 5 (7)
50	मंगोलिया	अनुच्छेद 5 (5)
51	मॉन्टेनेग्रो	अनुच्छेद 5(7)
52	मोरक्को	अनुच्छेद 5(7)
53	मोज़ाम्बीक	अनुच्छेद 5(7)
54	म्यांमार	अनुच्छेद 5 (7)
55	नामीबिया	अनुच्छेद 5(6)
56	नेपाल	अनुच्छेद 5 (7)
57	नीदरलैंड	अनुच्छेद 5(6)
58	न्यूज़ीलैंड	अनुच्छेद 5(5)
59	नॉर्वे	अनुच्छेद 5(7)
60	ओमान	अनुच्छेद 5 (5)
61	फ़िलिपींस	अनुच्छेद 5 (6)
62	पोलैंड	अनुच्छेद 5(5)
63	पुर्तगाली गणराज्य	अनुच्छेद 5(6)

64	क्रतर	अनुच्छेद 5 (8)
65	रोमानिया	अनुच्छेद 5(6)
66	रूस	अनुच्छेद 5(5)
67	सऊदी अरब	अनुच्छेद 5 (7)
68	सर्बिया	अनुच्छेद 5(7)
69	सिंगापुर	अनुच्छेद 5 (9)
70	स्लोवाक गणराज्य	अनुच्छेद 5(5)
71	स्लोवेनिया	अनुच्छेद 5(7)
72	दक्षिण अफ्रीका	अनुच्छेद 5(6)
73	स्पेन	अनुच्छेद 5(5)
74	श्री लंका	अनुच्छेद 5 (7)
75	सूडान	अनुच्छेद 5(7)
76	स्वीडन	अनुच्छेद 5(8)
77	स्विस परिसंघ	अनुच्छेद 5(6)
78	सीरिया	अनुच्छेद 5 (7)
79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 5 (6)
80	तंजानिया	अनुच्छेद 5(7)
81	थाईलैंड	अनुच्छेद 5 (7)
82	ट्रिनिडाड & टोबैगो	अनुच्छेद 5 (6)
83	टर्की	अनुच्छेद 5(5)
84	तुर्कमेनिस्तान	अनुच्छेद 5 (7)
85	युगांडा	अनुच्छेद 5(6)
86	यूक्रेन	अनुच्छेद 5(6)
87	संयुक्त अरब अमीरात	अनुच्छेद 5 (5)
88	यूनाइटेड किंगडम	अनुच्छेद 5(5)
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 5 (7)
90	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनुच्छेद 5 (5)
91	उजबेकिस्तान	अनुच्छेद 5 (5)
92	वियतनाम	अनुच्छेद 5 (5)
93	जाम्बिया	अनुच्छेद 5(6)

अनुच्छेद 13 - विनिर्दिष्ट गतिविधि छूटों के द्वारा स्थाई स्थापना दर्जे का कृत्रिम परिहार**वैकल्पिक प्रावधानों की पसंद की अधिसूचना**

अभिसमय के अनुच्छेद 13(7) के अनुसरण में, भारत इसके द्वारा अनुच्छेद 13 (1) के तहत विकल्प [क] को लागू करने का चयन करता है।

सूचीबद्ध समझौतों में मौजूदा प्रावधानों की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 13(7) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 13(5)(क) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
1	अल्बानिया	अनुच्छेद 5(4)
2	आर्मेनिया	अनुच्छेद 5(4)
3	ऑस्ट्रेलिया	अनुच्छेद 5(4)
4	ऑस्ट्रिया	अनुच्छेद 5(4)
5	बांग्लादेश	अनुच्छेद 5(3)
6	बेलारूस	अनुच्छेद 5(3)
7	बेल्जियम	अनुच्छेद 5(3)
8	भूटान	अनुच्छेद 5(4)
9	बोत्सवाना	अनुच्छेद 5(4)
10	ब्राज़ील	अनुच्छेद 5 (3)
11	बुल्गारिया	अनुच्छेद 5(3)
12	कनाडा	अनुच्छेद 5(3)
13	कोलम्बिया	अनुच्छेद 5(4)
14	क्रोएशिया	अनुच्छेद 5(5)
15	साइप्रस	अनुच्छेद 5(4)
16	चेक गणराज्य	अनुच्छेद 5(4)
17	डेनमार्क	अनुच्छेद 5(3)
18	मिश्र	अनुच्छेद 5(3)
19	एस्टोनिया	अनुच्छेद 5(4)
20	इथोपिया	अनुच्छेद 5(4)
21	फ़िजी	अनुच्छेद 5(4)
22	फ़िनलैंड	अनुच्छेद 5(4)
23	फ़्रांस	अनुच्छेद 5(4)
24	जॉर्जिया	अनुच्छेद 5(4)
25	जर्मनी	अनुच्छेद 5(4)
26	ग्रीस	अनुच्छेद II(1)(ज)(गग)

27	हांगकांग	अनुच्छेद 5(4)
28	हंगरी	अनुच्छेद 5(4)
29	आइसलैंड	अनुच्छेद 5(4)
30	इंडोनेशिया	अनुच्छेद 5(4)
31	आयरलैंड	अनुच्छेद 5(5)
32	इज़राइल	अनुच्छेद 5(4)
33	इटली	अनुच्छेद 5(3)
34	जापान	अनुच्छेद 5(6)
35	जॉर्डन	अनुच्छेद 5(5)
36	कज़ाकस्तान	अनुच्छेद 5(4)
37	केन्या	अनुच्छेद 5(4)
38	कोरिया	अनुच्छेद 5(4)
39	कुवैत	अनुच्छेद 5(5)
40	किरगिज गणराज्य	अनुच्छेद 5(5)
41	लातविया	अनुच्छेद 5(4)
42	लीबिया	अनुच्छेद 4(3)
43	लिथुआनिया	अनुच्छेद 5(4)
44	लक्ज़म्बर्ग	अनुच्छेद 5(4)
45	मेसिडोनिया	अनुच्छेद 5(4)
46	मलेशिया	अनुच्छेद 5(4)
47	माल्टा	अनुच्छेद 5(4)
48	मारीशस	अनुच्छेद 5(3)
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 5(4)
50	मंगोलिया	अनुच्छेद 5(3)
51	मॉन्टेनेग्रो	अनुच्छेद 5(4)
52	मोरक्को	अनुच्छेद 5(4)
53	मोज़ाम्बीक	अनुच्छेद 5(4)
54	म्यांमार	अनुच्छेद 5(4)
55	नामीबिया	अनुच्छेद 5(4)
56	नेपाल	अनुच्छेद 5(4)
57	नीदरलैंड	अनुच्छेद 5(4)
58	न्यूज़ीलैंड	अनुच्छेद 5(3)
59	नॉर्वे	अनुच्छेद 5(4)

60	ओमान	अनुच्छेद 5(3)
61	फ़िलिपींस	अनुच्छेद 5(3)
62	पोलैंड	अनुच्छेद 5(3)
63	पुर्तगाल	अनुच्छेद 5(4)
64	क्रतर	अनुच्छेद 5(5)
65	रोमानिया	अनुच्छेद 5(4)
66	रूस	अनुच्छेद 5(3)
67	सऊदी अरब	अनुच्छेद 5(4)
68	सर्बिया	अनुच्छेद 5(4)
69	सिंगापुर	अनुच्छेद 5(7)
70	स्लोवाक गणराज्य	अनुच्छेद 5(3)
71	स्लोवेनिया	अनुच्छेद 5(4)
72	दक्षिण अफ्रीका	अनुच्छेद 5(4)
73	स्पेन	अनुच्छेद 5(3)
74	श्री लंका	अनुच्छेद 5(4)
75	सूडान	अनुच्छेद 5(4)
76	स्वीडन	अनुच्छेद 5(5)
77	स्विस परिसंघ	अनुच्छेद 5(3)
78	सीरिया	अनुच्छेद 5(4)
79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 5(4)
80	तंजानिया	अनुच्छेद 5(4)
81	थाईलैंड	अनुच्छेद 5(4)
82	ट्रिनीडाड & टोबैगो	अनुच्छेद 5(3)
83	टर्की	अनुच्छेद 5(3)
84	तुर्कमेनिस्तान	अनुच्छेद 5(4)
85	युगांडा	अनुच्छेद 5(3)
86	यूक्रेन	अनुच्छेद 5(4)
87	संयुक्त अरब अमीरात	अनुच्छेद 5(3)
88	यूनाइटेड किंगडम	अनुच्छेद 5(3)
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 5 (4)
90	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनुच्छेद 5(3)
91	उजबेकिस्तान	अनुच्छेद 5(3)
92	वियतनाम	अनुच्छेद 5(3)
93	जाम्बिया	अनुच्छेद 5(3)

अनुच्छेद 16 - पारस्परिक करार की विधि**आरक्षण**

अभिसमय के अनुच्छेद 16(5)(क) अनुसरण में भारत के पास इस आधार पर इसके सम्मिलित कर करार को लागू नहीं करने के अनुच्छेद 16(1) के प्रथम वाक्य के लिए अधिकार सुरक्षित है कि इसका आशय यह सुनिश्चित करते हुए ओईसीडी/जी 20बीईपीएस पैकेज के अंतर्गत विवाद समाधान सुधारने के लिए न्यूनतम मानदण्ड पूरा करना है कि इसके प्रत्येक सम्मिलित कर करार के अंतर्गत (उस सम्मिलित कर करार को छोड़कर जो एक व्यक्ति को किसी भी संविदाकारी क्षेत्राधिकार के सक्षम प्राधिकारी को मामला प्रस्तुत करने की अनुमति देता है) जहां एक व्यक्ति विचार करता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी क्षेत्राधिकारों की कार्यवाही से उस व्यक्ति के लिए सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अनुसार कराधान में फल आता है अथवा फल आएगा तो वह व्यक्ति उन संविदाकारी क्षेत्राधिकारों के घरेलू कानून द्वारा प्रदान किए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना मामले को उस संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह व्यक्ति निवासी है, उन उपबंधों सहित जिसके तहत यदि उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला राष्ट्रीयता पर आधारित गैर भेदभाव से संबंधित सम्मिलित कर करार के उपबंधों के अंतर्गत आता है, तो मामले को उस संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसका वह व्यक्ति राष्ट्रिक है और उस संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी उन मामलों के लिए दूसरे संविदाकारी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के साथ द्विपक्षीय अधिसूचना तथा परामर्श प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगा जिसमें वह सक्षम प्राधिकारी, जिससे परस्पर करार प्रक्रिया मामला प्रस्तुत किया गया था, करदाता की आपत्ति को उचित होने पर विचार नहीं करता है;

अनुच्छेद 2 (1) (क) (ii) के अनुसरण में भारत के सभी सीटीए के लिए आरक्षण लागू है।

सूचीबद्ध समझौतों में मौजूदा प्रावधानों की अधिसूचना

इस अभिसमय के अनुच्छेद 16(6)(ख)(i) के अनुसार, भारत मानता है कि निम्नलिखित समझौतों में एक प्रावधान है जिसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 16 (1) के पहले वाक्य में निर्दिष्ट किसी मामले को एक विशिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कार्यवाही की पहली अधिसूचना से तीन साल से कम हो, जिसके परिणामस्वरूप कराधान शामिल कर समझौते के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
7	बेल्जियम	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
12	कनाडा	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
33	इटली	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
87	संयुक्त अरब अमीरात	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य

इस अभिसमय के अनुच्छेद 16(6)(ख)(ii) के अनुसार, भारत मानता है कि निम्नलिखित समझौतों में एक प्रावधान है जिसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 16 (1) के पहले वाक्य में निर्दिष्ट किसी मामले को एक विशिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कार्यवाही की पहली अधिसूचना से कम से कम तीन साल हो, जिसके परिणामस्वरूप कराधान शामिल कर समझौते के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। ऐसे प्रत्येक प्रावधान के अनुच्छेद और पैराग्राफ संख्या की पहचान नीचे की गई है।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
1	अल्बानिया	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
2	आर्मेनिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
3	ऑस्ट्रेलिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
4	ऑस्ट्रिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
5	बांग्लादेश	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
6	बेलारूस	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य

8	भूटान	अनुच्छेद 24(1), दूसरा वाक्य
9	बोत्सवाना	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
10	ब्राज़ील	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
11	बुल्गारिया	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
13	कोलम्बिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
14	क्रोएशिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
15	साइप्रस	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
16	चेक गणराज्य	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
17	डेनमार्क	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
19	एस्टोनिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
20	इथोपिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
21	फ़िजी	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
22	फ़िनलैंड	अनुच्छेद 24(1), दूसरा वाक्य
23	फ़्रांस	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
24	जॉर्जिया	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
25	जर्मनी	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
27	हांगकांग	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
28	हंगरी	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
29	आइसलैंड	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
30	इंडोनेशिया	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
31	आयरलैंड	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
32	इज़राइल	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
34	जापान	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
35	जॉर्डन	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
36	कज़ाक़स्तान	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
37	केन्या	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
38	कोरिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
39	कुवैत	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
40	किरगिज गणराज्य	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
41	लातविया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
43	लिथुआनिया	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
44	लक्ज़म्बर्ग	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
45	मेसिडोनिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य

46	मलेशिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
47	माल्टा	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
48	मारीशस	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
50	मंगोलिया	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
51	मॉन्टेनेग्रो	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
52	मोरक्को	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
53	मोज़ाम्बीक	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
54	म्यांमार	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
55	नामीबिया	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
56	नेपाल	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
57	नीदरलैंड	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
58	न्यूज़ीलैंड	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
59	नॉर्वे	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
60	ओमान	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
61	फ़िलिपींस	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
62	पोलैंड	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
63	पुर्तगाल	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
64	क्रतर	अनुच्छेद 23(1), दूसरा वाक्य
65	रोमानिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
66	रूस	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
67	सऊदी अरब	अनुच्छेद 24(1), दूसरा वाक्य
68	सर्बिया	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
69	सिंगापुर	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
70	स्लोवाक गणराज्य	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
71	स्लोवेनिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
72	दक्षिण अफ़्रीका	अनुच्छेद 24(1), दूसरा वाक्य
73	स्पेन	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
74	श्री लंका	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
75	सूडान	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
76	स्वीडन	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
77	स्विस परिसंघ	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
78	सीरिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य

79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
80	तंजानिया	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
81	थाईलैंड	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
82	ट्रिनीडाड एवं टोबैगो	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
83	टर्की	अनुच्छेद 25(2), दूसरा वाक्य
84	तुर्कमेनिस्तान	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
85	युगांडा	अनुच्छेद 25(1), दूसरा वाक्य
86	यूक्रेन	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य
90	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
91	उजबेकिस्तान	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
92	वियतनाम	अनुच्छेद 27(1), दूसरा वाक्य
93	जाम्बिया	अनुच्छेद 26(1), दूसरा वाक्य

सूचीबद्ध समझौतों की अधिसूचना जिसमें मौजूदा प्रावधान शामिल नहीं है

अभिसमय के अनुच्छेद 16(6)(ग)(i) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 16(4)(ख)(i) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार
26	ग्रीस
49	मेक्सिको

अभिसमय के अनुच्छेद 16(6)(ग)(ii) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 16(4)(ख)(ii) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार
12	कनाडा
18	मिश्र
26	ग्रीस
33	इटली
42	लीबिया
49	मेक्सिको
61	फ़िलिपींस
77	स्विस परिसंघ
83	टर्की
88	यूनाइटेड किंगडम

अभिसमय के अनुच्छेद 16(6)(घ)(i) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 16(4)(ख)(i) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार
3	ऑस्ट्रेलिया
26	ग्रीस

अभिसमय के अनुच्छेद 16(6)(घ)(ii) के अनुसरण में, भारत का विचार है कि निम्नलिखित करारों में अनुच्छेद 16(4)(ग)(ii) में वर्णित प्रावधान शामिल हैं।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार
3	ऑस्ट्रेलिया
7	बेल्जियम
26	ग्रीस
61	फिलिपींस
86	यूक्रेन
88	यूनाइटेड किंगडम

अनुच्छेद 17 - संगत समायोजन

आरक्षण

अभिसमय के अनुच्छेद 17(3)(क) के अनुसरण में, भारत अनुच्छेद 17 की संपूर्णता के लिए अपने शामिल कर समझौतों को इस सीमा तक लागू नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखता है कि अनुच्छेद 17(2) में पहले ही एक प्रावधान शामिल है। निम्नलिखित समझौते में ऐसे प्रावधान हैं जो इस आरक्षण के दायरे में हैं।

सूचीबद्ध करार की संख्या	अन्य संविदात्मक क्षेत्राधिकार	प्रावधान
1	अल्बानिया	अनुच्छेद 9(2)
2	आर्मेनिया	अनुच्छेद 9(2)
4	ऑस्ट्रिया	अनुच्छेद 9(2)
8	भूटान	अनुच्छेद 9(2)
9	बोत्सवाना	अनुच्छेद 9(2)
12	कनाडा	अनुच्छेद 9(2)
13	कोलम्बिया	अनुच्छेद 9 (2)
14	क्रोएशिया	अनुच्छेद 9(2)
15	साइप्रस	अनुच्छेद 9(2)
17	डेनमार्क	अनुच्छेद 10(2)
19	एस्टोनिया	अनुच्छेद 9(2)
20	इथोपिया	अनुच्छेद 9(2)

21	फ़िजी	अनुच्छेद 9(2)
22	फ़िनलैंड	अनुच्छेद 9(2)
24	जॉर्जिया	अनुच्छेद 9(2)
27	हांगकांग	अनुच्छेद 9(2)
28	हंगरी	अनुच्छेद 9(2)
29	आइसलैंड	अनुच्छेद 9(2)
30	इंडोनेशिया	अनुच्छेद 9(2)
31	आयरलैंड	अनुच्छेद 9(2)
32	इज़राइल	अनुच्छेद 9(2)
35	जॉर्डन	अनुच्छेद 9(2)
36	कजाकस्तान	अनुच्छेद 9(2)
37	केन्या	अनुच्छेद 9(2)
38	कोरिया	अनुच्छेद 9(2)
39	कुवैत	अनुच्छेद 9(2)
40	किरगिज गणराज्य	अनुच्छेद 9(2)
41	लातविया	अनुच्छेद 9(2)
44	लक्ज़मबर्ग	अनुच्छेद 9(2)
45	मेसिडोनिया	अनुच्छेद 9(2)
47	माल्टा	अनुच्छेद 9(2)
49	मेक्सिको	अनुच्छेद 9(2)
51	मॉन्टेनेग्रो	अनुच्छेद 9(2)
52	मोरक्को	अनुच्छेद 9(2)
53	मोज़ाम्बीक	अनुच्छेद 9(2)
54	म्यांमार	अनुच्छेद 9(2)
55	नामीबिया	अनुच्छेद 9(2)
56	नेपाल	अनुच्छेद 9(2)
57	नीदरलैंड	अनुच्छेद 9(2)
58	न्यूज़ीलैंड	अनुच्छेद 9(2) और 9(3)
61	फ़िलिपींस	अनुच्छेद 10(2)
62	पोलैंड	अनुच्छेद 10(2)
63	पुर्तगाल	अनुच्छेद 9(2)
64	क्रतर	अनुच्छेद 9(2)
65	रोमानिया	अनुच्छेद 9(2)

67	सऊदी अरब	अनुच्छेद 9(2)
68	सर्बिया	अनुच्छेद 9(2)
69	सिंगापुर	अनुच्छेद 9(2)
71	स्लोवेनिया	अनुच्छेद 9(2)
72	दक्षिण अफ्रीका	अनुच्छेद 9(2)
74	श्री लंका	अनुच्छेद 9(2)
75	सूडान	अनुच्छेद 9(2)
77	स्विस परिसंघ	अनुच्छेद 9(2)
78	सीरिया	अनुच्छेद 9(2)
79	ताजिकिस्तान	अनुच्छेद 9(2)
80	तंजानिया	अनुच्छेद 9(2)
81	थाईलैंड	अनुच्छेद 9(2)
82	ट्रिनिडाड & टोबैगो	अनुच्छेद 9(2)
83	टर्की	अनुच्छेद 9(2)
84	तुर्कमेनिस्तान	अनुच्छेद 9(2)
85	युगांडा	अनुच्छेद 9(2)
88	यूनाइटेड किंगडम	अनुच्छेद 10(2)
89	उरुग्वे	अनुच्छेद 9 (2)
90	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनुच्छेद 9(2)

अनुच्छेद 35 – प्रभावी होना

वैकल्पिक प्रावधानों की पसंद की अधिसूचना

अभिसमय के अनुच्छेद 35(2) के अनुसरण में, केवल अनुच्छेद 35(1)(क) और 5(क) की प्रयोज्यता के लिए, भारत इसके द्वारा “कराधान अवधि” को “कैलेंडर वर्ष” से बदलना पसंद करता है।

भारत ने इस अभिसमय के भाग VI का चयन नहीं किया है।

[अधिसूचना सं. 57 /2019/फा. सं. 500/71/2015- एफटीडी-I]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(INCOME TAX)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2887(E).—Whereas the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (hereinafter referred to as the “the said Convention”) was signed by India at Paris, France on the 7th day of June, 2017;

And whereas, the said Convention entered into force on the 01st day of July, 2018, being the first day of month following expiration of three calendar months beginning on the date of deposit of the fifth instrument of ratification, in accordance with para 1 of Article 34 of the said Convention;

And whereas, India had ratified the said Convention and had deposited the instrument of ratification along-with the list of Covered Tax Agreements, reservations and notifications (hereinafter referred to as “India’s Position under the said Convention”) to the Depositary as in Article 39 of the said Convention, on the 25th day of June, 2019;

And whereas, the date of entry into force of the said Convention for India is the 01st day of October, 2019, being the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the 25th day of June, 2019 being the date of deposit by India of the instrument of ratification, in accordance with para 2 of Article 34 of the said Convention;

And whereas, the provisions of the said Convention shall have effect in India with respect to a Covered Tax Agreement in accordance with provisions of Article 35 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India, in accordance with India’s Position under the said Convention, as set out in the Annexure hereto.

ANNEXURE**MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING**

The Parties to this Convention,

Recognising that governments lose substantial corporate tax revenue because of aggressive international tax planning that has the effect of artificially shifting profits to locations where they are subject to non-taxation or reduced taxation;

Mindful that base erosion and profit shifting (hereinafter referred to as “BEPS”) is a pressing issue not only for industrialised countries but also for emerging economies and developing countries;

Recognising the importance of ensuring that profits are taxed where substantive economic activities generating the profits are carried out and where value is created;

Welcoming the package of measures developed under the OECD/G20 BEPS project (hereinafter referred to as the “OECD/G20 BEPS package”);

Noting that the OECD/G20 BEPS package included tax treaty-related measures to address certain hybrid mismatch arrangements, prevent treaty abuse, address artificial avoidance of permanent establishment status, and improve dispute resolution;

Conscious of the need to ensure swift, co-ordinated and consistent implementation of the treaty-related BEPS measures in a multilateral context;

Noting the need to ensure that existing agreements for the avoidance of double taxation on income are interpreted to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by those agreements without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-

shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in those agreements for the indirect benefit of residents of third jurisdictions);

Recognising the need for an effective mechanism to implement agreed changes in a synchronised and efficient manner across the network of existing agreements for the avoidance of double taxation on income without the need to bilaterally renegotiate each such agreement;

Have agreed as follows:

PART I.

SCOPE AND INTERPRETATION OF TERMS

Article 1 – Scope of the Convention

This Convention modifies all Covered Tax Agreements as defined in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms).

Article 2 – Interpretation of Terms

1. For the purpose of this Convention, the following definitions apply:
 - a) The term “Covered Tax Agreement” means an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income (whether or not other taxes are also covered):
 - i) that is in force between two or more:
 - A) Parties; and/or
 - B) jurisdictions or territories which are parties to an agreement described above and for whose international relations a Party is responsible; and
 - ii) with respect to which each such Party has made a notification to the Depositary listing the agreement as well as any amending or accompanying instruments thereto (identified by title, names of the parties, date of signature, and, if applicable at the time of the notification, date of entry into force) as an agreement which it wishes to be covered by this Convention.
 - b) The term “Party” means:
 - i) A State for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force); or
 - ii) A jurisdiction which has signed this Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval) and for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force).
 - c) The term “Contracting Jurisdiction” means a party to a Covered Tax Agreement.
 - d) The term “Signatory” means a State or jurisdiction which has signed this Convention but for which the Convention is not yet in force.
2. As regards the application of this Convention at any time by a Party, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the relevant Covered Tax Agreement.

PART II.

HYBRID MISMATCHES

Article 3 - Transparent Entities

1. For the purposes of a Covered Tax Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction shall be considered to be income of a resident of a Contracting Jurisdiction but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that Contracting Jurisdiction, as the income of a resident of that Contracting Jurisdiction.

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that require a Contracting Jurisdiction to exempt from income tax or provide a deduction or credit equal to the income tax paid with respect to income derived by a resident of that Contracting Jurisdiction which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction according to the provisions of the Covered Tax Agreement shall not apply to the extent that such provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction.

3. With respect to Covered Tax Agreements for which one or more Parties has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents), the following sentence will be added at the end of paragraph 1: "In no case shall the provisions of this paragraph be construed to affect a Contracting Jurisdiction's right to tax the residents of that Contracting Jurisdiction."

4. Paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that they address whether income derived by or through entities or arrangements that are treated as fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction (whether through a general rule or by identifying in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements) shall be treated as income of a resident of a Contracting Jurisdiction.

5. A Party may reserve the right:

- a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
- b) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4;
- c) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;
- d) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements;
- e) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements and denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;
- f) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements;
- g) for paragraph 1 to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements.

6. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4 that is not subject to a reservation under subparagraphs c) through e) of paragraph 5, and if so, the article and paragraph number of each such provision. In the case of a Party that has made the reservation described in subparagraph g) of paragraph 5, the notification pursuant to the preceding sentence shall be limited to Covered Tax Agreements that are subject to that reservation. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) to the extent provided in paragraph 4. In other cases, paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3).

Article 4 – Dual Resident Entities

1. Where by reason of the provisions of a Covered Tax Agreement a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions

shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting Jurisdiction of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Covered Tax Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide rules for determining whether a person other than an individual shall be treated as a resident of one of the Contracting Jurisdictions in cases in which that person would otherwise be treated as a resident of more than one Contracting Jurisdiction. Paragraph 1 shall not apply, however, to provisions of a Covered Tax Agreement specifically addressing the residence of companies participating in dual-listed company arrangements.

3. A Party may reserve the right:

- a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
- b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;
- c) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by denying treaty benefits without requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;
- d) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence, and that set out the treatment of that person under the Covered Tax Agreement where such an agreement cannot be reached;
- e) to replace the last sentence of paragraph 1 with the following text for the purposes of its Covered Tax Agreements: "In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement.";
- f) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements with Parties that have made the reservation described in subparagraph e).

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraphs b) through d) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

Article 5 – Application of Methods for Elimination of Double Taxation

1. A Party may choose to apply either paragraphs 2 and 3 (Option A), paragraphs 4 and 5 (Option B), or paragraphs 6 and 7 (Option C), or may choose to apply none of the Options. Where each Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement chooses a different Option (or where one Contracting Jurisdiction chooses to apply an Option and the other chooses to apply none of the Options), the Option chosen by each Contracting Jurisdiction shall apply with respect to its own residents.

Option A

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of

eliminating double taxation shall not apply where the other Contracting Jurisdiction applies the provisions of the Covered Tax Agreement to exempt such income or capital from tax or to limit the rate at which such income or capital may be taxed. In the latter case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income or capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.

3. Paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income or capital described in that paragraph.

Option B

4. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation because such income is treated as a dividend by that Contracting Jurisdiction shall not apply where such income gives rise to a deduction for the purpose of determining the taxable profits of a resident of the other Contracting Jurisdiction under the laws of that other Contracting Jurisdiction. In such case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such income which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.

5. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income described in that paragraph.

Option C

6. a) Where a resident of a Contracting Jurisdiction derives income or owns capital which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction in accordance with the provisions of a Covered Tax Agreement (except to the extent that these provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction), the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow:

- i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction;
- ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other Contracting Jurisdiction.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.

b) Where in accordance with any provision of the Covered Tax Agreement income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction is exempt from tax in that Contracting Jurisdiction, such Contracting Jurisdiction may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

7. Paragraph 6 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that, for purposes of eliminating double taxation, require a Contracting Jurisdiction to exempt from tax in that Contracting Jurisdiction income derived or capital owned by a resident of that Contracting Jurisdiction which, in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction.

8. A Party that does not choose to apply an Option under paragraph 1 may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements).

9. A Party that does not choose to apply Option C may reserve the right, with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements), not to permit the other Contracting Jurisdiction(s) to apply Option C.

10. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include:

- a) in the case of a Party that chooses to apply Option A, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision;
- b) in the case of a Party that chooses to apply Option B, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision;
- c) in the case of a Party that chooses to apply Option C, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 7, as well as the article and paragraph number of each such provision.

An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where the Party that has chosen to apply that Option has made such a notification with respect to that provision.

PART III.

TREATY ABUSE

Article 6 – Purpose of a Covered Tax Agreement

1. A Covered Tax Agreement shall be modified to include the following preamble text:

“Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),”.

2. The text described in paragraph 1 shall be included in a Covered Tax Agreement in place of or in the absence of preamble language of the Covered Tax Agreement referring to an intent to eliminate double taxation, whether or not that language also refers to the intent not to create opportunities for non-taxation or reduced taxation.

3. A Party may also choose to include the following preamble text with respect to its Covered Tax Agreements that do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters:

“Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,”.

4. A Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain preamble language describing the intent of the Contracting Jurisdictions to eliminate double taxation without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation, whether that language is limited to cases of tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in the Covered Tax Agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions) or applies more broadly.

5. Each Party shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains preamble language described in paragraph 2, and if so, the text of the relevant preambular paragraph. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that preamble language, such preamble language shall be replaced by the text described in paragraph 1. In other cases, the text described in paragraph 1 shall be included in addition to the existing preamble language.

6. Each Party that chooses to apply paragraph 3 shall notify the Depositary of its choice. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements that do not already contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters. The text described in paragraph 3 shall be included in a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply that paragraph and have made such a notification with respect to the Covered Tax Agreement.

Article 7 – Prevention of Treaty Abuse

1. Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement.
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.
3. A Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.
4. Where a benefit under a Covered Tax Agreement is denied to a person under provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits, the competent authority of the Contracting Jurisdiction that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or capital, if such competent authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or arrangement. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under this paragraph by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before rejecting the request.
5. Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.
6. A Party may also choose to apply the provisions contained in paragraphs 8 through 13 (hereinafter referred to as the “Simplified Limitation on Benefits Provision”) to its Covered Tax Agreements by making the notification described in subparagraph c) of paragraph 17. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply it.
7. In cases where some but not all of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, then, notwithstanding the provisions of that paragraph, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to the granting of benefits under the Covered Tax Agreement:
 - a) by all Contracting Jurisdictions, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly; or
 - b) only by the Contracting Jurisdictions that choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly.

Simplified Limitation on Benefits Provision

8. Except as otherwise provided in the Simplified Limitation on Benefits Provision, a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall not be entitled to a benefit that would otherwise be

accorded by the Covered Tax Agreement, other than a benefit under provisions of the Covered Tax Agreement:

- a) which determine the residence of a person other than an individual which is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by reason of provisions of the Covered Tax Agreement that define a resident of a Contracting Jurisdiction;
- b) which provide that a Contracting Jurisdiction will grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contracting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of an associated enterprise; or
- c) which allow residents of a Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement,

unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 9 at the time that the benefit would be accorded.

9. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement if, at that time, the resident is:

- a) an individual;
- b) that Contracting Jurisdiction, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of any such Contracting Jurisdiction, political subdivision or local authority;
- c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;
- d) a person, other than an individual, that:
 - i) is a non-profit organisation of a type that is agreed to by the Contracting Jurisdictions through an exchange of diplomatic notes; or
 - ii) is an entity or arrangement established in that Contracting Jurisdiction that is treated as a separate person under the taxation laws of that Contracting Jurisdiction and:
 - A) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that Contracting Jurisdiction or one of its political subdivisions or local authorities; or
 - B) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision A);
- e) a person other than an individual, if, on at least half the days of a twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons who are residents of that Contracting Jurisdiction and that are entitled to benefits of the Covered Tax Agreement under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.

10. a) A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement will be entitled to benefits of the Covered Tax Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting Jurisdiction, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction, and the income derived from the other Contracting Jurisdiction emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision, the term “active conduct of a business” shall not include the following activities or any combination thereof:

- i) operating as a holding company;
 - ii) providing overall supervision or administration of a group of companies;
 - iii) providing group financing (including cash pooling); or
 - iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank, insurance company or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such.
- b) If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting Jurisdiction, or derives an item of income arising in the other Contracting Jurisdiction from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned Contracting Jurisdiction to which the item is related is substantial in relation to the same activity or a complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting Jurisdiction. Whether a business activity is substantial for the purposes of this subparagraph shall be determined based on all the facts and circumstances.
- c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be deemed to be conducted by such resident.

11. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement that is not a qualified person shall also be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement with respect to an item of income if, on at least half of the days of any twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the beneficial interests of the resident.

12. If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 9, nor entitled to benefits under paragraph 10 or 11, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant the benefits of the Covered Tax Agreement, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of the Covered Tax Agreement, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Covered Tax Agreement. Before either granting or denying a request made under this paragraph by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction to which the request has been made shall consult with the competent authority of the first-mentioned Contracting Jurisdiction.

13. For the purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision:

- a) the term “recognised stock exchange” means:
 - i) any stock exchange established and regulated as such under the laws of either Contracting Jurisdiction; and
 - ii) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions;
- b) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or the class or classes of beneficial interests of an entity which represents in the aggregate a majority of the aggregate vote and value of the entity;
- c) the term “equivalent beneficiary” means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement under the domestic law of that Contracting Jurisdiction, the Covered Tax Agreement or any other international instrument which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under the Covered Tax Agreement; for the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to

dividends, the person shall be deemed to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds;

- d) with respect to entities that are not companies, the term “shares” means interests that are comparable to shares;
- e) two persons shall be “connected persons” if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) in each person; in any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.

14. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that would limit the benefits of the Covered Tax Agreement (or that would limit benefits other than a benefit under the provisions of the Covered Tax Agreement relating to residence, associated enterprises or non-discrimination or a benefit that is not restricted solely to residents of a Contracting Jurisdiction) only to a resident that qualifies for such benefits by meeting one or more categorical tests.

15. A Party may reserve the right:

- a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to adopt a combination of a detailed limitation on benefits provision and either rules to address conduit financing structures or a principal purpose test, thereby meeting the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package; in such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard;
- b) for paragraph 1 (and paragraph 4, in the case of a Party that has chosen to apply that paragraph) not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain provisions that deny all of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits;
- c) for the Simplified Limitation on Benefits Provision not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 14.

16. Except where the Simplified Limitation on Benefits Provision applies with respect to the granting of benefits under a Covered Tax Agreement by one or more Parties pursuant to paragraph 7, a Party that chooses pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements for which one or more of the other Contracting Jurisdictions has not chosen to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision. In such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package.

- 17. a) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 15 contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). In other cases, paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). A Party making a notification under this subparagraph may also include a statement that while such Party accepts the application of paragraph 1 alone as an interim measure, it intends

where possible to adopt a limitation on benefits provision, in addition to or in replacement of paragraph 1, through bilateral negotiation.

- b) Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depository of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification.
- c) Each Party that chooses to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6 shall notify the Depository of its choice. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision.
- d) Each Party that does not choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, but chooses to apply either subparagraph a) or b) of paragraph 7 shall notify the Depository of its choice of subparagraph. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision.
- e) Where all Contracting Jurisdictions have made a notification under subparagraph c) or d) with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the Simplified Limitation on Benefits Provision. In other cases, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the Simplified Limitation on Benefits Provision.

Article 8 – Dividend Transfer Transactions

1. Provisions of a Covered Tax Agreement that exempt dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Jurisdiction from tax or that limit the rate at which such dividends may be taxed, provided that the beneficial owner or the recipient is a company which is a resident of the other Contracting Jurisdiction and which owns, holds or controls more than a certain amount of the capital, shares, stock, voting power, voting rights or similar ownership interests of the company paying the dividends, shall apply only if the ownership conditions described in those provisions are met throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividends (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividends).

2. The minimum holding period provided in paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a minimum holding period in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1.

3. A Party may reserve the right:

- a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
- b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that the provisions described in paragraph 1 already include:
 - i) a minimum holding period;
 - ii) a minimum holding period shorter than a 365 day period; or
 - iii) a minimum holding period longer than a 365 day period.

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depository of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1 that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision.

Article 9 – Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

1. Provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction (or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property)):
 - a) shall apply if the relevant value threshold is met at any time during the 365 days preceding the alienation; and
 - b) shall apply to shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust (to the extent that such shares or interests are not already covered) in addition to any shares or rights already covered by the provisions.
2. The period provided in subparagraph a) of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a time period for determining whether the relevant value threshold in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1 was met.
3. A Party may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.
4. For purposes of a Covered Tax Agreement, gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction.
5. Paragraph 4 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction, or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property).
6. A Party may reserve the right:
 - a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
 - b) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
 - c) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
 - d) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that includes a period for determining whether the relevant value threshold was met;
 - e) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that applies to the alienation of interests other than shares;
 - f) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 5.
7. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision.
8. Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification. In such case, paragraph 1 shall not apply with respect to that Covered Tax Agreement. In the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph f) of paragraph 6 and has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with

respect to a provision of a Covered Tax Agreement under this paragraph or paragraph 7, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 4. In other cases, paragraph 4 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 4.

Article 10 – Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

1. Where:

- a) an enterprise of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives income from the other Contracting Jurisdiction and the first-mentioned Contracting Jurisdiction treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction; and
- b) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned Contracting Jurisdiction,

the benefits of the Covered Tax Agreement shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned Contracting Jurisdiction. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other Contracting Jurisdiction, notwithstanding any other provisions of the Covered Tax Agreement.

2. Paragraph 1 shall not apply if the income derived from the other Contracting Jurisdiction described in paragraph 1 is derived in connection with or is incidental to the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise's own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).

3. If benefits under a Covered Tax Agreement are denied pursuant to paragraph 1 with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of paragraphs 1 and 2. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under the preceding sentence by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before either granting or denying the request.

4. Paragraphs 1 through 3 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny or limit benefits that would otherwise be granted to an enterprise of a Contracting Jurisdiction which derives income from the other Contracting Jurisdiction that is attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction.

5. A Party may reserve the right:

- a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
- b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4;
- c) for this Article to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4.

6. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraphs 1 through 3. In other cases, paragraphs 1 through 3 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with those paragraphs.

Article 11 – Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

1. A Covered Tax Agreement shall not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents, except with respect to the benefits granted under provisions of the Covered Tax Agreement:

- a) which require that Contracting Jurisdiction to grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a correlative or corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contracting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of a permanent establishment of the enterprise or the profits of an associated enterprise;
- b) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual derives income in respect of services rendered to the other Contracting Jurisdiction or a political subdivision or local authority or other comparable body thereof;
- c) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual is also a student, business apprentice or trainee, or a teacher, professor, lecturer, instructor, researcher or research scholar who meets the conditions of the Covered Tax Agreement;
- d) which require that Contracting Jurisdiction to provide a tax credit or tax exemption to Jurisdiction may tax in accordance with the Covered Tax Agreement (including profits that are attributable to a permanent establishment situated in that other Contracting Jurisdiction in accordance with the Covered Tax Agreement);
- e) which protect residents of that Contracting Jurisdiction against certain discriminatory taxation practices by that Contracting Jurisdiction;
- f) which allow residents of that Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that or either Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement;
- g) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction when that individual is a member of a diplomatic mission, government mission or consular post of the other Contracting Jurisdiction;
- h) which provide that pensions or other payments made under the social security legislation of the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction;
- i) which provide that pensions and similar payments, annuities, alimony payments or other maintenance payments arising in the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction; or
- j) which otherwise expressly limit a Contracting Jurisdiction's right to tax its own residents or provide expressly that the Contracting Jurisdiction in which an item of income arises has the exclusive right to tax that item of income.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement stating that the Covered Tax Agreement would not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents.

3. A Party may reserve the right:

- a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
- b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 2.

4. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

PART IV.**AVOIDANCE OF PERMANENT ESTABLISHMENT STATUS*****Article 12 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies***

1. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, but subject to paragraph 2, where a person is acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:

- a) in the name of the enterprise; or
- b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or
- c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting Jurisdiction in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless these activities, if they were exercised by the enterprise through a fixed place of business of that enterprise situated in that Contracting Jurisdiction, would not cause that fixed place of business to be deemed to constitute a permanent establishment under the definition of permanent establishment included in the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention).

2. Paragraph 1 shall not apply where the person acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise of the other Contracting Jurisdiction carries on business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

- 3.
- a) Paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that describe the conditions under which an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction (or a person shall be deemed to be a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction) in respect of an activity which a person other than an agent of an independent status undertakes for the enterprise, but only to the extent that such provisions address the situation in which such person has, and habitually exercises, in that Contracting Jurisdiction an authority to conclude contracts in the name of the enterprise.
 - b) Paragraph 2 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that an enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction in respect of an activity which an agent of an independent status undertakes for the enterprise.

4. A Party may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements.

5. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph a) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision.

6. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 2 shall apply with respect to

a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision.

Article 13 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

1. A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) or paragraph 3 (Option B) or to apply neither Option.

Option A

2. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

- a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character;
- b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a);
- c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b),

provided that such activity or, in the case of subparagraph c), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

Option B

3. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

- a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character, except to the extent that the relevant provision of the Covered Tax Agreement provides explicitly that a specific activity shall be deemed not to constitute a permanent establishment provided that the activity is of a preparatory or auxiliary character;
- b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a), provided that this activity is of a preparatory or auxiliary character;
- c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4. A provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 or 3) that lists specific activities deemed not to constitute a permanent establishment shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting Jurisdiction and:

- a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of a Covered Tax Agreement defining a permanent establishment; or
- b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5.
 - a) Paragraph 2 or 3 shall apply in place of the relevant parts of provisions of a Covered Tax Agreement that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).
 - b) Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as they may be modified by paragraph 2 or 3) that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).
6. A Party may reserve the right:
 - a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
 - b) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements that explicitly state that a list of specific activities shall be deemed not to constitute a permanent establishment only if each of the activities is of a preparatory or auxiliary character;
 - c) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.
7. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in subparagraph a) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply the same Option and have made such a notification with respect to that provision.
8. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or c) of paragraph 6 and does not choose to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 4 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision under this paragraph or paragraph 7.

Article 14 – Splitting-up of Contracts

1. For the sole purpose of determining whether the period (or periods) referred to in a provision of a Covered Tax Agreement that stipulates a period (or periods) of time after which specific projects or activities shall constitute a permanent establishment has been exceeded:
 - a) where an enterprise of a Contracting Jurisdiction carries on activities in the other Contracting Jurisdiction at a place that constitutes a building site, construction project, installation project or other specific project identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement, or carries on supervisory or consultancy activities in connection with such a place, in the case of a provision of a Covered Tax Agreement that refers to such activities, and these activities are carried on during one or more periods of time that, in the aggregate, exceed 30 days without exceeding the period or periods referred to in the relevant provision of the Covered Tax Agreement; and
 - b) where connected activities are carried on in that other Contracting Jurisdiction at (or, where the relevant provision of the Covered Tax Agreement applies to supervisory or consultancy activities, in connection with) the same building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first-mentioned enterprise,

these different periods of time shall be added to the aggregate period of time during which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that such provisions address the division of contracts into multiple parts to avoid the application of

a time period or periods in relation to the existence of a permanent establishment for specific projects or activities described in paragraph 1.

3. A Party may reserve the right:

- a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
- b) for the entirety of this Article not to apply with respect to provisions of its Covered Tax Agreements relating to the exploration for or exploitation of natural resources.

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 to the extent provided in paragraph 2. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

Article 15 – Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

1. For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are modified by paragraph 2 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

2. A Party that has made the reservations described in paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), subparagraph a) or c) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), and subparagraph a) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts) may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to the Covered Tax Agreements to which those reservations apply.

PART V.

IMPROVING DISPUTE RESOLUTION

Article 16 – Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.

3. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement.

4.
 - a)
 - i) The first sentence of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement (or parts thereof) that provide that where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdiction result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a resident including provisions under which, if the case presented by that person comes under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, the case may be presented to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national.
 - ii) The second sentence of paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, or in the absence of a provision of a Covered Tax Agreement describing the time period within which such a case must be presented.
 - b)
 - i) The first sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authority that is presented with the case by the person referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement.
 - ii) The second sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.
 - c)
 - i) The first sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement.
 - ii) The second sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement.
5. A Party may reserve the right:
 - a) for the first sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer's objection to be justified;

- b) for the second sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that do not provide that the case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by ensuring that for the purposes of all such Covered Tax Agreements the taxpayer referred to in paragraph 1 is allowed to present the case within a period of at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement;
 - c) for the second sentence of paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that for the purposes of all of its Covered Tax Agreements:
 - i) any agreement reached via the mutual agreement procedure shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting Jurisdictions; or
 - ii) it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by accepting, in its bilateral treaty negotiations, a treaty provision providing that:
 - A) the Contracting Jurisdictions shall make no adjustment to the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting Jurisdictions after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have been attributable to the permanent establishment (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default); and
 - B) the Contracting Jurisdictions shall not include in the profits of an enterprise, and tax accordingly, profits that would have accrued to the enterprise but that by reason of the conditions referred to in a provision in the Covered Tax Agreement relating to associated enterprises have not so accrued, after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have accrued to the enterprise (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default).
6. a) Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in clause i) of subparagraph a) of paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the first sentence of paragraph 1. In other cases, the first sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with that sentence.
- b) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of:
- i) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; a provision of a Covered Tax Agreement shall be replaced by the second sentence of paragraph 1 where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision; in other cases, subject to clause ii), the second sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the second sentence of paragraph 1;
 - ii) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action

resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; the second sentence of paragraph 1 shall not apply to a Covered Tax Agreement where any Contracting Jurisdiction has made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.

- c) Each Party shall notify the Depositary of:
 - i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph b) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement;
 - ii) in the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 5, the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph b) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.
- d) Each Party shall notify the Depositary of:
 - i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph c) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement;
 - ii) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.

Article 17 – Corresponding Adjustments

1. Where a Contracting Jurisdiction includes in the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting Jurisdiction has been charged to tax in that other Contracting Jurisdiction and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting Jurisdiction shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Covered Tax Agreement and the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall if necessary consult each other.

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a provision that requires a Contracting Jurisdiction to make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction where the other Contracting Jurisdiction includes those profits in the profits of an enterprise of that other Contracting Jurisdiction and taxes those profits accordingly, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of that other Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises.

3. A Party may reserve the right:

- a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 2;
- b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in the absence of a provision referred to in paragraph 2 in its Covered Tax Agreement:
 - i) it shall make the appropriate adjustment referred to in paragraph 1; or

- ii) its competent authority shall endeavour to resolve the case under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to mutual agreement procedure;
- c) in the case of a Party that has made a reservation under clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure), for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in its bilateral treaty negotiations it shall accept a treaty provision of the type contained in paragraph 1, provided that the Contracting Jurisdictions were able to reach agreement on that provision and on the provisions described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure).

4. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

PART VI. ARBITRATION

Article 18 – Choice to Apply Part VI

A Party may choose to apply this Part with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. This Part shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.

Article 19 – Mandatory Binding Arbitration

1. Where:

- a) under a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 1 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that a person may present a case to a competent authority of a Contracting Jurisdiction where that person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention), a person has presented a case to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on the basis that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention); and
- b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that the competent authority shall endeavour to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, within a period of two years beginning on the start date referred to in paragraph 8 or 9, as the case may be (unless, prior to the expiration of that period the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have agreed to a different time period with respect to that case and have notified the person who presented the case of such agreement),

any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submitted to arbitration in the manner described in this Part, according to any rules or procedures agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions pursuant to the provisions of paragraph 10.

2. Where a competent authority has suspended the mutual agreement procedure referred to in paragraph 1 because a case with respect to one or more of the same issues is pending before court or administrative tribunal, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until either a final decision has been rendered by the court or administrative tribunal or the case has been suspended or withdrawn. In addition, where a person who presented a case and a competent authority have agreed to suspend the mutual agreement procedure, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until the suspension has been lifted.

3. Where both competent authorities agree that a person directly affected by the case has failed to provide in a timely manner any additional material information requested by either competent authority after the start of the period provided in subparagraph b) of paragraph 1, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 shall be extended for an amount of time equal to the period beginning on the date by which the information was requested and ending on the date on which that information was provided.

4. a) The arbitration decision with respect to the issues submitted to arbitration shall be implemented through the mutual agreement concerning the case referred to in paragraph 1. The arbitration decision shall be final.
- b) The arbitration decision shall be binding on both Contracting Jurisdictions except in the following cases:
- i) if a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision. In such a case, the case shall not be eligible for any further consideration by the competent authorities. The mutual agreement that implements the arbitration decision on the case shall be considered not to be accepted by a person directly affected by the case if any person directly affected by the case does not, within 60 days after the date on which notification of the mutual agreement is sent to the person, withdraw all issues resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision from consideration by any court or administrative tribunal or otherwise terminate any pending court or administrative proceedings with respect to such issues in a manner consistent with that mutual agreement.
- ii) if a final decision of the courts of one of the Contracting Jurisdictions holds that the arbitration decision is invalid. In such a case, the request for arbitration under paragraph 1 shall be considered not to have been made, and the arbitration process shall be considered not to have taken place (except for the purposes of Articles 21 (Confidentiality of Arbitration Proceedings) and 25 (Costs of Arbitration Proceedings)). In such a case, a new request for arbitration may be made unless the competent authorities agree that such a new request should not be permitted.
- iii) if a person directly affected by the case pursues litigation on the issues which were resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision in any court or administrative tribunal.

5. The competent authority that received the initial request for a mutual agreement procedure as described in subparagraph a) of paragraph 1 shall, within two calendar months of receiving the request:

- a) send a notification to the person who presented the case that it has received the request; and
- b) send a notification of that request, along with a copy of the request, to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction.

6. Within three calendar months after a competent authority receives the request for a mutual agreement procedure (or a copy thereof from the competent authority of the other Contracting Jurisdiction) it shall either:

- a) notify the person who has presented the case and the other competent authority that it has received the information necessary to undertake substantive consideration of the case; or
- b) request additional information from that person for that purpose.

7. Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, one or both of the competent authorities have requested from the person who presented the case additional information necessary to undertake substantive consideration of the case, the competent authority that requested the additional information shall, within three calendar months of receiving the additional information from that person, notify that person and the other competent authority either:

- a) that it has received the requested information; or

- b) that some of the requested information is still missing.
8. Where neither competent authority has requested additional information pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:
- a) the date on which both competent authorities have notified the person who presented the case pursuant to subparagraph a) of paragraph 6; and
 - b) the date that is three calendar months after the notification to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction pursuant to subparagraph b) of paragraph 5.
9. Where additional information has been requested pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:
- a) the latest date on which the competent authorities that requested additional information have notified the person who presented the case and the other competent authority pursuant to subparagraph a) of paragraph 7; and
 - b) the date that is three calendar months after both competent authorities have received all information requested by either competent authority from the person who presented the case.
- If, however, one or both of the competent authorities send the notification referred to in subparagraph b) of paragraph 7, such notification shall be treated as a request for additional information under subparagraph b) of paragraph 6.
10. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall by mutual agreement (pursuant to the article of the relevant Covered Tax Agreement regarding procedures for mutual agreement) settle the mode of application of the provisions contained in this Part, including the minimum information necessary for each competent authority to undertake substantive consideration of the case. Such an agreement shall be concluded before the date on which unresolved issues in a case are first eligible to be submitted to arbitration and may be modified from time to time thereafter.
11. For purposes of applying this Article to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right to replace the two-year period set forth in subparagraph b) of paragraph 1 with a three-year period.
12. A Party may reserve the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of this Article:
- a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by this Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;
 - b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Article 20 – Appointment of Arbitrators

- 1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, paragraphs 2 through 4 shall apply for the purposes of this Part.
- 2. The following rules shall govern the appointment of the members of an arbitration panel:
 - a) The arbitration panel shall consist of three individual members with expertise or experience in international tax matters.
 - b) Each competent authority shall appoint one panel member within 60 days of the date of the request for arbitration under paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration). The two panel members so appointed shall, within 60 days of the latter of their appointments, appoint a third member who shall serve as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not be a national or resident of either Contracting Jurisdiction.

- c) Each member appointed to the arbitration panel must be impartial and independent of the competent authorities, tax administrations, and ministries of finance of the Contracting Jurisdictions and of all persons directly affected by the case (as well as their advisors) at the time of accepting an appointment, maintain his or her impartiality and independence throughout the proceedings, and avoid any conduct for a reasonable period of time thereafter which may damage the appearance of impartiality and independence of the arbitrators with respect to the proceedings.

3. In the event that the competent authority of a Contracting Jurisdiction fails to appoint a member of the arbitration panel in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a member shall be appointed on behalf of that competent authority by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction.

4. If the two initial members of the arbitration panel fail to appoint the Chair in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, the Chair shall be appointed by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction.

Article 21 – Confidentiality of Arbitration Proceedings

1. Solely for the purposes of the application of the provisions of this Part and of the provisions of the relevant Covered Tax Agreement and of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions related to the exchange of information, confidentiality, and administrative assistance, members of the arbitration panel and a maximum of three staff per member (and prospective arbitrators solely to the extent necessary to verify their ability to fulfil the requirements of arbitrators) shall be considered to be persons or authorities to whom information may be disclosed. Information received by the arbitration panel or prospective arbitrators and information that the competent authorities receive from the arbitration panel shall be considered information that is exchanged under the provisions of the Covered Tax Agreement related to the exchange of information and administrative assistance.

2. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall ensure that members of the arbitration panel and their staff agree in writing, prior to their acting in an arbitration proceeding, to treat any information relating to the arbitration proceeding consistently with the confidentiality and nondisclosure obligations described in the provisions of the Covered Tax Agreement related to exchange of information and administrative assistance and under the applicable laws of the Contracting Jurisdictions.

Article 22 – Resolution of a Case Prior to the Conclusion of the Arbitration

For the purposes of this Part and the provisions of the relevant Covered Tax Agreement that provide for resolution of cases through mutual agreement, the mutual agreement procedure, as well as the arbitration proceeding, with respect to a case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions:

- a) the competent authorities of the Contracting Jurisdictions reach a mutual agreement to resolve the case; or
- b) the person who presented the case withdraws the request for arbitration or the request for a mutual agreement procedure.

Article 23 – Type of Arbitration Process

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding pursuant to this Part:

- a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a proposed resolution which addresses all unresolved issue(s) in the case (taking into account all agreements previously reached in that case between the competent authorities of the

Contracting Jurisdictions). The proposed resolution shall be limited to a disposition of specific monetary amounts (for example, of income or expense) or, where specified, the maximum rate of tax charged pursuant to the Covered Tax Agreement, for each adjustment or similar issue in the case. In a case in which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have been unable to reach agreement on an issue regarding the conditions for application of a provision of the relevant Covered Tax Agreement (hereinafter referred to as a “threshold question”), such as whether an individual is a resident or whether a permanent establishment exists, the competent authorities may submit alternative proposed resolutions with respect to issues the determination of which is contingent on resolution of such threshold questions.

- b) The competent authority of each Contracting Jurisdiction may also submit a supporting position paper for consideration by the arbitration panel. Each competent authority that submits a proposed resolution or supporting position paper shall provide a copy to the other competent authority by the date on which the proposed resolution and supporting position paper were due. Each competent authority may also submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a reply submission with respect to the proposed resolution and supporting position paper submitted by the other competent authority. A copy of any reply submission shall be provided to the other competent authority by the date on which the reply submission was due.
- c) The arbitration panel shall select as its decision one of the proposed resolutions for the case submitted by the competent authorities with respect to each issue and any threshold questions, and shall not include a rationale or any other explanation of the decision. The arbitration decision will be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration panel shall deliver its decision in writing to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. The arbitration decision shall have no precedential value.

2. For the purpose of applying this Article with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements. In such a case, except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding:

- a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall provide any information that may be necessary for the arbitration decision to all panel members without undue delay. Unless the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree otherwise, any information that was not available to both competent authorities before the request for arbitration was received by both of them shall not be taken into account for purposes of the decision.
- b) The arbitration panel shall decide the issues submitted to arbitration in accordance with the applicable provisions of the Covered Tax Agreement and, subject to these provisions, of those of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions. The panel members shall also consider any other sources which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may by mutual agreement expressly identify.
- c) The arbitration decision shall be delivered to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions in writing and shall indicate the sources of law relied upon and the reasoning which led to its result. The arbitration decision shall be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration decision shall have no precedential value.

3. A Party that has not made the reservation described in paragraph 2 may reserve the right for the preceding paragraphs of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements with Parties that have made such a reservation. In such a case, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions of each such Covered Tax Agreement shall endeavour to reach agreement on the type of arbitration process that shall apply with respect to that Covered Tax Agreement. Until such an agreement is reached, Article 19 (Mandatory Binding Arbitration) shall not apply with respect to such a Covered Tax Agreement.

4. A Party may also choose to apply paragraph 5 with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 5 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with

respect to a Covered Tax Agreement where either of the Contracting Jurisdictions has made such a notification.

5. Prior to the beginning of arbitration proceedings, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement shall ensure that each person that presented the case and their advisors agree in writing not to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration proceedings from either competent authority or the arbitration panel. The mutual agreement procedure under the Covered Tax Agreement, as well as the arbitration proceeding under this Part, with respect to the case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a person that presented the case or one of that person's advisors materially breaches that agreement.

6. Notwithstanding paragraph 4, a Party that does not choose to apply paragraph 5 may reserve the right for paragraph 5 not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements or with respect to all of its Covered Tax Agreements.

7. A Party that chooses to apply paragraph 5 may reserve the right for this Part not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to paragraph 6.

Article 24 – Agreement on a Different Resolution

1. For purposes of applying this Part with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may choose to apply paragraph 2 and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 2 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.

2. Notwithstanding paragraph 4 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), an arbitration decision pursuant to this Part shall not be binding on the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement and shall not be implemented if the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree on a different resolution of all unresolved issues within three calendar months after the arbitration decision has been delivered to them.

3. A Party that chooses to apply paragraph 2 may reserve the right for paragraph 2 to apply only with respect to its Covered Tax Agreements for which paragraph 2 of Article 23 (Type of Arbitration Process) applies.

Article 25 – Costs of Arbitration Proceedings

In an arbitration proceeding under this Part, the fees and expenses of the members of the arbitration panel, as well as any costs incurred in connection with the arbitration proceedings by the Contracting Jurisdictions, shall be borne by the Contracting Jurisdictions in a manner to be settled by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. In the absence of such agreement, each Contracting Jurisdiction shall bear its own expenses and those of its appointed panel member. The cost of the chair of the arbitration panel and other expenses associated with the conduct of the arbitration proceedings shall be borne by the Contracting Jurisdictions in equal shares.

Article 26 – Compatibility

1. Subject to Article 18 (Choice to Apply Part VI), the provisions of this Part shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide for arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case. Each Party that chooses to apply this Part shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains such a provision, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where two Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of this Part as between those Contracting Jurisdictions.

2. Any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for in this Part shall not be submitted to arbitration if the issue falls within the scope of a case with respect to which an arbitration panel or similar body has previously been set up in

accordance with a bilateral or multilateral convention that provides for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.

3. Subject to paragraph 1, nothing in this Part shall affect the fulfilment of wider obligations with respect to the arbitration of unresolved issues arising in the context of a mutual agreement procedure resulting from other conventions to which the Contracting Jurisdictions are or will become parties.

4. A Party may reserve the right for this Part not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or to all of its Covered Tax Agreements) that already provide for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.

PART VII.

FINAL PROVISIONS

Article 27 – Signature and Ratification, Acceptance or Approval

1. As of 31 December 2016, this Convention shall be open for signature by:
 - a) all States;
 - b) Guernsey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Isle of Man (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Jersey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); and
 - c) any other jurisdiction authorised to become a Party by means of a decision by consensus of the Parties and Signatories.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval.

Article 28 – Reservations

1. Subject to paragraph 2, no reservations may be made to this Convention except those expressly permitted by:
 - a) Paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);
 - b) Paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);
 - c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
 - d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
 - e) Paragraphs 15 and 16 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
 - f) Paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
 - g) Paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
 - h) Paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
 - i) Paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents);
 - j) Paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);
 - k) Paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
 - l) Paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
 - m) Paragraph 2 of Article 15 (Definition of a Person Closely Related to an Enterprise);
 - n) Paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
 - o) Paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
 - p) Paragraphs 11 and 12 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration);
 - q) Paragraphs 2, 3, 6, and 7 of Article 23 (Type of Arbitration Process);

- r) Paragraph 3 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);
 - s) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility);
 - t) Paragraphs 6 and 7 of Article 35 (Entry into Effect); and
 - u) Paragraph 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI).
2. a) Notwithstanding paragraph 1, a Party that chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) may formulate one or more reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI (Arbitration). For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations pursuant to this subparagraph shall be made at the same time as that Party's notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).
- b) Reservations made under subparagraph a) are subject to acceptance. A reservation made under subparagraph a) shall be considered to have been accepted by a Party if it has not notified the Depositary that it objects to the reservation by the end of a period of twelve calendar months beginning on the date of notification of the reservation by the Depositary or by the date on which it deposits its instrument of ratification, acceptance, or approval, whichever is later. For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, objections to prior reservations made by other Parties pursuant to subparagraph a) can be made at the time of the first-mentioned Party's notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI). Where a Party raises an objection to a reservation made under subparagraph a), the entirety of Part VI (Arbitration) shall not apply as between the objecting Party and the reserving Party.
3. Unless explicitly provided otherwise in the relevant provisions of this Convention, a reservation made in accordance with paragraph 1 or 2 shall:
- a) modify for the reserving Party in its relations with another Party the provisions of this Convention to which the reservation relates to the extent of the reservation; and
 - b) modify those provisions to the same extent for the other Party in its relations with the reserving Party.
4. Reservations applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the reservations made by that Party for its own Covered Tax Agreements.
5. Reservations shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval, subject to the provisions of paragraphs 2, 6 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications). However, for a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations described in subparagraphs p), q), r) and s) of paragraph 1 of this Article shall be made at the same time as that Party's notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).
6. If reservations are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the reservations explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 2, 5 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications).
7. If reservations are not made at the time of signature, a provisional list of expected reservations shall be provided to the Depositary at that time.
8. For reservations made pursuant to each of the following provisions, a list of agreements notified pursuant to clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) that are within the scope of the reservation as defined in the relevant provision (and, in the case of a reservation under any of

the following provisions other than those listed in subparagraphs c), d) and n), the article and paragraph number of each relevant provision) must be provided when such reservations are made:

- a) Subparagraphs b), c), d), e) and g) of paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);
- b) Subparagraphs b), c) and d) of paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);
- c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
- d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
- e) Subparagraphs b) and c) of paragraph 15 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
- f) Clauses i), ii), and iii) of subparagraph b) of paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
- g) Subparagraphs d), e) and f) of paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
- h) Subparagraphs b) and c) of paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
- i) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents);
- j) Subparagraph b) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
- k) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
- l) Subparagraph b) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
- m) Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
- n) Paragraph 6 of Article 23 (Type of Arbitration Process); and
- o) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility).

The reservations described in subparagraphs a) through o) above shall not apply to any Covered Tax Agreement that is not included on the list described in this paragraph.

9. Any Party which has made a reservation in accordance with paragraph 1 or 2 may at any time withdraw it or replace it with a more limited reservation by means of a notification addressed to the Depositary. Such Party shall make any additional notifications pursuant to paragraph 6 of Article 29 (Notifications) which may be required as a result of the withdrawal or replacement of the reservation. Subject to paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), the withdrawal or replacement shall take effect:

- a) with respect to a Covered Tax Agreement solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the notification of withdrawal or replacement of the reservation is received by the Depositary:
 - i) for reservations in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and
 - ii) for reservations in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and
- b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions.

Article 29 – Notifications

1. Subject to paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), notifications pursuant to the following provisions shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval:

- a) Clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms);
- b) Paragraph 6 of Article 3 (Transparent Entities);
- c) Paragraph 4 of Article 4 (Dual Resident Entities);
- d) Paragraph 10 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
- e) Paragraphs 5 and 6 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
- f) Paragraph 17 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
- g) Paragraph 4 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
- h) Paragraphs 7 and 8 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
- i) Paragraph 6 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
- j) Paragraph 4 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents);
- k) Paragraphs 5 and 6 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);
- l) Paragraphs 7 and 8 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
- m) Paragraph 4 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
- n) Paragraph 6 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
- o) Paragraph 4 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
- p) Article 18 (Choice to Apply Part VI);
- q) Paragraph 4 of Article 23 (Type of Arbitration Process);
- r) Paragraph 1 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);
- s) Paragraph 1 of Article 26 (Compatibility); and
- t) Paragraphs 1, 2, 3, 5 and 7 of Article 35 (Entry into Effect).

2. Notifications in respect of Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the notifications made by that Party for its own Covered Tax Agreements.

3. If notifications are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the notifications explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect).

4. If notifications are not made at the time of signature, a provisional list of expected notifications shall be provided at that time.

5. A Party may extend at any time the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) by means of a notification addressed to the Depositary. The Party shall specify in this notification whether the agreement falls within the scope of any of the reservations made by the Party which are listed in paragraph 8 of Article 28 (Reservations). The Party may also make a new reservation described in paragraph 8 of Article 28 (Reservations) if the additional agreement would be the first to fall within the scope of such a reservation. The Party shall also specify any additional notifications

that may be required under subparagraphs b) through s) of paragraph 1 to reflect the inclusion of the additional agreements. In addition, if the extension results for the first time in the inclusion of a tax agreement entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, the Party shall specify any reservations (pursuant to paragraph 4 of Article 28 (Reservations)) or notifications (pursuant to paragraph 2 of this Article) applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of that jurisdiction or territory. On the date on which the added agreement(s) notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) become Covered Tax Agreements, the provisions of Article 35 (Entry into Effect) shall govern the date on which the modifications to the Covered Tax Agreement shall have effect.

6. A Party may make additional notifications pursuant to subparagraphs b) through s) of paragraph 1 by means of a notification addressed to the Depositary. These notifications shall take effect:

- a) with respect to Covered Tax Agreements solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the additional notification is received by the Depositary:
 - i) for notifications in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and
 - ii) for notifications in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and
- b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the additional notification: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions.

Article 30 – Subsequent Modifications of Covered Tax Agreements

The provisions in this Convention are without prejudice to subsequent modifications to a Covered Tax Agreement which may be agreed between the Contracting Jurisdictions of the Covered Tax Agreement.

Article 31 – Conference of the Parties

1. The Parties may convene a Conference of the Parties for the purposes of taking any decisions or exercising any functions as may be required or appropriate under the provisions of this Convention.
2. The Conference of the Parties shall be served by the Depositary.
3. Any party may request a Conference of the Parties by communicating a request to the Depositary. The Depositary shall inform all Parties of any request. Thereafter, the Depositary shall convene a Conference of the Parties, provided that the request is supported by one-third of the Parties within six calendar months of the communication by the Depositary of the request.

Article 32 – Interpretation and Implementation

1. Any question arising as to the interpretation or implementation of provisions of a Covered Tax Agreement as they are modified by this Convention shall be determined in accordance with the provision(s) of the Covered Tax Agreement relating to the resolution by mutual agreement of questions of interpretation or application of the Covered Tax Agreement (as those provisions may be modified by this Convention).
2. Any question arising as to the interpretation or implementation of this Convention may be addressed by a Conference of the Parties convened in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).

Article 33 – Amendment

1. Any Party may propose an amendment to this Convention by submitting the proposed amendment to the Depositary.

2. A Conference of the Parties may be convened to consider the proposed amendment in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).

Article 34 – Entry into Force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval.
2. For each Signatory ratifying, accepting, or approving this Convention after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of the deposit by such Signatory of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 35 – Entry into Effect

1. The provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction with respect to a Covered Tax Agreement:
 - a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and
 - b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of six calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.
2. Solely for the purpose of its own application of subparagraph a) of paragraph 1 and subparagraph a) of paragraph 5, a Party may choose to substitute “taxable period” for “calendar year”, and shall notify the Depositary accordingly.
3. Solely for the purpose of its own application of subparagraph b) of paragraph 1 and subparagraph b) of paragraph 5, a Party may choose to replace the reference to “taxable periods beginning on or after the expiration of a period” with a reference to “taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period”, and shall notify the Depositary accordingly.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, Article 16 (Mutual Agreement Procedure) shall have effect with respect to a Covered Tax Agreement for a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, except for cases that were not eligible to be presented as of that date under the Covered Tax Agreement prior to its modification by the Convention, without regard to the taxable period to which the case relates.
5. For a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction:
 - a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after 30 days after the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements; and
 - b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of nine calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements.
6. A Party may reserve the right for paragraph 4 not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

7. a) A Party may reserve the right to replace:

- i) the references in paragraphs 1 and 4 to “the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”; and
- ii) the references in paragraph 5 to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”;

- iii) the references in subparagraph a) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to “on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation”; and
- iv) the reference in subparagraph b) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to “on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the withdrawal or replacement of the reservation with respect to that specific Covered Tax Agreement”;

- v) the references in subparagraph a) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to “on the date of the communication by the Depositary of the additional notification”; and
- vi) the reference in subparagraph b) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to “on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the additional notification with respect to that specific Covered Tax Agreement”;

- vii) the references in paragraphs 1 and 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”; and

- viii) the reference in paragraph 3 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”;
- ix) the references in paragraph 4 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation”, “the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation” and “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation”; and
- x) the reference in paragraph 5 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the additional notification”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in

paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of Part VI (Arbitration) with respect to that specific Covered Tax Agreement”.

- b) A Party making a reservation in accordance with subparagraph a) shall notify the confirmation of the completion of its internal procedures simultaneously to the Depositary and the other Contracting Jurisdiction(s).
- c) If one or more Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement makes a reservation under this paragraph, the date of entry into effect of the provisions of the Convention, of the withdrawal or replacement of a reservation, of an additional notification with respect to that Covered Tax Agreement, or of Part VI (Arbitration) shall be governed by this paragraph for all Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.

Article 36 – Entry into Effect of Part VI

1. Notwithstanding paragraph 9 of Article 28 (Reservations), paragraph 6 of Article 29 (Notifications), and paragraphs 1 through 6 of Article 35 (Entry into Effect), with respect to two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, the provisions of Part VI (Arbitration) shall have effect:

- a) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)), on or after the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and
- b) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, on the date when both Contracting Jurisdictions have notified the Depositary that they have reached mutual agreement pursuant to paragraph 10 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), along with information regarding the date or dates on which such cases shall be considered to have been presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)) according to the terms of that mutual agreement.

2. A Party may reserve the right for Part VI (Arbitration) to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.

3. In the case of a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”.

4. A withdrawal or replacement of a reservation made under paragraph 4 of Article 26 (Compatibility) pursuant to paragraph 9 of Article 28 (Reservations), or the withdrawal of an objection to a reservation made under paragraph 2 of Article 28 (Reservations) which results in the application of Part VI (Arbitration) between two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1 of this Article, except that the references to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation”, “the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation” or “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation”, respectively.

5. An additional notification made pursuant to subparagraph p) of paragraph 1 of Article 29 (Notifications) shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1, except that the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the additional notification”.

Article 37 - Withdrawal

1. Any Party may, at any time, withdraw from this Convention by means of a notification addressed to the Depositary.

2. Withdrawal pursuant to paragraph 1 shall become effective on the date of receipt of the notification by the Depositary. In cases where this Convention has entered into force with respect to all Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement before the date on which a Party's withdrawal becomes effective, that Covered Tax Agreement shall remain as modified by this Convention.

Article 38 – Relation with Protocols

1. This Convention may be supplemented by one or more protocols.

2. In order to become a party to a protocol, a State or jurisdiction must also be a Party to this Convention.

3. A Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a party to the protocol in accordance with its provisions.

Article 39 – Depositary

1. The Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development shall be the Depositary of this Convention and any protocols pursuant to Article 38 (Relation with Protocols).

2. The Depositary shall notify the Parties and Signatories within one calendar month of:

- a) any signature pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval);
- b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval);
- c) any reservation or withdrawal or replacement of a reservation pursuant to Article 28 (Reservations);
- d) any notification or additional notification pursuant to Article 29 (Notifications);
- e) any proposed amendment to this Convention pursuant to Article 33 (Amendment);
- f) any withdrawal from this Convention pursuant to Article 37 (Withdrawal); and
- g) any other communication related to this Convention.

3. The Depositary shall maintain publicly available lists of:

- a) Covered Tax Agreements;
- b) reservations made by the Parties; and
- c) notifications made by the Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Paris, the 24th day of November 2016, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

India

Status of List of Reservations and Notifications upon Deposit of the Instrument of Ratification

This document contains the list of reservations and notifications made by India upon deposit of the instrument of ratification pursuant to Articles 28(5) and 29(1) of the Convention.

Article 2 – Interpretation of Terms***Notification - Agreements Covered by the Convention***

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention, India wishes the following agreement(s) to be covered by the Convention:

No	Title	Other Contracting Jurisdiction	Original/ Amending Instrument	Date of Signature	Date of Entry into Force
1	Agreement between the Government of the Republic of India and The Republic of Albania for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Albania	Original	08.07.2013	04.12.2013
2	Convention between the Government of the Republic of India and The Government of the Republic of Armenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income.	Armenia	Original	31.10.2003	09.09.2004 ¹
			Amending Instrument (a)	27.01.2016	14.06.2017
3	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Australia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Australia	Original	25.07.1991	30.12.1991
			Amending Instrument(a)	16.12.2011	02.04.2013
4	Convention between the Government of the Republic of India and The Government of the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income.	Austria	Original	08.11.1999	05.09.2001
			Amending Instrument (a)	06.02.2017	N/A
5	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Bangladesh	Original	27-08-1991	27-05-1992
			Amending Instrument (a)	16-02-2013	13-06-2013
6	Agreement between the Government of the Republic of India and The Republic of Belarus for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Property (Capital).	Belarus (Part of USSR)	Original	27.09.1997	17.07.1998
			Amending Instrument (a)	03.06.2015	19.11.2015
7	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Belgium	Original	26.04.1993	01.10.1997
			Amending Instrument (a)	09.03.2017	N/A
8	Agreement between the Government of the Republic of India and the Royal	Bhutan	Original	04-03-2013	17-07-2014

¹ India understands that Armenia considers that the treaty entered into force on 01.04.2004

	Government of Bhutan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income				
9	Convention between India and Botswana for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect of Taxes on income	Botswana	Original	08-12-2006	30-01-2008
10	Convention between the government of the Republic of India and the government of the Federation Republic of Brazil for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Brazil	Original	26.04.1988	11.03.1992
			Amending Instrument (a)	15.10.2013	06.08.2017
11	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Bulgaria for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Bulgaria	Original	26.05.1994	23.06.1995
12	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Canada for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Canada	Original	11.01.1996	06.05.1997
13	Convention between the government of the Republic of India and the government of the Republic of Colombia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Colombia	Original	13.05.2011	07.07.2014
14	Agreement between The Government of the Republic of India and The Government of the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income.	Croatia	Original	12.02.2014	06.02.2015 ²
15	Agreement and Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Cyprus for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Cyprus	Original	18.11.2016	14.12.2016
16	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Czech Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Czech Republic	Original	01.10.1998	27.09.1999

² India understands that Croatia considers that the treaty entered into force on 11.02.2015

17	Convention between the Republic of India and the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital.	Denmark	Original	08.03.1989	13.06.1989
			Amending Instrument (a)	10.10.2013	01.02.2015
18	Agreement between India and Egypt for the Avoidance of Double taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Egypt	Original	20-02-1969	30-09-1969
19	Agreement between the Republic of India and the Republic of Estonia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Estonia	Original	19.09.2011	20.06.2012
20	Convention Between India and Ethiopia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital Gains.	Ethiopia	Original	25-05-2011	15-10-2012
21	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Fiji for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Fiji	Original	30.01.2014	15.05.2014
22	Agreement and Protocol between the Republic of India and the Republic of Finland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Finland	Original	15.01.2010	19.04.2010
23	Convention between the Government of Republic of India and the Government of the French Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	France	Original	29.09.1992	01.08.1994
24	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Georgia for the Avoidance of Double Taxation of Income and on Capital.	Georgia	Original	24.08.2011	08.12.2011
25	Agreement between the Republic of India and the Federal Republic of Germany for the Avoidance of Double Taxation of Income and on Capital.	Germany	Original	19.06.1995	26.10.1996
26	Agreement between the Government of India and the Government of Greece for the Avoidance of Double Taxation of Income.	Greece	Original	11.02.1965	17.03.1967
27	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China for the Avoidance of	Hong Kong	Original	19.03.2018	30.11.2018

	Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income				
28	Agreement between the Government of India and the Government of Hungary for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Hungary	Original	03.11.2003	04.03.2005
29	Agreement between the Republic of India and the Government of Iceland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Iceland	Original	23.11.2007	21.12.2007
30	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Indonesia	Original	27-07-2012	05-02-2016
31	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Ireland for the Avoidance of Double Taxation and for the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains.	Ireland	Original	06.11.2000	26.12.2001 ³
32	Convention between the Republic of India and the State of Israel for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital	Israel	Original	29-01-1996	15-05-1996
			Amending Instrument (a)	14-10-2015	19-12-2016
33	Convention between the Government of Republic of India and the Government of the Republic of Italy for Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Italy	Original	19.02.1993	23.11.1995
34	Convention between the government of the Republic of India and the government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Japan	Original	07.03.1989	29.12.1989
			Amending Instrument (a)	24.02.2006	28.06.2006
			Amending Instrument (b)	11.12.2015	29.10.2016
35	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Jordan	Original	20-04-1999	16-10-1999
36	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Kazakhstan for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal	Kazakstan	Original	09-12-1996	02-10-1997
			Amending Instrument (a)	06-01-2017	12-03-2018

³ India understands that Ireland considers that the treaty entered into force on 27.12.2001

	evasion with respect to taxes on income and on capital				
37	Agreement between India and Kenya for the Avoidance of Double taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Kenya	Original	11-07-2016	30-08-2017
38	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Korea	Original	18-05-2015	12-09-2016
39	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Kuwait	Original	15-06-2006	17-10-2007
			Amending Instrument (a)	15-01-2017	26-03-2018
40	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Kyrgyz Republic for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Kyrgyz Republic	Original	13-04-1999	10-01-2001
41	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Latvia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Latvia	Original	18.09.2013	28.12.2013
42	Convention Government of India and Libya for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income	Libya	Original	02-03-1981	01-07-1982
43	Agreement and the protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Lithuania for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Lithuania	Original	26.07.2011	10.07.2012
44	Agreement between the Government of Republic of India and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg for Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital.	Luxembourg	Original	02.06.2008	09.07.2009
45	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Macedonia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Macedonia	Original	17.12.2013	12.09.2014
46	Agreement between the Government of the Republic of India and the	Malaysia	Original	09-05-2012	26-12-2012

	Government of Malaysia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income				
47	Agreement and the Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Malta for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Malta	Original	08.04.2013	07.02.2014
48	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Mauritius for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Mauritius	Original	24.08.1982	06.12.1983
			Amending Instrument (a)	10.05.2016	19.07.2016
49	Agreement and Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income	Mexico	Original	10.09.2007	01.02.2010
50	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Mongolia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital	Mongolia	Original	22-02-1994	29-03-1996
51	Convention between the Republic Of India and the Government of the Council of Ministers of Serbia and Montenegro for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Montenegro	Original	08.02.2006	23.09.2008
52	Convention between the Republic of India and the Kingdom of Morocco for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Morocco	Original	30.10.1998	20.02.2000
			Amending Instrument (a)	08.08.2013	N/A
53	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mozambique for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Mozambique	Original	30.09.2010	28.02.2011
54	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Union of Myanmar for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Myanmar	Original	02-04-2008	30-01-2009
55	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Namibia	Namibia	Original	15.02.1997	22.01.1999

	for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains				
56	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Nepal for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Nepal	Original	27-11-2011	16-03-2012
57	Convention between the Government of Republic of India and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Netherlands	Original	30.07.1988	21.01.1989
			Amending Instrument (a)	10.05.2012	02.11.2012
58	Convention between the Republic of India and the Government of New Zealand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	New Zealand	Original	17.10.1986	03.12.1986
			Amending Instrument (a)	29.08.1996	09.01.1997
			Amending Instrument (b)	21.06.1999	30.12.1999 ⁴
			Amending Instrument (c)	26.10.2016	07.09.2017
59	Agreement Between the Republic of India and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Norway	Original	02.02.2011	20.12.2011
60	Agreement between the Republic of India and the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Oman	Original	02-04-1997	03-06-1997
61	Convention between the Republic of India and the Republic of the Philippines for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Philippines	Original	12-02-1990	21-03-1994
62	Agreement between the Government of Republic of India for the Government of Polish People's Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Poland	Original	21.06.1989	26.10.1989
			Amending Instrument (a)	29.01.2013	01.06.2014
63	Convention between the Government of Republic of India and the Government of the Portuguese Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Portugal	Original	11.09.1998	30.04.2000 ⁵
			Amending Instrument (a)	24.06.2017	08.08.2018

⁴ India understands that New Zealand considers that the Second Protocol entered into force on 17/12/1999.

⁵ India understands that Portugal considers that the treaty entered into force on 5.4.2000

64	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Qatar	Original	07-04-1999	15-01-2000
65	Agreement between the Republic of India and Romania for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Romania	Original	08.03.2013	16.12.2013
66	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on Income.	Russia	Original	25.03.1997	11.04.1998
67	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income	Saudi Arabia	Original	25-01-2006	01-11-2006
68	Convention between the Republic Of India and the Government of the Council of Ministers of Serbia And Montenegro for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Serbia	Original	08.02.2006	23.09.2008
69	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Singapore	Original	24-01-1994	27-05-1994
			Amending Instrument (a)	29-06-2005	01-08-2005
			Amending Instrument (b)	24-06-2011	01-09-2011
			Amending Instrument (c)	30-12-2016	27/02/2017
70	Agreement between the Government of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic for the Avoidance of Double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.	Slovak Republic	Original	27.01.1986	13.03.1987
71	Convention between the Republic Of India and the Republic of Slovenia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Slovenia	Original	13.01.2003	17.02.2005
			Amending Instrument (a)	17.5.2016	21.12.2016
72	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of South Africa for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	South Africa	Original	04.12.1996	28.11.1997
			Amending Instrument (a)	26.7.2013	26.11.2014
73	Convention between the Republic Of	Spain	Original	08.02.1993	12.01.1995

	India and the Kingdom of Spain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.		Amending Instrument (a)	26.10.2012	N/A
74	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Sri Lanka	Original	22-01-2013	22-10-2013
75	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Sudan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Sudan	Original	22.10.2003	15.04.2004
76	Convention between the Republic of India and the Government of Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Sweden	Original	24.06.1997	25.12.1997
			Amending Instrument (a)	07.02.2013	16.08.2013
77	Agreement between the Government of India and Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Swiss Confederation	Original	02.11.1994	29.12.1994
			Amending Instrument (a)	16.02.2000	20.12.2000
			Amending Instrument (b)	30.08.2010	07.10.2011
78	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Syrian Arab Republic for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Syria	Original	18-06-2008	10-11-2008
79	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Tajikistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Tajikistan	Original	20-11-2008	10-04-2009
			Amending Instrument (a)	17-12-2016	20-02-2018
80	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Republic of Tanzania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Tanzania	Original	27.05.2011	12.12.2011
81	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Thailand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Thailand	Original	29-06-2015	13-10-2015 ⁶

⁶ India understands that Thailand considers that the treaty entered into force on 05/01/2016.

82	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Trinidad and Tobago for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Trinidad and Tobago	Original	08.02.1999	13.10.1999
83	Agreement between the Government of Republic of India and the Republic of Turkey for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	Turkey	Original	31.01.1995	01.02.1997 ⁷
84	Convention between the Government of Republic of India and the Government of Turkmenistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital	Turkmenistan	Original	25-02-1997	07-07-1997
85	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uganda for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Uganda	Original	30.04.2004	27.08.2004
86	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Ukraine for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital.	Ukraine	Original	07.04.1999	31.10.2001
87	An Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital	United Arab Emirates	Original	29-04-1992	22-09-1993
			Amending Instrument (a)	26-03-2007	03-10-2007
			Amending Instrument (b)	16-04-2012	12-03-2013
88	Convention between the Government of Republic of India and the Government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.	United Kingdom	Original	25.01.1993	26.10.1993 ⁸
			Amending Instrument (a)	30.10.2012	27.12.2013
89	Convention between the government of the Republic of India and the government of the Oriental Republic of Uruguay for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income	Uruguay	Original	08.09.2011	21.06.2013
90	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of	USA	Original	12.09.1989	18.12.1990

⁷ India understands that Turkey considers that the treaty entered into force on 30.12.1996

⁸ India understands that UK considers that the treaty entered into force on 25.10.1993

	America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.				
91	Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uzbekistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital	Uzbekistan	Original	29-07-1993	25-01-1994
			Amending Instrument (a)	11-04-2012	20-07-2012
92	Agreement between the Republic of India and the Socialist Republic of Vietnam for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Vietnam	Original	07-09-1994	02-02-1995
			Amending Instrument (a)	03-09-2016	21-02-2017
93	Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Zambia for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income	Zambia	Original	05.06.1981	18.01.1984

Article 3 – Transparent Entities

Reservation

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention, India reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements

Article 4 – Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention, India considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) through (d). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Albania	Article 4(3)
2	Armenia	Article 4(3)
3	Australia	Article 4(3)
4	Austria	Article 4(3)
5	Bangladesh	Article 4(3)
6	Belarus	Article 4(3)
7	Belgium	Article 4(3)
8	Bhutan	Article 4(3)
9	Botswana	Article 4(3)
10	Brazil	Article 4 (3)
11	Bulgaria	Article 4(3)
12	Canada	Article 4(3)

13	Colombia	Article 4 (3)
14	Croatia	Article 4(3)
15	Cyprus	Article 4(3)
16	Czech Republic	Article 4(3)
17	Denmark	Article 4(3)
18	Egypt	Article 4(3)
19	Estonia	Article 4(3)
20	Ethiopia	Article 4(3)
21	Fiji	Article 4(3)
22	Finland	Article 4(3)
23	France	Article 4(3)
24	Georgia	Article 4(3)
25	Germany	Article 4(3)
27	Hong Kong	Article 4(3)
28	Hungary	Article 4(3)
29	Iceland	Article 4(3)
30	Indonesia	Article 4(3)
31	Ireland	Article 4(3)
32	Israel	Article 4(3)
33	Italy	Article 4(3)
34	Japan	Article 4 (2)
35	Jordan	Article 4(3)
36	Kazakstan	Article 4(3)
37	Kenya	Article 4(3)
38	Korea	Article 4(3)
39	Kuwait	Article 4(4)
40	Kyrgyz Republic	Article 4(3)
41	Latvia	Article 4(3)
43	Lithuania	Article 4(3)
44	Luxembourg	Article 4(3)
45	Macedonia	Article 4(3)
46	Malaysia	Article 4(3)
47	Malta	Article 4(3)
48	Mauritius	Article 4(3)
49	Mexico	Article 4(3)
50	Mongolia	Article 4(3)
51	Montenegro	Article 4(3)

52	Morocco	Article 4(3)
53	Mozambique	Article 4(3)
54	Myanmar	Article 4(3)
55	Namibia	Article 4(3)
56	Nepal	Article 4(3)
57	Netherlands	Article 4(3)
58	New Zealand	Article 4(3)
59	Norway	Article 4(3)
60	Oman	Article 4(3)
61	Philippines	Article 4(3)
62	Poland	Article 4(3)
63	Portugal	Article 4(3)
64	Qatar	Article 4(3)
65	Romania	Article 4(3)
66	Russia	Article 4(3)
67	Saudi Arabia	Article 4(3)
68	Serbia	Article 4(3)
69	Singapore	Article 4(3)
70	Slovak Republic	Article 4(3)
71	Slovenia	Article 4(3)
72	South Africa	Article 4(3)
73	Spain	Article 4(3)
74	Sri Lanka	Article 4(3)
75	Sudan	Article 4(3)
76	Sweden	Article 4(3)
77	Swiss Confederation	Article 4(3)
78	Syria	Article 4(3)
79	Tajikistan	Article 4(3)
80	Tanzania	Article 4(3)
81	Thailand	Article 4(3)
82	Trinidad & Tobago	Article 4(3)
83	Turkey	Article 4(3)
84	Turkmenistan	Article 4(3)
85	Uganda	Article 4(3)
86	Ukraine	Article 4(3)
87	United Arab Emirates	Article 4(4)
88	United Kingdom	Article 4(3)

89	Uruguay	Article 4 (3)
90	USA	Article 4(3) and (4)
91	Uzbekistan	Article 4(3)
92	Vietnam	Article 4(3)
93	Zambia	Article 4(3)

Article 5 – Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 5(10) of the Convention, India hereby chooses under Article 5(1) to apply Option C of that Article.

For jurisdictions choosing Option C:

Pursuant to Article 5(10) of the Convention, India considers that the following agreement(s) contain(s) a provision described in Article 5(7). The article and paragraph number of each such provision is identified below

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
11	Bulgaria	Article 25(2),(3)
18	Egypt	Article 24(1),(2)
26	Greece	Article XVII (2),(4)
70	Slovak Republic	Article 23(2),(3)

Article 7 – Prevention of Treaty Abuse

Statement of Acceptance of the PPT as an Interim Measure

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention, India hereby expresses a statement that while India accepts the application of Article 7(1) alone as an interim measure, it intends where possible to adopt a limitation on benefits provision, in addition to or in replacement of Article 7(1), through bilateral negotiation.

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(c) of the Convention, India hereby chooses to apply Simplified LOB provision pursuant to Article 7(6).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention, India considers that the following agreements are not subject to a reservation under Article 7(15)(b) and contain(s) a provision described in Article 7(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Albania	Article 29 (6)
8	Bhutan	Article 27(2) and (3)
13	Colombia	Article 28 (2) and (3)
19	Estonia	Article 28(2) through (4)
20	Ethiopia	Article 28(2) and (3)
21	Fiji	Article 28(2) and (3)
22	Finland	Article 27 (1) and (2)
24	Georgia	Article 30 (2) through (4)

29	Iceland	Article 24(6)
30	Indonesia	Article 24(2) and (3)
32	Israel	Article 27A(1)
36	Kazakhstan	Article 28A(2)
37	Kenya	Article 29(2) and (3)
38	Korea	Article 28(2)
39	Kuwait	Article 27
41	Latvia	Article 28 (1)
43	Lithuania	Article 30 (1) and (2)
44	Luxembourg	Article 29 (2) and (3)
45	Macedonia	Article 28(2) through (4)
46	Malaysia	Article 28(2) and (3)
47	Malta	Article 27(2) and (3)
49	Mexico	Article 28 (6)
53	Mozambique	Article 28
54	Myanmar	Article 27(1) and (2)
56	Nepal	Article 28
59	Norway	Article 29
62	Poland	Article 28A
65	Romania	Article 27
74	Sri Lanka	Article 28(6)
78	Syria	Article 27
79	Tajikistan	Article 28(6)
80	Tanzania	Article 28(6)
87	United Arab Emirates	Article 29
88	United Kingdom	Article 28C
89	Uruguay	Article 29 (7)
91	Uzbekistan	Article 28B(2) and (3)

Pursuant to Article 7(17)(c) of the Convention, India considers that the following agreements contain a provision described in Article 7(14). The Article and Paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Albania	Article 29 (1) through (5)
2	Armenia	Article 28
29	Iceland	Article 24 (1) through (5)
49	Mexico	Article 28(1) through (5)
74	Sri Lanka	Article 28(1) through (5)

79	Tajikistan	Article 28 (1) through (5)
80	Tanzania	Article 28(1) through (5)
89	Uruguay	Article 29 (2) through (6)
90	USA	Article 24

Article 8 – Dividend Transfer Transactions

Reservation

Pursuant to Article 8(3)(b)(iii) of the Convention, India reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that the provisions described in Article 8(1) already include a minimum holding period longer than a 365 day period. The following agreement contains provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
63	Portugal	Article 10(2)

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 8(4) of the Convention, India considers that the following agreements contain a provision described in Article 8(1) that is not subject to a reservation described in Article 8(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
5	Bangladesh	Article 11(2)(a)
6	Belarus	Article 10(2)(a)
9	Botswana	Article 10(2)(a)
12	Canada	Article 10(2)(a)
14	Croatia	Article 10(2)(a)
17	Denmark	Article 11(2)(a)
33	Italy	Article 11(2)(a)
43	Lithuania	Article 10(2)(a)
48	Mauritius	Article 10(2)(a)
51	Montenegro	Article 10(2)(1)
56	Nepal	Article 10(2)(a)
60	Oman	Article 11(2)(a)
61	Philippines	Article 11(2)(a)
64	Qatar	Article 10(2)(a)
68	Serbia	Article 10(2)(1)
69	Singapore	Article 10(2)(a)
70	Slovak Republic	Article 10(2)(a)
71	Slovenia	Article 10(2)(a)
78	Syria	Article 10(2)(a)
79	Tajikistan	Article 10(2)(a)

80	Tanzania	Article 10(2)(a)
86	Ukraine	Article 10(2)(a)
90	USA	Article 10(2)(a)
93	Zambia	Article 10(2)(a)

Article 9 – Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention, India hereby chooses to apply Article 9(4).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(7) of the Convention, India considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(1). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
2	Armenia	Article 13(4)
3	Australia	Article 13(4)
4	Austria	Article 13(4)
6	Belarus	Article 13(4)
7	Belgium	Article 13(4)
8	Bhutan	Article 13(4)
9	Botswana	Article 13(4)
11	Bulgaria	Article 14(4)
13	Colombia	Article 13 (4)
14	Croatia	Article 13(4)
15	Cyprus	Article 13(4)
16	Czech Republic	Article 13(4)
17	Denmark	Article 14(4)
19	Estonia	Article 13(2)
20	Ethiopia	Article 13(4)
21	Fiji	Article 13(4)
23	France	Article 14(4)
24	Georgia	Article 13(4)
27	Hong Kong	Article 14(4)
28	Hungary	Article 13(2)
29	Iceland	Article 13(4)
30	Indonesia	Article 13(4)
31	Ireland	Article 13(4)
32	Israel	Article 14(4)
33	Italy	Article 14(4)

35	Jordan	Article 13(4)
36	Kazakstan	Article 13(4)
37	Kenya	Article 14(4)
38	Korea	Article 13(4)
39	Kuwait	Article 13(4)
40	Kyrgyz Republic	Article 13(4)
41	Latvia	Article 13(4)
44	Luxembourg	Article 13(4)
45	Macedonia	Article 13(4)
46	Malaysia	Article 14(4)
49	Mexico	Article 13(4)
50	Mongolia	Article 13(4)
51	Montenegro	Article 14(4)
52	Morocco	Article 13(4)
53	Mozambique	Article 13(4)
54	Myanmar	Article 13(4)
55	Namibia	Article 13(4)
56	Nepal	Article 13(4)
57	Netherlands	Article 13(4)
58	New Zealand	Article 13(4)
60	Oman	Article 15(4)
61	Philippines	Article 14(4)
62	Poland	Article 14(4)
63	Portugal	Article 13(4)
64	Qatar	Article 13(4)
67	Saudi Arabia	Article 13(4)
68	Serbia	Article 14(4)
70	Slovak Republic	Article 13(4)
71	Slovenia	Article 13(4)
72	South Africa	Article 13(4)
73	Spain	Article 14(4)
74	Sri Lanka	Article 13(4)
75	Sudan	Article 13(4)
76	Sweden	Article 13(4)
77	Swiss Confederation	Article 13(4)
80	Tanzania	Article 13(4)
81	Thailand	Article 13(4)

82	Trinidad & Tobago	Article 13(4)
83	Turkey	Article 13(4)
84	Turkmenistan	Article 13(4)
85	Uganda	Article 13(4)
86	Ukraine	Article 13(4)
87	United Arab Emirates	Article 13(3)
89	Uruguay	Article 13 (4)
91	Uzbekistan	Article 14(4)
92	Vietnam	Article 14(4)

Article 12 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(5) of the Convention, India considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Albania	Article 5 (5)(a)
2	Armenia	Article 5 (5)(a)
3	Australia	Article 5(5)(a)
4	Austria	Article 5 (5)(a)
5	Bangladesh	Article 5 (4)(a)
6	Belarus	Article 5 (4)(a)
7	Belgium	Article 5 (4)(a)
8	Bhutan	Article 5 (5)(a)
9	Botswana	Article 5(5) (a)
10	Brazil	Article 5 (4)
11	Bulgaria	Article 5 (4)(a)
12	Canada	Article 5 (4)(a)
13	Colombia	Article 5(5) (a)
14	Croatia	Article 5 (6)(a)
15	Cyprus	Article 5 (5)(a)
16	Czech Republic	Article 5 (5)(a)
17	Denmark	Article 5 (4)(a)
18	Egypt	Article 5(4)(i)
19	Estonia	Article 5 (5)(a)
20	Ethiopia	Article 5(5)(a)
21	Fiji	Article 5(5)(a)
22	Finland	Article 5 (5) (a)

23	France	Article 5 (5) (a)
24	Georgia	Article 5 (5) (a)
25	Germany	Article 5 (5) (a)
26	Greece	Article II(1)(h)(dd)(1)
27	Hong Kong	Article 5 (5) (a)
28	Hungary	Article 5 (5) (a)
29	Iceland	Article 5 (5) (a)
30	Indonesia	Article 5 (5) (a)
31	Ireland	Article 5 (6) (a)
32	Israel	Article 5 (5)
33	Italy	Article 5 (4) (a)
34	Japan	Article 5(7) (a)
35	Jordan	Article 5 (6)
36	Kazakstan	Article 5 (5)
37	Kenya	Article 5(5) (a)
38	Korea	Article 5 (5) (a)
39	Kuwait	Article 5 (6) (a)
40	Kyrgyz Republic	Article 5 (6) (a)
41	Latvia	Article 5 (5) (a)
42	Libya	Article 4(4)
43	Lithuania	Article 5 (5) (a)
44	Luxembourg	Article 5 (5) (a)
45	Macedonia	Article 5(5) (a)
46	Malaysia	Article 5 (5) (a)
47	Malta	Article 5(5)(a)
48	Mauritius	Article 5(4)(i)
49	Mexico	Article 5 (5) (a)
50	Mongolia	Article 5 (4)
51	Montenegro	Article 5(5)(1)
52	Morocco	Article 5(5)
53	Mozambique	Article 5(5) (a)
54	Myanmar	Article 5 (5) (a)
55	Namibia	Article 5(5) (a)
56	Nepal	Article 5 (5) (a)
57	Netherlands	Article 5(5) (a)
58	New Zealand	Article 5(4) (a)
59	Norway	Article 5(5) (a)

60	Oman	Article 5 (4)
61	Philippines	Article 5 (4) (a)
62	Poland	Article 5(4) (a)
63	Portuguese Republic	Article 5(5) (a)
64	Qatar	Article 5 (6) (a)
65	Romania	Article 5(5)(a)
66	Russia	Article 5(4) (a)
67	Saudi Arabia	Article 5 (5) (a)
68	Serbia	Article 5(5)(1)
69	Singapore	Article 5 (8) (a)
70	Slovak Republic	Article 5(4) (a)
71	Slovenia	Article 5(5) (a)
72	South Africa	Article 5(5)
73	Spain	Article 5(4) (a)
74	Sri Lanka	Article 5 (5) (a)
75	Sudan	Article 5(5) (a)
76	Sweden	Article 5(6) (a)
77	Swiss Confederation	Article 5(5)(i)
78	Syria	Article 5 (5) (a)
79	Tajikistan	Article 5 (5)
80	Tanzania	Article 5(5) (a)
81	Thailand	Article 5 (5) (a)
82	Trinidad & Tobago	Article 5 (4) (a)
83	Turkey	Article 5(4) (a)
84	Turkmenistan	Article 5 (5) (a)
85	Uganda	Article 5(4) (a)
86	Ukraine	Article 5(5) (a)
87	United Arab Emirates	Article 5 (4)
88	United Kingdom	Article 5(4) (a)
89	Uruguay	Article 5 (5) (a)
90	USA	Article 5 (4) (a)
91	Uzbekistan	Article 5 (4)
92	Vietnam	Article 5 (4) (a)
93	Zambia	Article 5(4) (i)

Pursuant to Article 12(6) of the Convention, India considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Albania	Article 5 (7)
2	Armenia	Article 5 (7)
3	Australia	Article 5(6)
4	Austria	Article 5 (6)
5	Bangladesh	Article 5 (5)
6	Belarus	Article 5 (5)
7	Belgium	Article 5 (5)
8	Bhutan	Article 5 (7)
9	Botswana	Article 5(7)
10	Brazil	Article 5 (5)
11	Bulgaria	Article 5 (5)
12	Canada	Article 5 (5)
13	Colombia	Article 5(7)
14	Croatia	Article 5 (8)
15	Cyprus	Article 5 (7)
16	Czech Republic	Article 5 (7)
17	Denmark	Article 5 (5)
18	Egypt	Article 5(5)
19	Estonia	Article 5 (6)
20	Ethiopia	Article 5(6)
21	Fiji	Article 5(7)
22	Finland	Article 5 (7)
23	France	Article 5 (6)
24	Georgia	Article 5 (7)
25	Germany	Article 5 (6)
26	Greece	Article II (1)(h)(ee)
27	Hong Kong	Article 5 (6)
28	Hungary	Article 5 (6)
29	Iceland	Article 5 (7)
30	Indonesia	Article 5 (7)
31	Ireland	Article 5 (8)
32	Israel	Article 5 (6)
33	Italy	Article 5 (5)
34	Japan	Article 5(8)
35	Jordan	Article 5 (8)
36	Kazakstan	Article 5 (7)

37	Kenya	Article 5(7)
38	Korea	Article 5 (7)
39	Kuwait	Article 5 (8)
40	Kyrgyz Republic	Article 5 (8)
41	Latvia	Article 5 (6)
42	Libya	Article 4(5)
43	Lithuania	Article 5 (6)
44	Luxembourg	Article 5 (7)
45	Macedonia	Article 5(7)
46	Malaysia	Article 5 (7)
47	Malta	Article 5(7)
48	Mauritius	Article 5(5)
49	Mexico	Article 5 (7)
50	Mongolia	Article 5 (5)
51	Montenegro	Article 5(7)
52	Morocco	Article 5(7)
53	Mozambique	Article 5(7)
54	Myanmar	Article 5 (7)
55	Namibia	Article 5(6)
56	Nepal	Article 5 (7)
57	Netherlands	Article 5(6)
58	New Zealand	Article 5(5)
59	Norway	Article 5(7)
60	Oman	Article 5 (5)
61	Philippines	Article 5 (6)
62	Poland	Article 5(5)
63	Portuguese Republic	Article 5(6)
64	Qatar	Article 5 (8)
65	Romania	Article 5(6)
66	Russia	Article 5(5)
67	Saudi Arabia	Article 5 (7)
68	Serbia	Article 5(7)
69	Singapore	Article 5 (9)
70	Slovak Republic	Article 5(5)
71	Slovenia	Article 5(7)
72	South Africa	Article 5(6)
73	Spain	Article 5(5)

74	Sri Lanka	Article 5 (7)
75	Sudan	Article 5(7)
76	Sweden	Article5(8)
77	Swiss Confederation	Article5(6)
78	Syria	Article 5 (7)
79	Tajikistan	Article 5 (6)
80	Tanzania	Article 5(7)
81	Thailand	Article 5 (7)
82	Trinidad & Tobago	Article 5 (6)
83	Turkey	Article5(5)
84	Turkmenistan	Article 5 (7)
85	Uganda	Article 5(6)
86	Ukraine	Article5(6)
87	United Arab Emirates	Article 5 (5)
88	United Kingdom	Article5(5)
89	Uruguay	Article 5 (7)
90	USA	Article 5 (5)
91	Uzbekistan	Article 5 (5)
92	Vietnam	Article 5 (5)
93	Zambia	Article 5(6)

Article 13 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention, India hereby chooses to apply Option [A] under Article 13(1).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention, India considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Albania	Article 5(4)
2	Armenia	Article 5(4)
3	Australia	Article 5(4)
4	Austria	Article 5(4)
5	Bangladesh	Article 5(3)
6	Belarus	Article 5(3)
7	Belgium	Article 5(3)
8	Bhutan	Article 5(4)

9	Botswana	Article 5(4)
10	Brazil	Article 5 (3)
11	Bulgaria	Article 5(3)
12	Canada	Article 5(3)
13	Colombia	Article 5(4)
14	Croatia	Article 5(5)
15	Cyprus	Article 5(4)
16	Czech Republic	Article 5(4)
17	Denmark	Article 5(3)
18	Egypt	Article 5(3)
19	Estonia	Article 5(4)
20	Ethiopia	Article 5(4)
21	Fiji	Article 5(4)
22	Finland	Article 5(4)
23	France	Article 5(4)
24	Georgia	Article 5(4)
25	Germany	Article 5(4)
26	Greece	Article II (1)(h)(cc)
27	Hong Kong	Article 5(4)
28	Hungary	Article 5(4)
29	Iceland	Article 5(4)
30	Indonesia	Article 5(4)
31	Ireland	Article 5(5)
32	Israel	Article 5(4)
33	Italy	Article 5(3)
34	Japan	Article 5(6)
35	Jordan	Article 5(5)
36	Kazakstan	Article 5(4)
37	Kenya	Article 5(4)
38	Korea	Article 5(4)
39	Kuwait	Article 5(5)
40	Kyrgyz Republic	Article 5(5)
41	Latvia	Article 5(4)
42	Libya	Article 4(3)
43	Lithuania	Article 5(4)
44	Luxembourg	Article 5(4)
45	Macedonia	Article 5(4)

46	Malaysia	Article 5(4)
47	Malta	Article 5(4)
48	Mauritius	Article 5(3)
49	Mexico	Article 5(4)
50	Mongolia	Article 5(3)
51	Montenegro	Article 5(4)
52	Morocco	Article 5(4)
53	Mozambique	Article 5(4)
54	Myanmar	Article 5(4)
55	Namibia	Article 5(4)
56	Nepal	Article 5(4)
57	Netherlands	Article 5(4)
58	New Zealand	Article 5(3)
59	Norway	Article 5(4)
60	Oman	Article 5(3)
61	Philippines	Article 5(3)
62	Poland	Article 5(3)
63	Portugal	Article 5(4)
64	Qatar	Article 5(5)
65	Romania	Article 5(4)
66	Russia	Article 5(3)
67	Saudi Arabia	Article 5(4)
68	Serbia	Article 5(4)
69	Singapore	Article 5(7)
70	Slovak Republic	Article 5(3)
71	Slovenia	Article 5(4)
72	South Africa	Article 5(4)
73	Spain	Article 5(3)
74	Sri Lanka	Article 5(4)
75	Sudan	Article 5(4)
76	Sweden	Article 5(5)
77	Swiss Confederation	Article 5(3)
78	Syria	Article 5(4)
79	Tajikistan	Article 5(4)
80	Tanzania	Article 5(4)
81	Thailand	Article 5(4)
82	Trinidad & Tobago	Article 5(3)

83	Turkey	Article 5(3)
84	Turkmenistan	Article 5(4)
85	Uganda	Article 5(3)
86	Ukraine	Article 5(4)
87	United Arab Emirates	Article 5(3)
88	United Kingdom	Article 5(3)
89	Uruguay	Article 5 (4)
90	USA	Article 5(3)
91	Uzbekistan	Article 5(3)
92	Vietnam	Article 5(3)
93	Zambia	Article 5(3)

Article 16 – Mutual Agreement Procedure

Reservation

Pursuant to Article 16(5)(a) of the Convention, India reserves the right for the first sentence of Article 16(1) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer's objection to be justified.

Reservation is applicable to all CTAs of India provided in pursuance to Article 2(1)(a)(ii)

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(i) of the Convention, India considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
7	Belgium	Article 25(1), Second Sentence
12	Canada	Article 25(1), Second Sentence
33	Italy	Article 26(1), Second Sentence
87	United Arab Emirates	Article 27(1), Second Sentence

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention, India considers that the following agreement(s) contain(s) a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Albania	Article 26(1), Second Sentence
2	Armenia	Article 25(1), Second Sentence
3	Australia	Article 25(1), Second Sentence
4	Austria	Article 25(1), Second Sentence
5	Bangladesh	Article 27(1), Second Sentence
6	Belarus	Article 26(1), Second Sentence
8	Bhutan	Article 24(1), Second Sentence
9	Botswana	Article 26(1), Second Sentence
10	Brazil	Article 25(1), Second Sentence
11	Bulgaria	Article 27(1), Second Sentence
13	Colombia	Article 25(1), Second Sentence
14	Croatia	Article 25(1), Second Sentence
15	Cyprus	Article 25(1), Second Sentence
16	Czech Republic	Article 26(1), Second Sentence
17	Denmark	Article 25(1), Second Sentence
19	Estonia	Article 25(1), Second Sentence
20	Ethiopia	Article 25(1), Second Sentence
21	Fiji	Article 25(1), Second Sentence
22	Finland	Article 24(1), Second Sentence
23	France	Article 27(1), Second Sentence
24	Georgia	Article 26(1), Second Sentence
25	Germany	Article 25(1), Second Sentence
27	Hong Kong	Article 25(1), Second Sentence
28	Hungary	Article 25(1), Second Sentence
29	Iceland	Article 26(1), Second Sentence
30	Indonesia	Article 26(1), Second Sentence
31	Ireland	Article 25(1), Second Sentence
32	Israel	Article 26(1), Second Sentence
34	Japan	Article 25(1), Second Sentence
35	Jordan	Article 25(1), Second Sentence
36	Kazakhstan	Article 26(1), Second Sentence
37	Kenya	Article 26(1), Second Sentence

38	Korea	Article 25(1), Second Sentence
39	Kuwait	Article 25(1), Second Sentence
40	Kyrgyz Republic	Article 25(1), Second Sentence
41	Latvia	Article 25(1), Second Sentence
43	Lithuania	Article 26(1), Second Sentence
44	Luxembourg	Article 26(1), Second Sentence
45	Macedonia	Article 25(1), second sentence
46	Malaysia	Article 25(1), Second Sentence
47	Malta	Article 25(1), second sentence
48	Mauritius	Article 25(1), Second Sentence
49	Mexico	Article 25(1), Second Sentence
50	Mongolia	Article 26(1), Second Sentence
51	Montenegro	Article 27(1), second sentence
52	Morocco	Article 25(1), Second Sentence
53	Mozambique	Article 25(1), Second Sentence
54	Myanmar	Article 25(1), Second Sentence
55	Namibia	Article 26(1), Second Sentence
56	Nepal	Article 25(1), Second Sentence
57	Netherlands	Article 25(1), second sentence
58	New Zealand	Article 25(1), Second Sentence
59	Norway	Article 26(1), second sentence
60	Oman	Article 26(1), Second Sentence
61	Philippines	Article 26(1), Second Sentence
62	Poland	Article 26(1), second sentence
63	Portugal	Article 25(1), second sentence
64	Qatar	Article 23(1), Second Sentence
65	Romania	Article 25(1), second sentence
66	Russia	Article 25(1), second sentence
67	Saudi Arabia	Article 24(1), Second Sentence
68	Serbia	Article 27(1), second sentence
69	Singapore	Article 27(1), Second Sentence
70	Slovak Republic	Article 25(1), second sentence
71	Slovenia	Article 25(1), second sentence
72	South Africa	Article 24(1), Second Sentence
73	Spain	Article 27(1), second sentence
74	Sri Lanka	Article 25(1), Second Sentence
75	Sudan	Article 25(1), Second Sentence

76	Sweden	Article 26(1), second sentence
77	Swiss Confederation	Article 25(1), second sentence
78	Syria	Article 25(1), Second Sentence
79	Tajikistan	Article 25(1), Second Sentence
80	Tanzania	Article 25(1), Second Sentence
81	Thailand	Article 25(1), Second Sentence
82	Trinidad and Tobago	Article 25(1), Second Sentence
83	Turkey	Article 25(2), Second Sentence
84	Turkmenistan	Article 26(1), Second Sentence
85	Uganda	Article 25(1), Second Sentence
86	Ukraine	Article 26(1), second sentence
89	Uruguay	Article 26(1), Second Sentence
90	USA	Article 27(1), Second Sentence
91	Uzbekistan	Article 27(1), Second Sentence
92	Vietnam	Article 27(1), Second Sentence
93	Zambia	Article 26(1), Second Sentence

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(c)(i) of the Convention, India considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(b)(i)

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction
26	Greece
49	Mexico

Pursuant to Article 16(6)(c)(ii) of the Convention, India considers that the following agreement(s) do(es) not contain a provision described in Article 16(4)(b)(ii)

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction
12	Canada
18	Egypt
26	Greece
33	Italy
42	Libya
49	Mexico
61	Philippines
77	Swiss Confederation
83	Turkey
88	United Kingdom

Pursuant to Article 16(6)(d)(i) of the Convention, India considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(i).

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction
3	Australia
26	Greece

Pursuant to Article 16(6)(d)(ii) of the Convention, India considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(c)(ii).

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction
3	Australia
7	Belgium
26	Greece
61	Philippines
86	Ukraine
88	United Kingdom

Article 17 – Corresponding Adjustments

Reservation

Pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention, India reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in Article 17(2). The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement Number	Other Contracting Jurisdiction	Provision
1	Albania	Article 9(2)
2	Armenia	Article 9(2)
4	Austria	Article 9(2)
8	Bhutan	Article 9(2)
9	Botswana	Article 9(2)
12	Canada	Article 9(2)
13	Colombia	Article 9 (2)
14	Croatia	Article 9(2)
15	Cyprus	Article 9(2)
17	Denmark	Article 10(2)
19	Estonia	Article 9(2)
20	Ethiopia	Article 9(2)
21	Fiji	Article 9(2)
22	Finland	Article 9(2)
24	Georgia	Article 9(2)
27	Hong Kong	Article 9(2)
28	Hungary	Article 9(2)

29	Iceland	Article 9(2)
30	Indonesia	Article 9(2)
31	Ireland	Article 9(2)
32	Israel	Article 9(2)
35	Jordan	Article 9(2)
36	Kazakstan	Article 9(2)
37	Kenya	Article 9(2)
38	Korea	Article 9(2)
39	Kuwait	Article 9(2)
40	Kyrgyz Republic	Article 9(2)
41	Latvia	Article 9(2)
44	Luxembourg	Article 9(2)
45	Macedonia	Article 9(2)
47	Malta	Article 9(2)
49	Mexico	Article 9(2)
51	Montenegro	Article 9(2)
52	Morocco	Article 9(2)
53	Mozambique	Article 9(2)
54	Myanmar	Article 9(2)
55	Namibia	Article 9(2)
56	Nepal	Article 9(2)
57	Netherlands	Article 9(2)
58	New Zealand	Article 9(2) and 9(3)
61	Philippines	Article 10(2)
62	Poland	Article 10(2)
63	Portugal	Article 9(2)
64	Qatar	Article 9(2)
65	Romania	Article 9(2)
67	Saudi Arabia	Article 9(2)
68	Serbia	Article 9(2)
69	Singapore	Article 9(2)
71	Slovenia	Article 9(2)
72	South Africa	Article 9(2)
74	Sri Lanka	Article 9(2)
75	Sudan	Article 9(2)
77	Swiss Confederation	Article 9(2)
78	Syria	Article 9(2)

79	Tajikistan	Article 9(2)
80	Tanzania	Article 9(2)
81	Thailand	Article 9(2)
82	Trinidad & Tobago	Article 9(2)
83	Turkey	Article 9(2)
84	Turkmenistan	Article 9(2)
85	Uganda	Article 9(2)
88	United Kingdom	Article 10(2)
89	Uruguay	Article 9 (2)
90	USA	Article 9(2)

Article 35 – Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(2) of the Convention, solely for the purpose of its own application of Article 35(1)(a) and (5)(a), India hereby chooses to substitute “taxable period” for “calendar year”.

India has not opted for Part VI of the Convention

[Notification No. 57/2019/F. No. 500/71/2015-FTD-I]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.